चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 14 फरवरी–20 फरवरी 2011 | मूल्य 5 रुपये

क्या यही ग्राम स्वराज है?

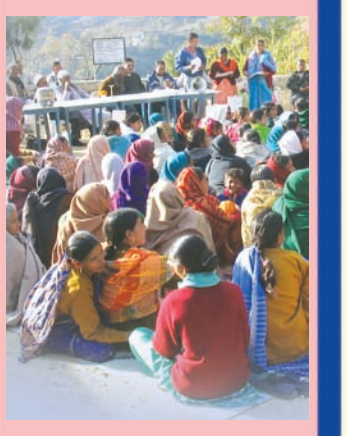

पेज-6

बर्बादी की यह योजना बंद करें

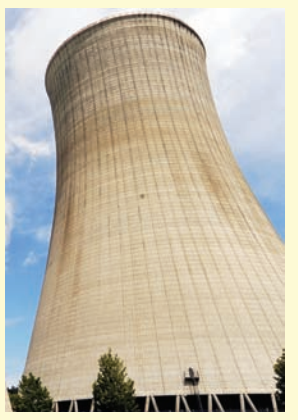

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

अधूरी तैयारी ने तोड़ दिया सपना

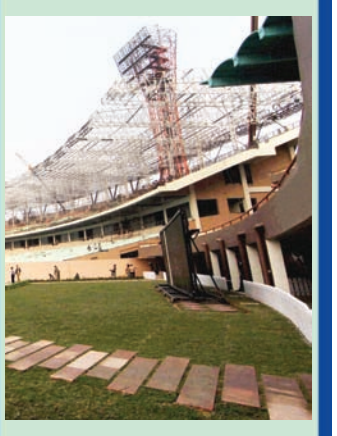

पेज-15

पश्चिम एशिया में क्रांति

लोकतंत्र के लिए मुसलमान

प्रजातंत्र की एक ख़ासियत है. इसकी लहर उठती है. एक-एक देश करके यह दुनिया में नहीं फैली है. आंदोलन या बदलाव की आंधी चली और कई देशों ने एक साथ प्रजातंत्र को अपनाया. प्रजातंत्र की पहली लहर ने पूरे यूरोप और अमेरिका में अपनी जगह बनाई. लोकतंत्र की दूसरी लहर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आई. जब भारत समेत कई देशों ने आज़ादी के बाद प्रजातंत्र को अपनाया. इसकी तीसरी लहर सोवियत ब्लॉक के टूटने के बाद आई, जब कई सोशलिस्ट स्टेट्स ने प्रजातंत्र को अपनाया. इस तरह दुनिया के हर हिस्से में लोकतंत्र ने अपनी पैठ बना ली थी, सिर्फ़ पश्चिम एशिया ही एक ऐसा इलाक़ा बच गया था, जहां प्रजातंत्र नहीं पहुंच सका था. ट्यूनीशिया के बाद मिस्र में आई आंधी प्रजातंत्र की चौथी लहर की शुरुआत है. इसका स्वागत होना चाहिए.

मनीष कुमार

जब भी किसी देश में लोग सड़कों पर बेरोज़गारी, महंगाई, ग़रीबी या किसी अन्य मांग को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ लामबंद होते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है. लेकिन जब कोई आंदोलन विद्रोह का रूप ले लेता है, जब किसी आंदोलन का मक़सद सत्ता परिवर्तन होता है तो उसे क्रांति कहते हैं. मिस्र में जो हो रहा है, वह महज़ कोई जनाक्रोश नहीं, कोई साधारण आंदोलन नहीं, बल्कि एक क्रांति है. एक ऐसी क्रांति, जो सिर्फ़ मिस्र तक सीमित रहने वाली नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनने वाली है.

ट्यूनीशिया के बाद मिस्र की घटनाओं से पश्चिम एशिया के देशों की तानाशाही की नींव हिल गई है. आंदोलन की आग ट्यूनीशिया से मिस्र और फिर अल्जीरिया, मौरिशेनिया, जॉर्डन, यमन और सऊदी अरब तक पहुंच चुकी है. समझने की बात यह है कि यह इलाक़ा पहले से ही दुनिया के लिए एक फ्लैश प्वाइंट बना हुआ है. फिलिस्तीन–इजराइल, इराक और अफगानिस्तान में अस्थिरता और अमेरिकी सेना की मौजूदगी, लेबनान का संकट और न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर ईरान पर हमले की आशंका के बीच ये आंदोलन हो रहे हैं. ये आंदोलन किसी पार्टी या किसी नेता या किसी विचारधारा की वजह से नहीं शुरू हुए हैं. जंगल की आग की तरह ये आंदोलन शुरू हुए हैं. इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा असरदार हैं. ऐसे आंदोलनों को नियंत्रित कर पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है. समझने वाली बात यह है कि मिस्र का आंदोलन किन्हीं आकस्मिक कारणों से नहीं हुआ है. लोग परेशान थे और जब उन्होंने देखा कि ट्यूनीशिया में किस तरह जनता ने आंदोलन किया, उससे उनकी हिम्मत बढ़ी और आंदोलन शुरू हो गया. एक बार लोग सड़क पर उतरे, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए. एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, जो अरब वर्ल्ड के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया.

मिस्र में जनता की नाराज़गी की चार प्रमुख वजहें हैं. पहली वजह आर्थिक है. मिस्र में बेरोज़गारी है, महंगाई है. पूरी अर्थव्यवस्था एकाधिकार में फंसी हुई है. सरकार ने पूंजीपतियों को खुला छोड़ दिया है ग़रीब और मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए और ऐसे पूंजीपतियों ने लोगों का ख़ून चूस लिया है. दूसरी वजह है प्रशासनिक संवेदनहीनता. यहां के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला है.

तीसरी वजह सामाजिक है. मिस्र का युवा वर्ग विमुख हो गया है और शिक्षा प्रणाली बेकार हो गई है. मिस्र का एजूकेशन सिस्टम भी लचर है. जिस तरह की पढ़ाई होती है, वह नई पीढ़ी की आशाओं पर खरी नहीं उतरती. युवा पीछे छूटते जा रहे हैं. मिस्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत और भी ख़राब है. जनता के पास पीने का साफ़ पानी तक नहीं है. जो पानी मिलता है, वह पीने लायक नहीं है. वह दूषित है, लेकिन लोगों को वही पानी पीना पड़ता है. मिस्र के किसानों की हालत सबसे ख़राब है. वहां किसानों का जीना हराम हो गया है. उनके लिए कोई योजना नहीं है. चौथी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है राजनीतिक. राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ दल समय के साथ–साथ तानाशाह होते चले गए हैं. भ्रष्टाचार करने वालों पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है. उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती है. वे क़ानून का मखौल उड़ाकर साफ़–साफ़ बच निकलते हैं. जनता इस अत्याचारी व्यवस्था से मुक्ति चाहती है. हाल में हुए चुनावों में जो धांधली की गई, उससे जनता का गुस्सा उबल पड़ा है. मिस्र की जनता अब अपने फ़ैसले ख़ुद लेना चाहती है. मिस्र के लोग अब प्रजातंत्र चाहते हैं, सरकार चलाने में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण ख़ुद कर सकें और देश के संसाधनों को देश की जनता के लिए इस्तेमाल कर सकें. इसलिए मिस्र के क्रांतिकारी देश में प्रजातंत्र लागू करने की मांग कर रहे हैं.

पश्चिम एशिया से जो तस्वीरें आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं. जिन देशों में लड़के–लड़कियों का हाथ पकड़ कर चलना जुर्म है, वहां आज वे कंधे से कंधा मिलाकर और हाथ में हाथ पकड़ कर सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. दरअसल, इस आंदोलन ने पश्चिमी एशिया के समाज के बारे में कई भ्रांतियों को ख़त्म किया है. ख़ुद को प्रजातंत्र का रखवाला समझने वाले अमेरिका और यूरोप के देशों ने अरबी समाज की ऐसी तस्वीर खींची कि दुनिया को लगता था कि पूरा अरब धार्मिक कट्टरवाद के दलदल में फंसा है. अरबी समाज की सोच ही मध्यकालीन है. वह आधुनिकता और विज्ञान के ख़िलाफ़ है. अमेरिका और यूरोप के देशों ने अरब के तानाशाहों से हाथ मिलाकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रखा था. यह किसी को भनक तक नहीं थी कि मुसलमान प्रजातंत्र के लिए ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ सकते हैं.

अरब देशों में मिस्र सबसे बड़ा है. इसकी आबादी 80 मिलियन है यानी 8 करोड़. यह एशिया और अफ्रीका के बीच का देश है, इसलिए सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से इसका महत्व दूसरे अरब देशों से कहीं ज़्यादा है. 1952 से 1970 के बीच जनरल गमाल अब्देल नासिर के शासनकाल में मिस्र पूरे अरब वर्ल्ड पर हावी था. उनके बाद अनवर सदात और होस्नी मुबारक सत्ता में आए, जिन्होंने मिस्र के वर्चस्व को बरक़रार रखने के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन इससे कुछ अरब देशों में मिस्र का प्रभुत्व तो कम हुआ, लेकिन अपने इतिहास और सामरिक कारणों से यह अरब देशों के दिलोदिमाग से उतर नहीं सका. यही वजह है कि तानाशाही का जो रूप मिस्र में है, वह अरब के दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बन गया. मिस्र के तानाशाह होस्नी मुबारक के जाते ही अरब देशों के तानाशाह भी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेंगे. वैसे भी पश्चिमी एशिया में यह कहा ही जाता है कि मिस्र में जो भी होता है, वह सारे अरब देशों में फैल जाता है. यह बात फिर से सही साबित हो रही है. जिस तरह मिस्र में लोग सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, वैसा ही कुछ अरब के दूसरे देशों में शुरू हो गया है. प्रजातंत्र का यह आंदोलन पूरे पश्चिम एशिया में भड़क उठा है. कहीं यह आग दिख रही है और कहीं यह आग आने वाले दिनों में दिखने वाली है. अरब देशों में शुरू से ही तानाशाह शासकों–राजाओं और राजकुमारों की सत्ता रही है. इस निरंकुशता के ख़िलाफ़ जब भी किसी ने आवाज़ उठाई, उसे बेदर्दी से दबा दिया गया. इसीलिए पश्चिम एशिया में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दो भावी प्रधानमंत्री

शिवधर रेड्डी, पी एस रणपीसे और डी के पांडे को इस बात के लिए भेजा है कि वे इस बात की जांच करें कि वहां के अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चुनावी दबाव

चुनाव आयोग के अधिकारियों के लगातार पश्चिमी बंगाल के दौरों से न सिर्फ़ सत्ताधारी वामपंथी दल, बल्कि राज्य सरकार के बाबू भी परेशान हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों जकी अहमद और पीआरके नायडू ने बंगाल के ज़िला स्तर के बाबुओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे संभावित लोगों की पहचान करें, जो चुनाव के वक़्त अशांति फैला सकते हैं और अवैध हथियार ज़ब्त करें. ज़िला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को चुनाव के समय शांति बनाए रखने की पूरी ज़िम्मेदारी दे दी गई है. चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों शिवधर रेड्डी, पी एस रणपीसे और डी के पांडे को इस बात के लिए भेजा है कि वे इस बात की जांच करें कि वहां के अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं. ज़ाहिर है, ऐसे हालात बाबुओं के लिए सुविधाजनक तो नहीं हो सकते हैं.

रेलवे के बाबुओं की मुश्किलें

कुछ सालों तक लाभ कमाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय रेलवे को असलियत का एहसास हो गया है. 22 सौ करोड़ रुपये के घाटे के बाद अब रेलवे बोर्ड ने अपने ख़र्चों में कटौती करने की योजना बनाई है. बोर्ड के अध्यक्ष विवेक सहाय ने बाबुओं को निर्देश दिया है कि वे ख़र्च में कटौती करें और आमदनी बढ़ाने के उपाय खोजें. इस बीच, सूत्रों का मानना है कि रेलवे 39500 करोड़ रुपये की सहायता मांग सकता है. हालांकि वित्त मंत्रालय ने अड़ंगा डाला तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन रेलवे के बाबुओं के लिए ऐसी स्थिति बन रही है कि उन्हें बहुत ही ज़रूरी यात्रा करने, ओवरटाइम–यात्रा भत्ता रोकने और ठेकेदारों के भुगतान की गति धीमी करने का आदेश दिया जा रहा है. दिलचस्प रूप से ईस्टर्न जोन को इस दायरे में शामिल नहीं किया गया है. शायद इसलिए, क्योंकि यह ममता बनर्जी के गृहराज्य में भी आता है.

राजनयिकों पर राव ने कसा शिकंजा

विदेश में दो वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले में फंसने के बाद विदेश मंत्रालय इस कोशिश में है कि भविष्य में ऐसी शर्मिंदगी फिर न उठानी पड़े. ये मामले बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे. विदेश सचिव निरुपमा राव ने विदेशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वे अपने स्टाफ द्वारा अपनी ग़लती छुपाने के लिए किए जाने वाले कृत्यों को बिल्कुल बर्दाश्त न करें. सूत्रों के मुताबिक़, राव ने अपने पत्र में कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक कड़ा संदेश दिया है. मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा निर्देशों के मुताबिक़, ऐसे किसी भी राजनयिक को, जो विवादास्पद मामलों में फंसता है, तत्काल वापस बुला लिया जाएगा. साथ ही उसे मंत्रालय की ओर से होने वाली जांच का सामना भी करना पड़ेगा, ताकि यह फ़ैसला किया जा सके कि वह दोषी है या नहीं.

dilipcherian@gmail.com

लोकतंत्र के लिए मुसलमान

पृष्ठ 1 का शेष

एक कहावत बन गई है कि शासक वर्ग एक पहाड़ की तरह है और उसका विरोध करना अपने सिर को पहाड़ में मारने जैसा है. लेकिन ट्यूनीशिया और मिस्र में जो हो रहा है, उससे यह कहावत झूठी साबित हो रही है. ट्यूनीशिया और मिस्र में जो हुआ, वह सभी अरब देशों के लिए सबक है. अगला नंबर उन्हीं का है. ये देश हैं अल्जीरिया, जॉर्डन, लीबिया, सीरिया, यमन और मोरक्को. मिस्र की तरह ही सऊदी अरब में भी राजाओं का राज चलता है. सऊदी अरब की जनता भी सरकार के ज़ुल्म को चुपचाप सहती है, अपना मुंह खोलने से डरती है. पूरा पश्चिमी एशिया ही इस तरह की हुकूमतों के हाथ में है. सत्ता में जनता की हिस्सेदारी नहीं है, सरकार की नीतियों में जनता का कोई दखल नहीं है. कुछ देशों में धर्म की आड़ में निरंकुश सत्ता है तो कुछ देशों में आज भी सत्ता पर जन्म सिद्ध अधिकार मानकर डायनेस्टी रूल चल रहा है. अरब देशों के संगठन अरब लीग के बाइस सदस्य हैं. इनमें से एक भी देश पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं है. इन देशों की जनता ग़रीब है, सरकार की नीतियां स्थिर और संतुलित नहीं है. लोकतंत्र के सबसे क़रीब है लेबनान, लेकिन यह भी आतंरिक समस्याओं से जूझ रहा है. इन देशों के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. फिलिस्तीन में पाक–साफ़ चुनाव हुए थे, लेकिन जीतने वाली हमास पार्टी को सत्ता पर क़ाबिज़ नहीं होने दिया गया. मोरक्को और कुवैत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में आज भी राजा का फ़रमान ही क़ानून है. सीरिया में भी लगभग यही स्थिति है. ज़्यादातर देशों में पुराने राजाओं ने नए राजवंशों को जगह दे दी है.

मिस्र में जिस तरह लोगों ने हिम्मत दिखाई है, वह अरब के दूसरे देशों के लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करेगी और पूरे इलाके में प्रजातंत्र के लिए आंदोलन हो सकते हैं. ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया का मध्यम वर्ग, कामकाजी वर्ग और बुद्धिजीवी हक़ीक़त का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं. पश्चिम एशिया के लोगों को लगता है कि उनकी सरकार न तो उनकी परेशानियां ख़त्म कर सकती है, न ही उनके भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है. आज का दौर इंटरनेट और टेलीविजन का दौर है. पश्चिम एशिया के पढ़े–लिखे मध्य वर्ग को यह पता है कि बाक़ी दुनिया किस तरह आगे जा रही है और वे किस तरह वक़्त की इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं. पश्चिम एशिया के मध्य वर्ग ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ ली है. यही वजह है कि फेसबुक से शुरू हुआ यह आंदोलन विश्व स्तर पर अपना महत्व दर्ज करा रहा है.

यह आंदोलन पश्चिम एशिया के सुल्तानों के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला है. इसकी वजह साफ़ है. जो हालात मिस्र में हैं, वही हालात पश्चिमी एशिया के हर देश में हैं. यह दुनिया का वह इलाक़ा है, जहां प्रजातंत्र की हवा तक पहुंचने से रोका गया है. वजह साफ़ है. पश्चिमी देशों और ख़ासकर अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए यहां के शासक वर्ग को अपने पक्ष में कर रखा है, ताकि वह बिना रोक–टोक यहां के खनिज ख़ासकर पेट्रोलियम को अपने देश में आयात कर सके. पश्चिमी एशिया की ज़्यादातर सरकारें अमेरिका की पिछलग्गू हैं. यहां के लोग सरकार के कामकाज से, तानाशाही से तंग आ चुके हैं और अब प्रजातंत्र की खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं. यह इतिहास के दरवाज़े पर एक दस्तक है. ट्यूनीशिया और मिस्र में जिस तरह आंदोलन हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इतिहास ने रुख मोड़ा है. प्रजातंत्र की हवा अब पश्चिम एशिया में बहने वाली है. मिस्र की क्रांति सिर्फ़ मिस्र तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह प्रजातंत्र की चौथी लहर शुरू होने का संकेत दे रही है. ट्यूनीशिया और मिस्र का आंदोलन पश्चिम एशिया में क्रांति की शुरुआत है. अब इसे रोकने की ताक़त दुनिया की किसी भी सरकार में नहीं है. पूरा पश्चिम एशिया इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक प्रजातंत्र की ओर, दूसरा गृहयुद्ध की तरफ़. यह पश्चिम एशिया के तानाशाहों को तय करना है कि वे अपने देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं. अगर उनमें देशप्रेम होगा तो वे प्रजातंत्र के लिए रास्ते बनाएंगे, सत्ता में आम जनता को हिस्सेदारी देंगे या फिर अपने देश के लोगों से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत करेंगे, जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

manish@chauthiduniya.com

कश्मीर शांति पर सियासत

स्मिता शुक्ला

कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित में आपसी स्तर पर कभी कोई मतभेद नहीं रहा. मतभेद सिर्फ़ सियासत की देन है, भाई को भाई से सिर्फ़ सियासत ने लड़वाया है और किसी ने नहीं. स्वर्ग कही जाने वाली धरती अब सिर्फ़ ख़ून से लाल दिखाई देती है, बच्चों और रोती–बिलखती माताओं की आवाज़ें सुनाई देना अब कश्मीर में आम बात हो गई है. आज के बच्चे, जो भविष्य के कर्णधार हैं, वे सिर्फ़ सियासी दांव–पेंच का शिकार बनकर रह गए हैं. क्या ऐसे राज्य की कल्पना हमारी केंद्र सरकार करती है? क्या ऐसे नौजवान आने वाले कल में देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे? इन सवालों के जवाब आख़िर कौन देगा? उक्त गंभीर सवाल सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस नामक संगठन द्वारा बुलाई गई एक सभा में उभर कर सामने आए. मुद्दा था, कश्मीर में शांति और अमन की बहाली कैसे हो.

सीपीआई के वरिष्ठ नेता ए बी वर्धन ने कहा कि अगर कश्मीरी पाकिस्तान जाने की मंशा रखते तो वे ऐसा बहुत पहले ही कर चुके होते, लेकिन कश्मीरी अवाम की यह मंशा कतई नहीं है. कश्मीरियों को तो बस चैन–ओ–अमन चाहिए. कश्मीरियों की मायूस आंखें कहती हैं कि कुछ और नहीं, तो कम से कम हमें चैन से जीने का संपूर्ण अधिकार तो दिया जाए. घाटी में अफसपा सेना की बर्बरता का एक जीता–जागता उदाहरण है. अफसपा की वजह से सेना किसी भी तरह की मनमानी कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है. केंद्र को चाहिए कि वह अफसपा क़ानून को जल्द से जल्द हटाए. सीपीआई (एम) के महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि हमने कश्मीरी अवाम से खुलकर बातचीत की और वहां के लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश की. हमने हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं से भी बात की. हमने पाया कि कश्मीर की समस्याओं का हल बंदूक़ की नोक पर नहीं, बल्कि एक उचित और शांत संवाद द्वारा ही मिलेगा. हम कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए भरसक प्रयास करने को तैयार हैं, पर हमें इसमें केंद्र और जम्मू–कश्मीर सरकार की मदद की दरकार है.

लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आक्रोश भरे स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू–मुस्लिम में फ़र्क़ करना जानती है. देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद उसने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाए. जम्मू–कश्मीर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए गठित कमेटी में मुख्य रूप से रामविलास पासवान (लोजपा), प्रकाश करात (सीपीआई–एम), ए बी वर्धन एवं डी राजा (भाकपा), डॉ. कमल मित्रा चिनॉय (जेएनयू), शाहिद सिद्दीकी (रालोद), नागेश्वर राव (तेदेपा), दानिश अली (जेडीएस), पत्रकार सीमा मुस्तफा एवं फिल्म निर्माता महेश भट्ट जैसे लोग शामिल हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वी पी हाउस प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम का संचालन पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस पी शुक्ल ने किया.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय को आफ़ताब-ए-सहाफ़त अवार्ड

फ़रमान चौधरी

ऑल इंडिया तंज़ीम उलेमा–ए–हक़ द्वारा आयोजित आतंकवाद और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय एकता अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में किया गया, जिसमें उर्दू के पहले अंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक चौथी दुनिया अख़बार के प्रधान संपादक संतोष भारतीय को उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आफ़ताब–ए–सहाफ़त अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीज़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात में सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हम सबको राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए हरसंभव कोशिश करनी चाहिए.

अधिवेशन में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि वह उर्दू न जानते हुए भी उर्दू की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू गंगा–जमुनी तहज़ीब की ज़ुबान है, उर्दू ने देश को आज़ादी दिलाई, उर्दू ने ख्वाब को ताबीर दी, उर्दू ने देश को एक लड़ी में पिरो दिया और उर्दू ने राष्ट्रीय एकता का विकास किया. उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा कि हम सबको मिलजुल कर राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए काम करना चाहिए.

इस अवसर पर त्रैमासिक हुस्न–ए–तदबीर के विशेष अंक मदारिस नंबर और मासिक नारा–ए–तकबीर के ईरान के हवाले से विशेष अंक का विमोचन भी हुआ. राष्ट्रीय एकता अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने वाले अहम लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन, जमीअतुल कुरैश दिल्ली के अध्यक्ष साजिद अतीक़, मौलाना रोशन आलम मज़ाहिरी, मीर हसन अल्वी, इशितयाक़ हुसैन रफ़ीक़ी, ख़ालिद अनवर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन मज़ाहिरी, डॉ. काशिफ़ ज़काई, क़ारी शम्सुद्दीन, मोहम्मद अज़ीज़ बक़ाई, मोहम्मद रियाज़ुद्दीन, मौलाना मुईनुल हक क़ासमी, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी और मोहम्मद शारिक़ उर्फ़ आशू ख़ां आदि के नाम उल्लेखनीय हैं. अधिवेशन का संचालन मुफ़्ती अफ़रोज़ आलम क़ासमी ने किया, जबकि उद्घाटन क़ारी अबुल हसन आज़मी की तिलावते कुरआन–ए–पाक से हुआ.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 49
दिल्ली, 14 फरवरी –20 फरवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी–2,3,4 सेक्टर 11, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भ्रष्टाचार सरकार या कहें कि पूरी भारतीय व्यवस्था के लिए एक और गले की हड्डी साबित हो रहा है और इसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो अंजाम की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा.

संसद के समक्ष चुनौतियां

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज हर जगह सिर्फ़ तंत्र ही तंत्र का राज है और इस राज में लोक के लिए जगह घटती ही जा रही है. जनता की समस्याओं पर सरकार की चुप्पी देखकर यही एहसास होता है. अब चुनौती संसद के सामने है कि वह कैसे इन समस्याओं का समाधान निकालती है. भारत में मिस्र जैसे हालात न पैदा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि संसद के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए.

शशि शेखर

जनता महंगाई की मार से त्रस्त है. अशिक्षा और बेरोज़गारी ने जीवन दु:खद बना दिया है. ग़रीबी एक अभिशाप बनकर रह गई है. बच्चों के लिए शिक्षा तो एक सपना भर है, क्योंकि पेट भरने को भोजन ही नहीं है. जनता भूख से मर रही है तो कभी उग्रवादियों की गोलियों से और कभी-कभी तो अपना अधिकार मांगते हुए देश की पुलिस के हाथों ही जान से हाथ धो बैठती है. नव उदारवादी नीतियों ने ग़रीबों को और ग़रीब एवं अमीरों को और अमीर बना दिया है. ग़रीब आदिवासियों से उनका घर-बार, ज़मीन, परंपरागत जीवनशैली, उनकी पूरी दुनिया ही छीन ली जाती है और वह भी विकास के नाम पर. जंगलों को काटकर अवैध खनन चल रहा है. खेतिहरों से उनकी ज़मीन छीन ली जाती है, मुआवज़ा मांगने पर लाठियों-गोलियों की बरसात होने लगती है. ऐसे हालात में किसानों के पास आत्महत्या छोड़कर और कोई रास्ता नहीं बचता. सरकार के नाम पर ऐसे लोग सत्ता पर काबिज़ हैं, जो या तो ख़ुद लुटेरे हैं या लुटेरों के संरक्षक और पोषक. बेरोज़गारी का आलम यह है कि सरकार को मनरेगा जैसी योजना बनानी पड़ गई और यहां भी कहानी वही रही. मज़दूरों का पैसा अफसर और ठेकेदार खा गए. आज पढ़ने वालों के मन में पढ़ाई से ज़्यादा यह डर रहता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं. भारत में युवा शक्ति तो है, लेकिन सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसका फ़ायदा उठा सके. आख़िर जनता जाए तो किसके पास? गुहार लगाए तो किस दहलीज़ पर? मिस्र के ताजा हालात को देखते हुए इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं भारत की जनता भी अपनी समस्याओं से ऊब कर सड़क पर न आ जाए. बहरहाल, यहां कुछ ऐसी ही चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा रही है, जो संसद के समक्ष हैं. ये ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान संसद को ही निकालना है. इस देश और इसके नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग़रीबी. भारत की अर्थव्यवस्था की सफल कहानी सिर्फ़ देश के 20 फ़ीसदी लोगों के लिए ही है. बाक़ी बची 80 फ़ीसदी जनता के लिए इस सबके कोई मायने नहीं हैं. देश की इतनी बड़ी आबादी के जीवन की तुलना अफ्रीका के सबसे ग़रीब देशों से की जा सकती है. भारत की आधी ग़रीब जनता देश के सिर्फ़ सात राज्यों में रहती है यानी बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड. ये सबसे ग़रीब राज्य वही हैं, जहां जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ रही है. अब सवाल यह उठता है कि भारत में इस ग़रीबी के कारण क्या हैं. सबसे पहली बात यह है कि भारत में रोज़गार के साधन घटते जा रहे हैं. बेरोज़गारी में हम दुनिया के सबसे ग़रीब और छोटे देशों को भी टक्कर दे रहे हैं. एक आंकड़े के मुताबिक़, भारत में बेरोज़गारी की दर वर्ष 2009 में 10.70 फ़ीसदी थी. इस हिसाब से हम दुनिया के सारे देशों की सूची में 122वें स्थान पर हैं. रोज़गार न होने के कई मतलब होते हैं. जनता रोज़गार के अभाव में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं कर पाती. इस कारण देश का सकल घरेलू उत्पाद भी कम हो जाता है और ग़रीबी और भी बढ़ जाती है. बेरोज़गारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का हाल भी कुछ ठीक नहीं है.

दिल्ली की एक संस्था नॉलेज अवेयरनेस रिसर्च एंड मैनेजमेंट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव, मध्य प्रदेश के दमोह, कर्नाटक के कोलार और बंगलुरू के देहाती क्षेत्रों में मनरेगा के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया. इस रिपोर्ट से पता चला कि बड़े-बड़े वादों और दावों के बाद भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कर्नाटक के कोलार एवं बंगलुरू देहात जैसे स्थानों पर क्रमश: 13 और 10-10 फ़ीसदी परिवार ही मनरेगा के तहत पंजीकृत है. एक गांव के 160 परिवारों में से महज़ 13 फ़ीसदी यानी 20 परिवार ही नरेगा के तहत पंजीकृत थे और साल में महज़ 32 दिनों का काम इन लोगों को मिल पाता है. मनरेगा के तहत यह नया प्रावधान किया गया है कि किसी गांव में अगर एक काम होता है तो दोबारा फिर वही काम नहीं होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि एक गांव में कितने तालाब खोदे जाएंगे या कितनी सड़कें बनेंगी. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में लोगों के पास काम की कमी होना तय है. मनरेगा के तहत दी जाने वाली मज़दूरी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं. ऐसी स्थिति में संसद को यह सोचना पड़ेगा कि मनरेगा में व्याप्त धांधली को कैसे ख़त्म किया जाए और इसे आम आदमी के लिए एक फ़ायदेमंद योजना में बदला जा सके. ग़रीबी और बेरोज़गारी की एक और महत्वपूर्ण वजह है, जल, जंगल और ज़मीन से आम आदमी को बेदखल करने की साजिश. ये प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं, जो ग्रामीण भारत के लोगों के जीने का एक आधार हैं. इसमें देश के करोड़ों किसान, आदिवासी एवं मज़दूर शामिल हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि उदारीकरण की नीति की वजह से जल, जंगल और ज़मीन पर भी पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि पड़ गई. इस सबका परिणाम यह हुआ कि कभी खनन तो कभी कॉरपोरेट खेती के नाम पर जंगल और ज़मीन पर उनका क़ब्ज़ा होता

गया. भारी-भरकम और बेवजह की सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों की ज़मीनों के अधिग्रहण से आदिवासियों और किसानों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा. 2007 में सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि और प्राकृतिक संसाधन ही हैं. समिति ने केंद्र सरकार के क़ानून यानी वन अधिकार क़ानून (फारेस्ट राइट एक्ट) को कारगर ढंग से लागू करने की भी सलाह दी. समिति ने अपनी सिफ़ारिश में कहा कि आदिम जनजाति समुदायों के भूमि क़ब्ज़े को मान्यता दे दी जाए, लेकिन आज भी लाखों आदिवासियों को जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है. ज़ाहिर है, इन शोषित और पीड़ित लोगों को उनका अधिकार दिलाना आज संसद के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसके बाद, जब ग़रीबी और बेरोज़गारी से त्रस्त जनता ख़रीदारी करने बाज़ार पहुंचती है, तब उसका सामना महंगाई नामक दैत्य से होता है. पिछले एक साल में महंगाई ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए. खाने की चीजों के दाम में लगभग 20 फ़ीसदी तक की बढ़ोत्तरी हुई. फल, सब्जी, दूध एवं अनाज सब महंगे. आम आदमी की जेब नहीं, गर्दन काटने की पूरी तैयारी कालाबाज़ारियों और जमाखोरों ने कर ली. सरकार इसे लेकर चिंतित दिखी ज़रूर, लेकिन कोई ठोस क़दम उठाती नज़र नहीं आई. अब सवाल यह है कि आख़िर बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में लाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर इस चुनौती से भी संसद को ही निपटना है. बहरहाल, इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की थाली से खाना तो ग़ायब किया ही, ज़रा उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए, जिनकी रोज की आमदनी 20 रुपये से भी कम है. आख़िर उनकी भूख कैसे मिटती होगी. उनके हिस्से की थाली का हाल एक रिपोर्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2009 के आंकड़ों के मुताबिक़, विश्व में भूखे और कुपोषित लोगों के सूचकांक में भारत 65वें नंबर पर है. यानी भारत में भूखे, कुपोषित लोगों की संख्या पाकिस्तान, नेपाल, सूडान, पेरू, मालावी और मंगोलिया जैसे देशों से भी ज़्यादा है. 23.9 फ़ीसदी भूखी और कुपोषित जनता के साथ भारत चौरासी देशों की इस ग्लोबल हंगर सूची में 65वें स्थान पर हैं. नाइजीरिया जैसे देश के मुक़ाबले भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी ज़्यादा ज़रूर है, फिर भी भारत में नाइजीरिया के मुक़ाबले ज़्यादा भूखे और कुपोषित लोग हैं. कुछ और भी सवाल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उपरोक्त समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार माने जा सकते हैं और संसद के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं. मसलन, इस देश की लगभग एक चौथाई आबादी यानी अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अंदाज़ा सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट से ही लग जाता है. शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरी तक में उसका प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के मुक़ाबले बहुत कम है. मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का हाल अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे दयनीय है. बावजूद इसके, राजनीतिक दलों ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझाया ही है. चुनावी राजनीति के चक्कर में उन्हें बस वोट बैंक की नज़र से ही देखा गया. रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान से पैरा 3 (अनुसूचित जाति आदेश 1950) को हटाने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों और ईसाइयों को दलित का दर्जा देने की अनुशंसा की, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शिक्षा और नौकरियों में भी आरक्षण देने की बात कही. एक साल हो गए, जब यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई तो सरकार के लिए यही अनुशंसाएं गले की हड्डी बन गईं.

भ्रष्टाचार सरकार या कहें कि पूरी भारतीय व्यवस्था के लिए एक और गले की हड्डी साबित हो रहा है और इसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो अंजाम की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा. सबसे दु:खद तो यह कि इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का जो हश्र हो रहा है, उस पर भी संसद में एक तरह की ख़ामोशी ही देखने को मिल रही है. सत्येंद्र दूबे, मंजूनाथ से लेकर जेठवा तक एक लंबी सूची. जब एक साल के भीतर दर्जन भर आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, तब सरकार ने एक क़ानून बनाने की बात कही, व्हिसल ब्लोअर बिल 2010. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां मिलेंगी, लेकिन सिर्फ़ अधिकार मिलने से क्या होगा? लोकायुक्त जैसा पद पहले ही बेमानी हो चुका है, जिसके पास पर्याप्त अधिकार हैं. दूसरी ओर जीप से लेकर 2-जी घोटाले तक के सफर के बाद सरकार ने लोकपाल बिल का झुनझुना थमाने की कोशिश की है. प्रस्तावित लोकपाल को ख़ुद कोई कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं दिया गया है. बहुत संभव है कि प्रस्तावित लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था का हाल भी सीबीआई और सीवीसी जैसा हो जाए. तब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनयुद्ध के अलावा क्या कोई चारा बचेगा? अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली समेत देश के पचपन शहरों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आम आदमी सड़क पर आए. इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक एक अभियान के तहत सड़क पर उतरे ये लोग अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीक़े से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन यह शांति अशांति में बदले, इससे पहले संसद को उक्त तमाम चुनौतियों पर ध्यान देना होगा, साथ ही इनका समाधान भी निकालना होगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार

एक सुरक्षित और आपदा के प्रति समुत्थानशील भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध

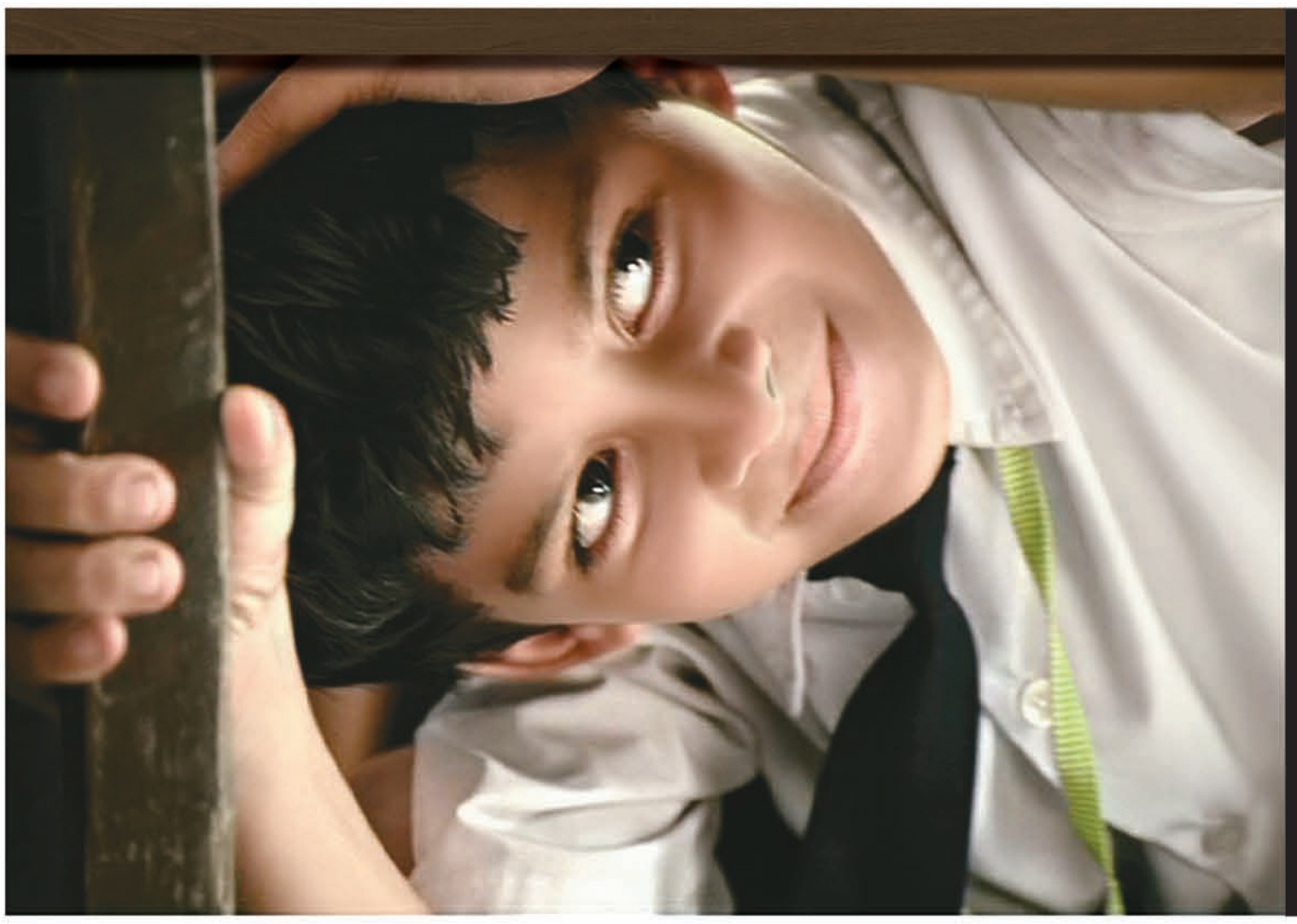

भूकंप के दौरान... झुको! ढको! पकड़ो!!

याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें

- खुले स्थान में जाएं।
- यदि बाहर न निकल सकें, तो झुक जाएं और किसी मेज के नीचे शरण लें।
- अपने सिर को सुरक्षा हेतु किसी मज़बूत चीज़ के नीचे छिपा लें।
- दौड़ कर एक कोने में खड़े हों और अपने सिर को बचाएं।

भूकंप के दौरान

- घबराएं नहीं, शांत रहें।
- भूकंप के झटके रूकने की प्रतीक्षा करें।
- खिड़की, दर्पण, किताबों की अलमारी तथा अन्य बिना बंधी हुई भारी वस्तुओं से दूर हो जाएं।
- खुले स्थान में जाने के लिए लिफ्ट की बजाए सीढ़ियों का प्रयोग करें।

भूकंप के बाद

- पहले झटके के बाद आने वाले अगले झटकों के लिए सचेत रहें।
- घायल और फंसे हुए व्यक्तियों की मदद करें।
- याद रखें कि बच्चों, बूढ़ों और विकलांग लोगों को विशेष मदद की ज़रूरत होती है, उनकी मदद करें।
- टूटी–फूटी इमारतों के बाहर हो जाएं।

जोखिम से बचने के लिए–अपने घर/इमारत को मज़बूत बनाएं–तकनीकी सलाह प्राप्त करें।

सरकारी रवैय्या भी बहुत नकारात्मक रहा इस पूरे मामले में. सरकार ने आज तक कोई ऐसा नियम-क़ानून नहीं बनाया, जिसकेआधार पर पानी के दोहन की सीमा तय की जा सके.

आगरा
जल संकट और सरकारी भ्रष्टाचार

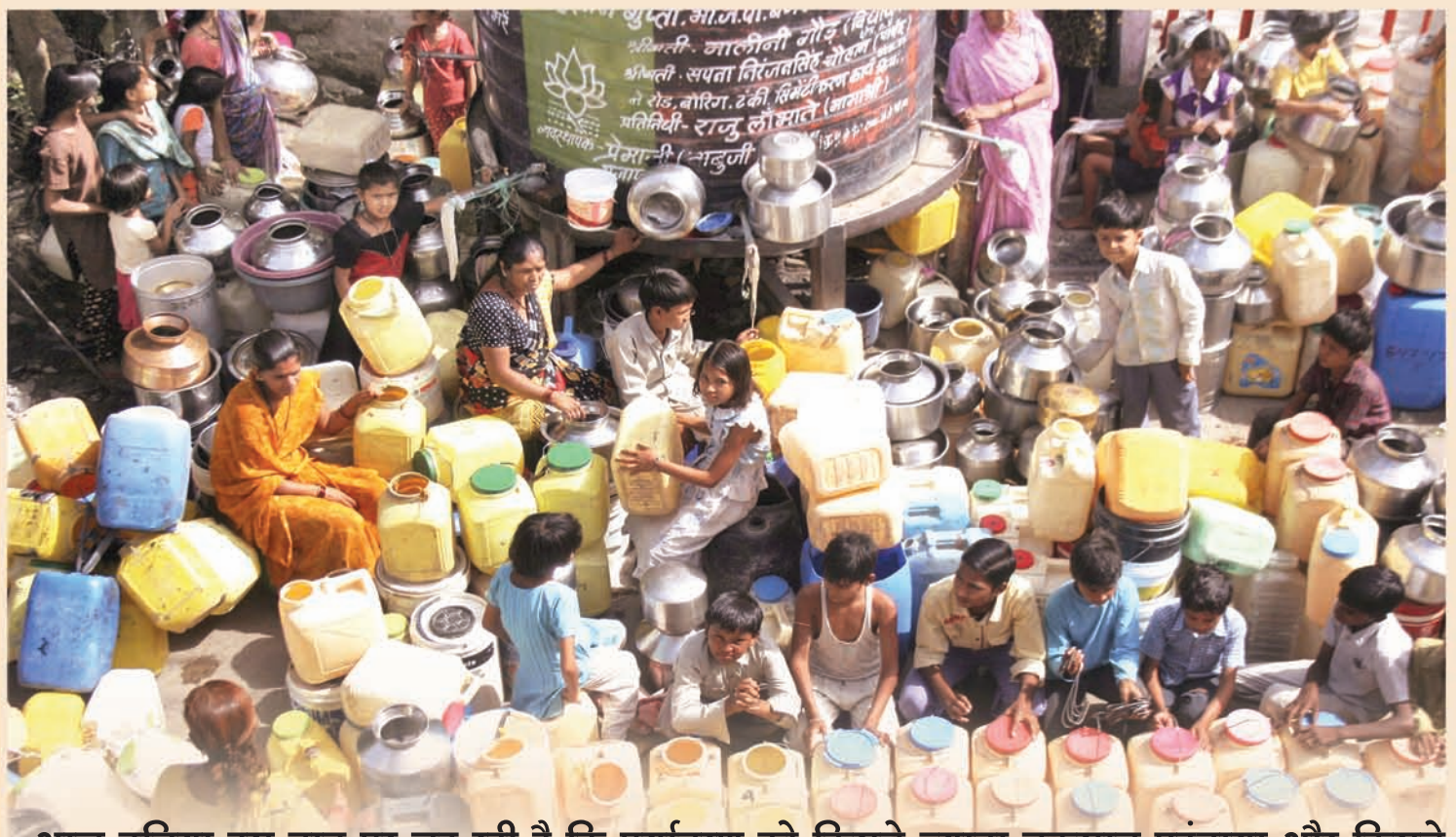

आज दुनिया इस बात पर लड़ रही है कि पर्यावरण को किसने ज़्यादा नुक़सान पहुंचाया और किसने प्रकृति का अधिक दोहन किया है. बड़ी-बड़ी कांफ्रेंस होती हैं, बड़े-बड़े देशों के पर्यावरणविद् एवं मंत्री भाषण देते हैं, पर्यावरण और धरती की अमूल्य धरोहरों को बचाने की कसमें खाते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के वही तीन पात. उसी पुराने ढर्रे पर ही जीवन चलता रहता है, दोहन होता रहता है, चाहे पानी का हो या तेल का. पानी कितना अमूल्य है, यह कोई बताने की बात नहीं है. बिन पानी न तो मानव रह सकता है और न ही पशु और वनस्पति जगत, लेकिन सरकार ने इस बहुत बड़ी सच्चाई से मानो मुंह मोड़ रखा है.

सिद्धार्थ राय

पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज जल संकट की ज़बरदस्त मार झेल रहा है. यहां आज पीने और कृषि दोनों के लिए पानी की कमी है. जब पीने को पानी नहीं रहेगा और न ही कृषि के लिए, तो जनजीवन का क्या होगा? आज इसी सवाल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता दो-दो हाथ कर रही है. लेकिन ये स्थितियां अचानक नहीं खड़ी हो गई हैं. इसके अनेक कारण रहे हैं. जनता भी उतनी ही दोषी है, जितनी आज और कल की सरकारें. पानी का अंधाधुंध दोहन होता रहा है. किसानों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसे उन्मुक्त दोहन से क्या हो सकता है? वैसे इसमें किसानों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं था. सरकार ने सिर्फ़ इस बात पर ध्यान दिया कि किसानों का मुंह कैसे बंद रखा जाए. कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर तो कभी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर. कभी यह नहीं सोचा गया कि आख़िर जब पानी रहेगा, तभी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. आज जो पानी की कमी की बात की जा रही है, वह कोई नई नहीं है. पहले भी सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठन इस समस्या की तरफ़ उंगलियां उठाते रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं. लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग सिर्फ़ गड्ढे खोदने में लगे रहे और ग़लत पंप और हैंडपंप बनाते रहे. आगरा मंडल के तहत जो ज़िले आते हैं, वे हैं आगरा, मथुरा, हाथरस एवं फिरोज़ाबाद. पहले अलीगढ़ भी इसी मंडल के अंतर्गत था. अलीगढ़ की बात यहां इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि वहां भी यही समस्या है. याद रखने की बात है कि यह पूरा इलाक़ा गहन कृषि क्षेत्र है. यहां पानी का अधिकाधिक प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है. पूरे क्षेत्र की संपन्नता और रोज़गार कृषि पर ही आधारित है. इस कारण यहां पर पानी की कमी किसी भी शहरीकृत क्षेत्र से अधिक चिंतित करने वाली है.

आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इस पूरे क्षेत्र में पानी साठ से सत्तर मीटर गहराई में पाया जाता है. यह पानी भी कोई बहुत मीठा या पीने के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है. सिर्फ़ यह है कि इस पानी से किसी तरह काम चल सकता है. मतलब यह है कि पानी खारा तो है, लेकिन बाक़ी जगहों से कम. बात यह है कि पीने या खेती करने के लिए पानी एक स्तर तक ही खारा हो सकता है. अगर बहुत खारा पानी है तो वह न पीने के काम आ सकता है और न खेती के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खारा पानी सिंचाई के काम में ले लिया जाए तो ज़मीन यानी खेत के ऊसर हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है. इस स्तर का पानी पशुओं को भी पिलाने के काम नहीं आ सकता. ऐसा नहीं है कि इस पानी को खेती के लिए उपयोग करने के बारे में सोचा नहीं गया. लेकिन एक और समस्या है कि यह पानी तेलिया है. मतलब इसमें तेल है. तेल होने की वजह से यह पानी खेत की मिट्टी में समाता ही नहीं, ऊपर ही रह जाता है. जिस स्तर तक पानी है, मतलब साठ से सत्तर मीटर तक, ज़ाहिर है कि इसी स्तर तक के पानी का दोहन किया जा सकता है. यही किया भी गया है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह रहा कि पानी का स्तर और नीचे गिर गया है. मतलब यह कि अब लोग उस स्तर की अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, जहां से खारा पानी शुरू होता है और यह पानी किसी काम का नहीं है. दरअसल आगरा जनपद और आसपास के इलाक़ों की स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी. 1980 में यहां का जलस्तर सामान्य था. 1996 में जलस्तर घटकर 34 मीटर चला गया. अगले दस सालों में यह जलस्तर भयावह रूप से 42 मीटर चला गया और 2010 आते-आते 45 मीटर तक. पूरे क्षेत्र में 1280 सरकारी और 68000 ग़ैर सरकारी ट्यूबवेलों से अंधाधुंध पानी की निकासी की जा रही है. फिरोज़ाबाद में भी यही स्थिति है. मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में भी 2-4 मीटर का ही अंतर है.

समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो जाती. जैसा कहा गया है कि पानी का स्ट्राटा (वह आख़िरी सीमा, जहां तक ठीक पानी मिलता है) 60-70 मीटर है और स्तर 40-45 मीटर है. यह जलस्तर लगातार दोहन की वजह से गिरता जा रहा है. हर साल एक से डेढ़ मीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसा अनुमान है कि अगर जलस्तर इसी मानक से गिरता रहा तो दस-पंद्रह साल में सारा मीठा पानी ख़त्म हो जाएगा. यदि यह पानी ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि आगे का पानी तो बस नाम का पानी है, जिसका प्रयोग मुमकिन नहीं है. मतलब यह है कि सारी खेती ख़त्म हो जाएगी, सारे पशु या तो मर जाएंगे या भाग जाएंगे. जहां तक लोगों की बात है, उन्हें भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा. आज का आगरा, जो ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, रेगिस्तान बनकर रह जाएगा और पर्यटक ऊंची क़ीमतों पर पानी ख़रीद कर पिएंगे. जैसा कि चिली के कई शहरों के साथ हुआ, इस क्षेत्र के भी कई शहर सुनसान हो जाएंगे.

इन सारी समस्याओं का एक और पहलू है. बात करनी होगी मथुरा और आगरा की दक्षिणी सीमा के पास के स्थानों की, जो चंबल से लगे हुए हैं और राजस्थान की ओर पड़ते हैं. समूचे चंबल घाटी क्षेत्र में गड्ढों की भरमार है. आख़िर ये गड्ढे कैसे बन गए? हुआ यह कि यहां भी जलस्तर बहुत तेज़ी से गिरता चला गया. इस कारण ज़मीन से पानी बहुत नीचे चला गया. मतलब यह कि मिट्टी ऊसर हो गई और फिर यह बंजर मिट्टी रेत में बदल गई. जब यहां बारिश होती है तो यह सारी रेतीली मिट्टी तेजी से बहकर चंबल में चली जाती है. ज़ाहिर है कि राजस्थान का मरुस्थल इस ओर बढ़ रहा है. गर्मियों में राजस्थान की रेत तेज़ हवाओं के साथ उड़कर आने से दिल्ली तक मरुस्थलीकरण का ख़तरा पैदा हो गया है. ऐसे में इस क्षेत्र के लिए मरुस्थलीकरण का पैमाना क्या होगा, यही सोचने वाली बात है. अगर आगरा और आसपास की जगहों पर पानी का स्तर इसी तरह तेज़ी से गिरता गया तो इनका भी मरुस्थलीकरण होने से रोकना असंभव होगा.

इस विषय में सरकारी महकमों और सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया. जब बात आती है सरकारी भूमिका की, तो पानी मुहैय्या कराना अफसरों और मंत्रियों के लिए पैसा बनाने का साधन बन जाता है. पानी एक बड़ा गोरखधंधा बन गया है. ऐसा ही यहां भी हुआ है. सरकार नलकूप और हैंडपंप लगाने की बहुत सारी योजनाएं लाती रहीं, लेकिन वे अपनी अनुमानित अवधि से पहले ही बेकार हो जाते हैं या सूख जाते हैं. मतलब पानी नहीं देते. अब ऐसा होता क्यों है? क्या सरकार की ओर से पर्याप्त पैसा नहीं आता ऐसी योजनाओं के लिए? ऐसा नहीं है. क्या अफसर सारा पैसा खा जाते हैं? क्या हैंडपंप बनाते समय नियमावली का ध्यान नहीं रखा जाता? सच बात तो यह है कि नलकूप और हैंडपंप बनाने का ठेका सरकार स्थानीय ठेकेदारों को दे देती है. ठेकेदार सारे नियम-क़ानून ताक पर रखकर कम पैसा लगाते हैं, रद्दी सामान का प्रयोग करते हैं और जिस गहराई तक बोरिंग होनी चाहिए, उतनी नहीं करते. सरकारी अफसर उनसे मिले हुए हैं. ऐसे ठेकेदारों से सामान का लेनदेन होता है, जो रिश्वत देते हों. सरकारी अफसर ऐसा सिर्फ़ अपने लिए नहीं करते, उन्हें आगे भी पैसा पहुंचाना पड़ता है. 2009-10 में आगरा जनपद में लगाए गए हैंडपंप बेकार हो गए, सूख गए. जांच बैठी तो पाया गया कि हैंडपंप लगाते समय नियमों का पालन नहीं किया गया था. जितनी बोरिंग होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई और भुगतान पूरा ले लिया गया. दरअसल हैंडपंप लगाना बच्चों का खेल नहीं है. पहले तो अगर 2.5 इंच का डिस्चार्ज चाहिए तो 4-6 इंच का बोर होना चाहिए. फिर उसे मोटी रोड़ी से भरा जाता है, ताकि नीचे बोरे में पाइप पर मिट्टी न गिर पड़े. ऐसा इसलिए, क्योंकि पानी के स्रोत पर पाइप छेद वाला होता है और रोड़ी न भरी जाए तो छेद मिट्टी से भर जाते हैं और पानी आना बंद हो जाता है. ठेकेदार और सरकारी अफसर इन सारे चरणों पर पैसा बचाने की जुगत में रहते हैं, इसलिए हैंडपंप सूख जाते हैं. आगरा जनपद में भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था. बोरिंग होनी थी 60 मीटर, लेकिन हुई 40 मीटर. गर्मी आते ही पानी का स्तर नीचे चला गया और हैंडपंप सूख गए. ठेकेदारों ने हर पंप पर मीटर पाइप और बोरिंग आदि का पैसा बचाकर अपनी जेब में डाल लिया. जांच अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि नियमावली का पालन न करने और तकनीकी कमी के कारण पंप सूख गए थे. कई जगह ऐसा भी देखा गया कि जहां सरकारी महकमों यानी जल निगम, यू पी एग्रो और नलकूप निगम को बोरिंग करनी चाहिए थी, वहां किसानों को ख़ुद ही बोरिंग करानी पड़ी अपना पैसा लगाकर.

सरकारी रवैय्या भी बहुत नकारात्मक रहा इस पूरे मामले में. सरकार ने आज तक कोई ऐसा नियम-क़ानून नहीं बनाया, जिसके आधार पर पानी के दोहन की सीमा तय की जा सके. बात बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आज तक इस मामले में सरकार ने कोई विधेयक पेश नहीं किया. ऊपर से यमुना एक्सप्रेस-वे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना बनाते समय भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जल संकट के कारण भविष्य में पूरी परियोजना पर ताला लग सकता है. एक्सप्रेस-वे से लगा हुआ एशिया का सबसे बड़ा शहर बसाने की योजना भी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो शहर बसा कर क्या होगा? इसी एक्सप्रेस-वे के मामले में किसानों ने आंदोलन छेड़ा. मीडिया से लेकर सरकार तक ने इसे हर्जाने और किसानों की क्षतिपूर्ति का मामला बताया, लेकिन इस बात पर किसी की नज़र नहीं गई कि किसान सिर्फ अपने खेतों की सही क़ीमत ही नहीं मांग रहे थे, उनकी एक बड़ी मांग यह भी थी कि उन्हें खेती के लिए पानी की किल्लत हो रही है और सरकार उन्हें पानी मुहैय्या कराए.

हर साल फतेहपुर सीकरी और आसपास के कई इलाक़ों में पानी के लिए क़त्ल-बलवा होता है. जल संकट की वजह से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और जीवनदायक पानी जीवन ले रहा है. सरकार की एक और योजना है गंगा का पानी इस पूरे इलाक़े में लेकर आना. आज तक उस योजना पर कोई कार्य नहीं हुआ. यह योजना 1200 करोड़ रुपये की है, लेकिन आम जनता का मानना है कि इससे कोई भला नहीं होने वाला. यमुना का पानी इतना दूषित है कि वह पीने या खेती करने लायक़ नहीं बचा है. दिल्ली से आते हुए यमुना में बड़े पैमाने पर गंदगी का डिस्चार्ज हो जाता है, इसीलिए यह स्थिति पैदा हो गई है. यही पानी कुछ तरीक़ों से फ़िल्टर करके जनता को पिलाया जाता है, जो कई बीमारियों को जन्म देता है. समाज का अमीर वर्ग तो पानी ख़रीद कर पी रहा है, लेकिन ग़रीब आदमी पानी जैसी मूलभूत ज़रूरत पर कहां से पैसा ख़र्च करे. इसी कारण उसे यही गंदा और खारा पानी पीकर काम चलाना पड़ता है.

सोचने वाली बात है कि जब यह समस्या आज की नहीं है, नई नहीं है तो फिर सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? अगर बात यह है कि परियोजनाएं बनी और पैसा आवंटित हुआ तो वह पैसा कहां गया? जब यह समस्या बढ़ रही थी, तब कोई सुधार और शोध क्यों नहीं हुआ? बात यह है कि पानी का अन्वेषण और पानी मुहैय्या कराना मंत्रियों और अफसरों के लिए पैसा बनाने की तकनीक बन गया है. पानी बेचने वालों का धंधा चल निकला है. आज तक या तो अन्वेषण-शोध हुआ ही नहीं, हुआ तो रिपोर्ट को अनदेखा कर दबा दिया गया. क्यों? सरकार के एजेंडे पर यह सबसे पहला काम होना चाहिए था.

feedback@chauthiduniya.com

शराब घर-घर पहुंचती जा रही है और लोगों को खेती-किसानी से जो भी पैसा मिलता है, वे उसे शराब में बर्बाद कर देते हैं.

क्या यही ग्राम स्वराज है?

विनीता यशस्वी

मैं घूमने के लिए कई बार यहां-वहां जाती रहती हूं. कभी बड़े शहरों में तो कभी छोटे शहरों में और कई बार उत्तराखंड के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भी. वैसे तो गांवों में भी अब बदलाव आने लगे हैं, पर कहने में संकोच नहीं होता कि ज़्यादातर बदलावों का परिणाम उल्टा ही हुआ है. गांवों में घूमते हुए जो सबसे बड़ी समस्या महसूस होती है, वह यह है कि गांवों में रोज़गार के अवसरों का नितांत अभाव है, इस वजह से युवाओं का शहरों की तरफ़ पलायन बढ़ने लगा है. गांवों में औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग ही रह जाते हैं. मनरेगा जैसी योजना भी इस पलायन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है. खेती भी दिनोंदिन कठिन और महंगी होती जा रही है.

गांवों में चकबंदी न होने के कारण किसानों की जोत की ज़मीन दूर-दूर होती है, जिससे उनकी मेहनत दोगुनी हो जाती है और यदि मौसम ने भी उनका साथ नहीं दिया तो वह मेहनत भी किसी काम नहीं आती है. यदि फ़सल हो भी जाए तो उसे मंडी तक पहुंचाना एक कठिन काम है. बिचौलिए अपना पैसा पहले ही अपनी जेब में डाल लेते हैं. सड़क के नज़दीक स्थित गांवों के लिए तो फिर भी यह थोड़ा आसान है, पर जो गांव आज भी सड़कों से बहुत दूर हैं, वहां के किसानों को अपनी फ़सल मंडी तक ले जाने में न केवल काफी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादा पैसा भी ख़र्च करना पड़ता है. इसी वजह से लोग अब खेती के प्रति उदासीन होने लगे हैं. इस उदासीनता का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिल्डरों ने उठाया है. अब वे इन जगहों पर घुसपैठ करने लगे हैं. खेती के प्रति उदासीन लोगों को भी अपनी ज़मीन बेच देना सरल लगता है और उन्हें मेहनत से भी छुटकारा मिल जाता है. इसी सोच के चलते वे अपनी ज़मीनों को औने-पौने दामों में बिल्डरों को बेच रहे हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो किसान पहले अपनी ज़मीन का मालिक था, वह बाद में अपनी ही ज़मीन में बिल्डर का चौकीदार बनकर रह जाता है.

एक बार एक गांव में घूमते-घूमते जब मैं एक स्कूल की ओर पहुंची तो पता चला कि वहां स्कूल तो है, पर अध्यापक नहीं हैं और जो हैं भी, उनका ध्यान पढ़ाने में कम, अपना ट्रांसफर शहरों की तरफ़ कराने में ज़्यादा लगा रहता है. कई बार तो कुछ अध्यापक अपनी जगह किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं और महीने के अंत में अपनी तनख्वाह से 2-3 हज़ार रुपये उसे देकर बाक़ी अपनी जेब में डाल लेते हैं. एक बच्चे ने बताया कि उसके स्कूल में विज्ञान विषय तो है, पर उसे पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है. यदि कभी कोई शिक्षक आ भी जाता है तो प्रयोगशाला नहीं है. इसलिए न चाहते हुए भी दूसरे विषय लेने पड़ते हैं. जो बच्चे शहर जाकर पढ़ाई का ख़र्च उठा सकते हैं, वे तो चले जाते हैं, पर जो नहीं जा पाते, उन्हें वहीं यानी गांव में रहकर ही पढ़ना पड़ता है. जब वे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं तो बाक़ी बच्चों से बिछुड़ जाते हैं. जब वे किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते. एक बच्चे ने यह भी बताया कि कभी-कभी कुछ शिक्षक उनसे शराब, बीड़ी और सिगरेट जैसी चीजें भी मंगवाते हैं.

गांव में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए श्मशान घाट ज़्यादा नज़दीक होता है, अस्पताल नहीं. सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है, जब किसी गर्भवती महिला की तबियत ख़राब हो जाती है. जहां अस्पताल हैं भी, वहां कंपाउंडर ही डॉक्टर का काम करते हैं. डॉक्टर पिछड़े क्षेत्रों में आना पसंद नहीं करते. इन सारी समस्याओं के बीच सुखद बात सिर्फ़ यह है कि गांवों में बच्चियों को लेकर माता-पिता का रवैया निराश करने वाला नहीं है. वे अपनी बच्चियों को पढ़ाने में विश्वास रखते हैं.

एक बार जब मैं अल्मोड़ा के गांव द्यूली में थी तो वहां के प्रधान ने बताया कि गांव की कुल जनसंख्या 450 है, जिसमें 300 मतदाता हैं. गांव में समस्याओं के सिवा कुछ है ही नहीं. नल तो हैं, पर पानी नहीं है. लाइनें हैं, पर बिजली नहीं है. 1985-86 में विद्युत कनेक्शन मिले और 10-12 साल तक बिजली आई भी, पर वोल्टेज इतना कम रहता था कि उसमें कोई काम नहीं हो सकता था और बिल 10-12 हज़ार रुपये तक आ जाता था. कई बार विभाग से शिक़ायत करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में बिजली ही कटवानी पड़ी. ग्राम प्रधान ने बताया कि विकास के नाम पर जहां पानी नहीं था, वहां सीमेंट की डिग्गी बना दी गई, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को सीमेंट-पत्थर डालकर सुखा दिया गया. भ्रष्टाचार इतना है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी के लोगों को फ़ायदा दिया जाता है. गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए तीन बार सर्वे किया गया, पर आज तक सड़क नहीं बनी. इन गांवों को आपस में जोड़ने वाले खड़ंजों की हालत बहुत ख़राब है. पंचायत भवन खस्ताहाल हो चुका है. यहां कोई मनोरंजन कक्ष नहीं है. स्वास्थ्य परिचारिका या आशा कार्यकर्ता जैसे लोग भी यहां नहीं आते. बीमार होने पर अल्मोड़ा या हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों की तरफ़ जाना पड़ता है.

द्यूली से ही थोड़ी दूर स्थित एक अन्य गांव के प्रधान ने एक नई कहानी सुनाई, जिसे सुनकर कान खड़े हो गए. उन्होंने बताया कि गांव में खड़ंजा बनाने के लिए 50 हज़ार रुपये स्वीकृत हुए. एक बीडीसी सदस्य ने उनसे मस्टररोल बनाने को कहा. जब उन्होंने काम के बग़ैर मस्टररोल बनाने से इंकार किया तो तर्क दिया गया कि सभी गांवों में ऐसा हो रहा है. अंततः उन्होंने मस्टररोल पर मज़दूरों के आड़े-तिरछे हस्ताक्षर बनवा कर और अंगूठा-निशान लगवा कर उन्हें दे दिया. काम शुरू होते ही सात हज़ार रुपये का चेक लेने उन्हें ब्लॉक बुलाया गया, पर बाबू ने ढाई हज़ार रुपये पहले ही ले लिए. काम ख़त्म होने पर 25 हज़ार रुपये और दिए गए. 50 हज़ार में से उन्हें सिर्फ़ 27 हज़ार रुपये ही मिले.

गांवों में सड़कें क्या पहुंचीं, शराब घर-घर पहुंचती जा रही है और लोग इस कदर आदी होते जा रहे हैं कि उन्हें खेती-किसानी से जो भी पैसा मिलता है, वे उसे शराब में बर्बाद कर देते हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर होती जा रही है. गांव की महिलाओं ने बताया कि पहले तो वे तोड़-फोड़ करके दुकानें हटवा देती थीं, उन्हें हटाने के लिए आंदोलन भी करती थीं, पर अब तो ठेकेदार गाड़ियों में घूम-घूमकर शराब बेचते हैं. गाड़ियां गांव-दर-गांव चक्कर लगाती रहती हैं. उन्हें तो हटाया भी नहीं जा सकता. महिलाएं कहती हैं कि आदमी शराब पीकर मारपीट और गाली-गलौच करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ता जा रहा है.

सबसे ज़्यादा ख़राब हालत अस्पतालों की है. कई गांवों में तो स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई चीज है ही नहीं. लोगों ने बताया कि गांव में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए श्मशान घाट ज़्यादा नज़दीक होता है, अस्पताल नहीं. सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है, जब किसी गर्भवती महिला की तबियत ख़राब हो जाती है. जहां अस्पताल हैं भी, वहां कंपाउंडर ही डॉक्टर का काम करते हैं. डॉक्टर पिछड़े क्षेत्रों में आना पसंद नहीं करते. इन सारी समस्याओं के बीच सुखद बात सिर्फ़ यह है कि गांवों में बच्चियों को लेकर माता-पिता का रवैया निराश करने वाला नहीं है. वे अपनी बच्चियों को पढ़ाने में विश्वास रखते हैं. कई जगह तो लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से कहीं ज़्यादा है और वे लड़कों से ज़्यादा अच्छे स्थान प्राप्त करती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

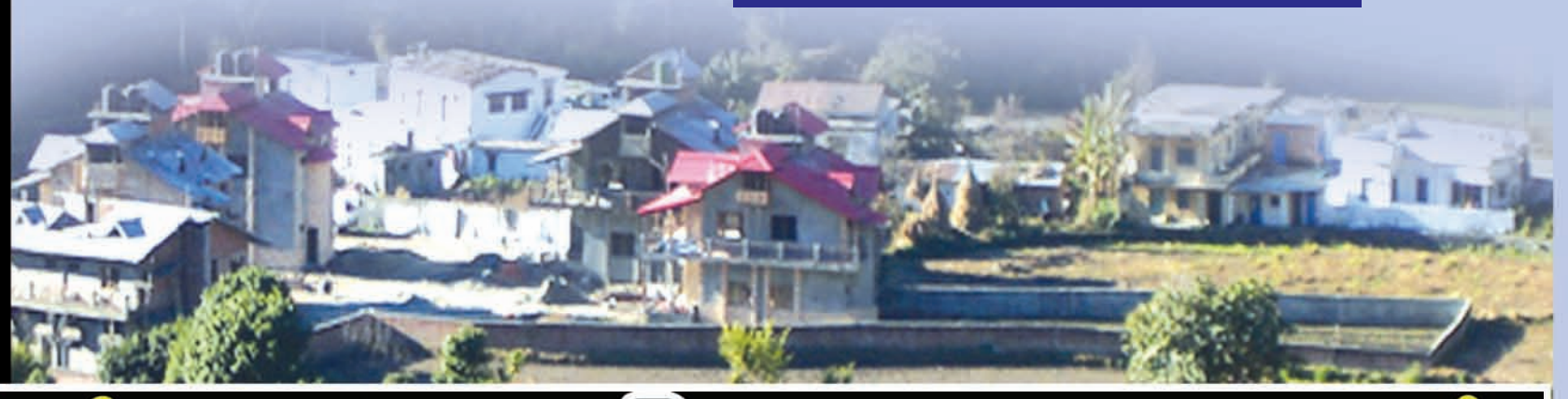

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आरटीआई के इस्तेमाल से मिली जानकारी के मुताबिक़, जैतापुर भूकंप जोन-4 में आता है, लेकिन ईआईए रिपोर्ट में इसे जोन-3 में दिखाया गया है.

जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट

बर्बादी की यह योजना बंद करें

सुलभा ब्रह्मे

भारत सरकार ने 2032 तक 63 हज़ार मेगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन का फ़ैसला लिया है. सरकार का मानना है कि यह क़दम ऊर्जा की भारी मांग की वजह से उठाया जा रहा है. इसी के तहत 2005 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के मदबन में दस हज़ार मेगावाट क्षमता के एक विशाल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. यह अपने आप में एक विशेष प्रोजेक्ट होगा. अभी तक दुनिया की किसी भी एक जगह पर इतनी क्षमता का एक ही प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किया गया है. अगले 15 से 18 सालों में इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है. पहले चरण में 3300 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए दो रिएक्टर लगाने की योजना है. आगे इसे 9900 मेगावाट में तब्दील कर दिया जाएगा. इसके लिए 938 हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल होगा, जिसमें से प्लांट के लिए 692 हेक्टेयर और आवासीय उपयोग के लिए बाकी ज़मीन का इस्तेमाल होगा. 2335 ज़मीन मालिकों एवं उनके परिवारों की जीविका और मज़दूरों की ज़िंदगी इस प्लांट के लिए दांव पर लगेगी. इस प्रोजेक्ट की वजह से मछुआरों की समस्या भी बढ़ने वाली है.

फ्रांस की कंपनी अरेवा यहां पर 6 रिएक्टर लगाने वाली है, प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी. अरेवा फ्रांस की सरकार नियंत्रित कंपनी है. अरेवा ने यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर (ईपीआर) तकनीक का विकास किया है. लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक एक भी ईपीआर का पूर्ण निर्माण नहीं हो सका है, जिसे ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके. अरेवा ने पहला ईपीआर फिनलैंड को बेचा, लेकिन अब तक इस रिएक्टर से उत्पादन कार्य शुरू नहीं हो सका है. इसकी डिजाइन की वजह से फिनलैंड का प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है. उल्टे प्रोजेक्ट की कीमत 50 फ़ीसदी और बढ़ चुकी है. फिनलैंड के रिएक्टर की कीमत 5.7 बिलियन यूरो है. चीनी रिएक्टर की कीमत 5 बिलियन यूरो है. इस हिसाब से जैतापुर के छह रिएक्टरों के लिए जनता के लगभग 1 लाख 93 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च हो जाएंगे. जबकि भाप चालित, कोयला आधारित पावर स्टेशन की कीमत प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपये आएगी.

बहरहाल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जैतापुर प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस पाने के लिए एनपीसीआईएल ने नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) को इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करने को कहा. एनईईआरआई ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तैयार किया और 16 मई, 2010 को एक जन सुनवाई भी की. हालांकि एनईईआरआई की रिपोर्ट की प्रति स्थानीय भाषा में गांव वालों के बीच बांटी गई थी, लेकिन सिर्फ़ एक गांव में, वह भी जन सुनवाई के सिर्फ़ 5 दिन पहले. इसके अलावा बाकी के 5 गांवों में रिपोर्ट की प्रतियां नहीं दी गईं. जन सुनवाई के वक़्त भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. एनईईआरआई की जांच रिपोर्ट भी अवैज्ञानिक है.

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आरटीआई के इस्तेमाल से मिली जानकारी के मुताबिक़, जैतापुर भूकंप जोन-4 में आता है, लेकिन ईआईए रिपोर्ट में इसे जोन-3 में दिखाया गया है. अब चाहे जोन 3 हो या जोन 4, दोनों ही हालत में इस क्षेत्र में भूकंप आने की अधिक आशंका है. 1995-2005 के बीच जैतापुर और इसके आसपास के इलाक़े में 60 भूकंपीय कंपन जीएसआई द्वारा दर्ज किए गए. यहां तक कि 2005 में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.1 थी और उसका केंद्र बिंदु जैतापुर में जहां प्लांट लगना है, लगभग वही था.

जैव विविधता पर भी इस प्लांट का ग़लत असर होगा. नेरी की रिपोर्ट के अनुसार, मदबन पठार एक ऊसर-बंजर जगह है, जहां पर कोई जैव विविधता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल, मदबन पठार की पहाड़ियों पर अर्ध सदाबहार जंगल है, आर्द्र भूमि है, अर्जुन नदी है और ऐसा दर्रा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के समुद्री जंतु रहते हैं. ये सारे मिलकर एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी कारण यह परियोजना कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत अवैध है. जैतापुर के 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट कुल 432 हेक्टेयर भूमि घेर लेंगे, जिससे जीव और वनस्पति दोनों का ही मदबन पठार से ख़ात्मा हो जाएगा.

रेडियो एक्टिव कचरे के निस्तारण को लेकर भी यह परियोजना आसपास के इलाक़ों और जनता के लिए हानिकारक है. न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन इंडिया लि. के अनुसार, कम और मध्यम स्तर के नाभिकीय कचरे को ज़मीन से ऊपर ही निस्तारित किया जाएगा. इसके विरुद्ध ईआईए कहता है कि निस्तारण ज़मीन की सतह के नीचे होना है. दरअसल, नाभिकीय कचरा, जो ज़मीन में दबा दिया जाता है, उसका तीन सौ वर्षों तक निरीक्षण करना होता है. लेकिन यह सब कैसे होना है, ईआईए की रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है. नाभिकीय ईंधन, जिसका इस्तेमाल हो चुका है, को भी दोबारा पुन: संशोधित करना है, लेकिन यह बात भी ईआईए रिपोर्ट में नहीं है. इस काम के लिए न तो कोई जगह तय की गई है और न किसी संसाधन की बात कही जा रही है.

फ्रांस की कंपनी अरेवा यहां पर 6 रिएक्टर लगाने वाली है, प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी. अरेवा फ्रांस की सरकार नियंत्रित कंपनी है. अरेवा ने यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर (ईपीआर) तकनीक का विकास किया है. लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक एक भी ईपीआर का पूर्ण निर्माण नहीं हो सका है, जिसे ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके.

सारी ग्राम पंचायतों ने इस नाभिकीय ऊर्जा पार्क के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है. यहां के लोग विगत पांच सालों से शांतिपूर्वक और प्रजातांत्रिक तरीक़े से विरोध कर रहे हैं. बावजूद इन सभी विरोधों और नाभिकीय प्लांट के विरुद्ध पाए गए सारे तथ्यों के, केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार और एनपीसीआईएल यह प्लांट लगाने पर अडिग हैं. राज्य सरकार ने ज़बरन भूमि का अधिग्रहण किया और विरोध करने वालों पर लाठियां चलवाईं. सरकार के सारे अत्याचारों के बाद भी यहां की जनता अपनी भूमि के बदले मुआवजा लेने को तैयार नहीं है. 16 अक्टूबर, 2010 को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने मुंबई में ऐलान किया कि एनपीसीआईएल और राज्य सरकार ने एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इस योजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय किसान इस परियोजना के विरोध में नहीं हैं. मंत्री के इस बयान पर जनता गुस्से में आ गई और उस अख़बार की सामूहिक होली जलाई गई, जिसमें मंत्री का उक्त बयान छपा था.

29 अक्टूबर, 2010 को स्थानीय जनता ने पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदेश को शांतिपूर्वक विरोध के सहारे तोड़ दिया और तीन हज़ार लोगों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी.

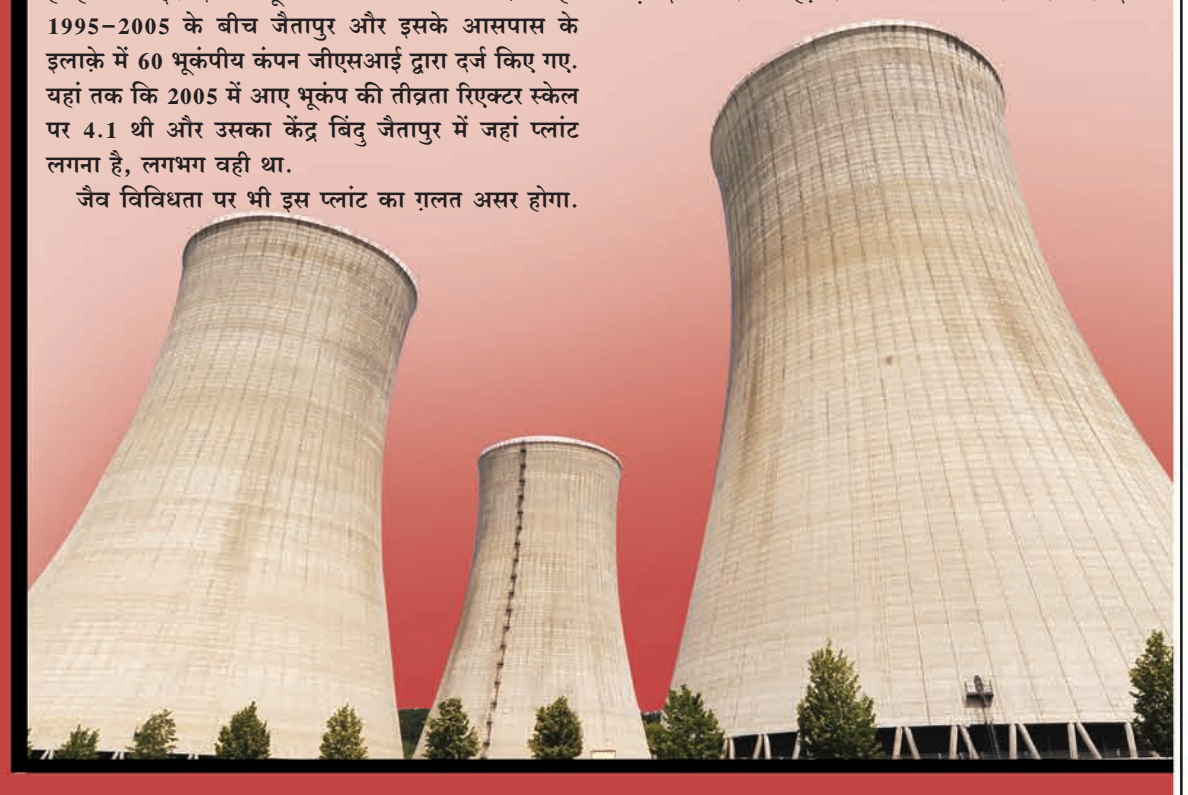

उनके अनुसार, जब वे अपने खेत नाभिकीय प्लांट के लिए देना ही नहीं चाहते तो मुआवजे का सवाल कहां उठता है. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 28 नवंबर, 2010 को जैतापुर प्लांट को हरी झंडी दे दी. इसके पीछे कारण कूटनीतिक और सामरिक बताए गए. इस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के साथ अनुबंध करने का रास्ता साफ़ हो गया. ऐसा तब किया गया, जब फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भारत यात्रा पर आए हुए थे. इसके विरोध में 5 हज़ार मछुआरों, खेतिहरों और गांव के अन्य लोगों ने मदबन में अरेवा वापस जाओ-सरकोजी वापस जाओ के नारे के साथ जेल भरो आंदोलन किया.

बीती 18 दिसंबर को एनपीसीआईएल की एक सूमो गाड़ी, जिसे पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे थे, की टक्कर एक स्कूटर से हुई, जिसमें स्कूटर सवार की मृत्यु हो गई. मृतक एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता का भांजा था. ध्यान देने की बात यह है कि उक्त सामाजिक कार्यकर्ता इस प्लांट का विरोध कर रहे थे. इससे पहले भी पुलिस द्वारा आपत्तिजनक ढंग से गाड़ी चलाना जनता को खटकता रहा है. पूरी स्थिति पर पुलिस ने जो असंवेदनशील रवैया अख्तियार किया, वह बहुत ही ग़ैर ज़िम्मेदाराना था. पुलिस ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के ख़िलाफ़ गंभीर धाराएं लगाईं जैसे दंगा फैलाना, घातक हथियारों का प्रयोग और यहां तक कि हत्या का प्रयास. निर्दोष लोगों को अग्रिम ज़मानत भी नहीं दी गई. दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अध्यापकों को निर्देश दिया कि वे स्कूली बच्चों को यह समझाएं कि यह नाभिकीय पावर प्लांट स्वच्छ और सुरक्षित है. इसके विरोध में बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार किया, जो सौ फ़ीसदी सफल रहा.

18 जनवरी, 2011 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें बार्क, एनपीसीआईएल, नाभिकीय ऊर्जा विभाग और स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया गया. यह आमंत्रण स्थानीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सरकार जानकारी साझा करने में ईमानदारी नहीं दिखा रही थी और यह लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन था. महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने खुलेआम उन लोगों को धमकी दी है, जो इस प्लांट के विरोध में हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोंकण का भला नहीं चाहते. जो लोग इस प्लांट के विरोध में हैं, वे अपने घरों को वापस नहीं पहुंच पाएंगे. सरकार ने जनता की जनतांत्रिक मांगों के विरुद्ध काम करने का मन बना लिया है. यहां तक कि सरकार लोगों के शांतिपूर्ण विरोध को भी बलपूर्वक दबाने के लिए तत्पर दिख रही है. भले ही राज्य तंत्र के पास अधिक मशीनें या अधिक बल हो, लेकिन जनता ने इस संघर्ष को अंतिम परिणाम तक ले जाने का मन बना लिया है.

(लेखिका कोंकण बचाओ समिति की चेयरमैन एवं पर्यावरणविद् हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

क्या है मांग?

1. जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को तत्काल बंद किया जाए.
2. ज़बरन अधिग्रहीत ज़मीन को लौटाया जाए.
3. कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस केस वापस लिए जाएं.
4. कोंकण में प्रस्तावित और मौजूद विकास परियोजनाओं के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाए.
5. कोंकण में चल रहे सभी ताप बिजली संयंत्रों, खनन कार्यों और रासायनिक उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए.
6. जनता को साथ में लेकर विकास के लिए अन्य दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं.

Lambda Group at a Glance

LETL

LAMBDA MICROWAVES PVT. LTD.

LAMBDA MICROWAVE TECHNOLOGIES

ARIALCOM

TEK 41 SOLUTIONS

LETL

LAMITEK SYSTEMS PVT. LTD.

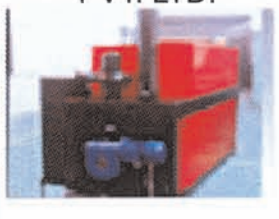

ARB BEARINGS

पीएफ घोटाले में फंसे जजों की जांच चल रही है और दिनाकरन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी जारी है.

श्रद्धा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु जब यही श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाए, तब क्या किया जाए?

चौथी दुनिया

मेघनाद देसाई

भारत को भारतीयों ने ज़्यादा लूटा

यह 19वीं शताब्दी की बात है. ब्रिटिश जमकर भारत को लूट रहे थे और सारा पैसा इंग्लैंड ले जा रहे थे. यानी भारत से धन की निकासी अपने चरम पर थी. तब कांग्रेस के पुरोधाओं के लिए ब्रिटिश शासन की आलोचना का यही मुख्य आधार रहा. दादाभाई नौरोजी ने पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में संपत्ति की इस लूट का हवाला देकर विदेशी शासन को कठघरे में खड़ा किया. उस समय के आकलन के अनुसार यह लूट भारत की राष्ट्रीय आय का 4 से 5 फ़ीसदी थी. लंदन भेजे गए इस धन से किसी भी तरह की लाभ की आशा भी नहीं थी. भारत के राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत अमीर हो सकता है, बशर्ते धन की यह लूट बंद हो जाए. ग्रेट डिप्रेशन के दौरान धन निकासी का यह सिलसिला धीरे-धीरे कम होने लगा और 1939 तक यह लगभग ख़त्म हो गया. बावजूद इसके भारतीय संपत्ति की उस लूट की कहानी अब भी राष्ट्र की स्मृति से ख़त्म नहीं हो पाई है.

भारतीय राजा-महाराजाओं ने भी भारत की संपत्ति को लूटा, लेकिन यह आंतरिक लूट थी, जिसे वे नौकर-चाकर, रॉल्स रॉयसेज और विदेशी प्रेमिकाओं पर उड़ाते थे. किसी ने भी इसका आकलन नहीं किया कि इन राजाओं ने आम आदमी का कितना पैसा लूटा. इस मसले पर एक राष्ट्रवादी विचार यह था कि वे भले ही डाकू थे, लेकिन अपने देश के ही यानी देशी थे. अब हम एक ग्लोबलाइज़्ड दुनिया में हैं और धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं. इसलिए अब लूट की मात्रा भी बड़ी होती जा रही है. आख़िरकार उन 26 लोगों ने, जिनके नाम हम जर्मनी के साथ एक संधि की वजह से कभी नहीं जान पाएंगे, लगभग 1.8 लाख करोड़ डॉलर छुपाकर दूसरे देशों में रखा हुआ है. चूंकि डॉलर अभी 45 रुपये के बराबर है, इसलिए यह लूट भी 2-जी से 45 गुना ज़्यादा है. 2-जी भी 1.8 लाख करोड़ का है, लेकिन यह रुपये में है. ज़ाहिर है, ये 26 खाते तो महज़ शुरुआत है. कौन जानता है कि स्विट्जरलैंड, केयमैन द्वीप, लिख़-टेन-श्टाइन, दुबई, पनामा एवं मॉरीशस में और कितने छुपे खाते हैं.

हम लोग कम से कम एक बात पर तो गर्व कर ही सकते हैं, हमें अपना धन लूटने और उसे विदेश में जमा करने के लिए अब किसी विदेशी का इंतज़ार नहीं करना है. हम इस काम को ख़ुद कर सकते हैं और कर रहे हैं. पुराने दिनों में, जब पूंजी पर नियंत्रण था, तब इस काले धन में से ज़्यादातर पैसे का इस्तेमाल फिल्म निर्माण, नशीले पदार्थ, अपराध और वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा था. इन पैसों का इस्तेमाल राजनेताओं को ख़रीदने में भी हुआ. यह पैसा रुका हुआ नहीं था, बल्कि इससे कमाई की जा रही थी. टैक्स की बचत हो रही थी सो अलग. आज भी काले धन से संचालित होने वाली एक बहुत बड़ी अर्थ व्यवस्था का अस्तित्व है. यह बात दिल्ली के किसी भी मॉल में दुकान चला रहे किसी दुकान मालिक से पूछकर जान सकते हैं. स्विट्जरलैंड में जमा धन से कमाई तो हो रही है, लेकिन इसे भारत में निवेश नहीं किया जा रहा है. उसे ज़रूर अपराधियों, नशीले पदार्थों के सौदागरों और ऐसी ही जगहों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा.

भारतीय राजा-महाराजाओं ने भी भारत की संपत्ति को लूटा, लेकिन यह आंतरिक लूट थी, जिसे वे नौकर-चाकर, रॉल्स रॉयसेज और विदेशी प्रेमिकाओं पर उड़ाते थे. किसी ने भी इसका आकलन नहीं किया कि इन राजाओं ने आम आदमी का कितना पैसा लूटा. इस मसले पर एक राष्ट्रवादी विचार यह था कि वे भले ही डाकू थे, लेकिन अपने देश के ही यानी देशी थे.

मैं यह आशा नहीं करता कि इन पैसों को वापस लाया जाएगा और किसी को इसके लिए दंड भी मिलेगा. इस काम के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था न तो सक्षम है और न ही उसमें इतनी इच्छाशक्ति है. यह बात सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया का वित्तीय पोषण कहां से होता है और इसमें कुछ राजनीतिक दलों मसलन वामपंथी पार्टियों को छोड़कर लगभग सारे राजनीतिक दल शामिल हैं. यह पता चला है कि तेल माफ़िया द्वारा यशवंत सोनावणे की हत्या से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को 25 करोड़ रुपये दिए गए थे. इस घटना को झुठलाया भी जा सकता है, लेकिन इसके सच होने की संभावना ज़्यादा है. रोज़ाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण असल में खुली लूट की छूट देता नज़र आता है. नेताओं द्वारा धन की यह लूट राजा-महाराजाओं द्वारा लूटे गए धन से कहीं बड़ी है. यह पैसा बहुत हद तक भारतीय अर्थ व्यवस्था में ही वापस लौट आता है. इस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां लोगों को बहलाने-फुसलाने, नेताओं के भाषण कार्यक्रम करने, मतदाताओं को पैसा देकर ख़रीदने और विरोधी दलों को डराने-धमकाने के लिए करती हैं. इस काम में विपक्षी दल भी शामिल हैं. यह आंतरिक लूट है, लेकिन यह कई वैध और अवैध तरीक़ों से अर्थव्यवस्था को मदद भी पहुंचाती है. आख़िरकार इसी तरीक़े से तो भारतीय लोकतंत्र चल रहा है.

दादाभाई नौरोजी भारत की ग़रीबी को लेकर चिंतित थे, लेकिन आज की राजनीतिक व्यवस्था को मानो इस सब की कोई फ़िक्र ही नहीं है. आख़िरकार हमारी अर्थव्यवस्था 8 से 9 फ़ीसदी की दर से बढ़ रही है और सरकारी खजाना वैध रूप से चुकाए जा रहे टैक्स से भरा हुआ है. ऐसी हालत में भला कोई सरकार स्विस अकाउंट या 2-जी घोटाले या राजनीति में काले धन के इस्तेमाल जैसी छोटी-मोटी बातों पर क्यों ध्यान दे. हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है. काले धन की करामात को धन्यवाद. हो सकता है कि असली विकास दर 12 से 13 फ़ीसदी हो. यह आपराधिक हो सकता है, लेकिन फ़िक्र किसे है.

feedback@chauthiduniya.com

रवि किशोर

आम आदमी और न्यायपालिका

आज हर कोई न्यायपालिका के उत्तरदायित्व की बात कर रहा है. यानी न्यायपालिका से जुड़े हर एक तंत्र को उत्तरदायी कैसे बनाया जा सके. जज इंक्वायरी एक्ट विधेयक में संशोधन की बात चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक परिषद गठित करने की बात है, जो आरोपों के घेरे में आए जजों के ख़िलाफ़ जांच कर सके. सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसमें कोई शक नहीं है कि जजों की जवाबदेही तय करने और उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जजों और ख़ासकर उच्च न्यायालयों में बैठे जजों की ईमानदारी को लेकर आम आदमी के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं. यह बात सुप्रीमकोर्ट की एक बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू एवं ज्ञान सुधा मिश्रा थे, के एक कथन से और भी पुख्ता होती है. इन दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा था कि सिंगल बेंच द्वारा दिए गए कुछ अतार्किक और चौंका देने वाले निर्णयों से इस देश के आम आदमी का विश्वास भीतर तक हिल गया है.

ऑर्डर लिखते हुए जस्टिस काटजू कहते हैं कि हैमलेट में शेक्सपीयर ने लिखा है कि डेनमार्क के राजतंत्र में कुछ सड़ रहा है और यही बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में कही जा सकती है कि वहां कुछ सड़ रहा है. बेंच ने आगे कहा, हमें ऐसा कहते हुए दु:ख हो रहा है, लेकिन यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ ख़ास जजों की ईमानदारी को लेकर शिक़ायतें आ रही हैं.

ऑर्डर लिखते हुए जस्टिस काटजू कहते हैं कि हैमलेट में शेक्सपीयर ने लिखा है कि डेनमार्क के राजतंत्र में कुछ सड़ रहा है और यही बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में कही जा सकती है कि वहां कुछ सड़ रहा है. बेंच ने आगे कहा, हमें ऐसा कहते हुए दु:ख हो रहा है, लेकिन यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ ख़ास जजों की ईमानदारी को लेकर शिक़ायतें आ रही हैं. कुछ जजों के नाते-रिश्तेदार उसी अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं और शुरू के ही कुछ सालों में इन जजों के बेटे या संबंधी करोड़पति बन जाते हैं, अच्छा-ख़ासा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, उनके पास महंगी कारें आ जाती हैं, वे आलीशान घर बना लेते हैं और एक विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं. अब वे दिन गए, जब किसी जज का रिश्तेदार या बेटा अपने संबंधों का फ़ायदा नहीं उठा पाता था और उसे भी अन्य वकीलों की तरह ही संघर्ष करना पड़ता था.

पीएफ घोटाले में फंसे जजों की जांच चल रही है और दिनाकरन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी जारी है. प्रशांत भूषण को हालांकि सुप्रीमकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन के ख़िलाफ़ एक टिप्पणी के लिए अवमानना का मामला झेलना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अपने पिता वरिष्ठ वकील एवं पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण का समर्थन मिल रहा है. प्रशांत भूषण अपने उस कथन पर क़ायम हैं, जो के जी बालाकृष्णन के कुछ संबंधियों से जुड़ा था. यह मामला भी शक पैदा करता है. प्रशांत भूषण द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन जस्टिस अय्यर ने भी किया है. उक्त चंद उदाहरण ही पूरी स्थिति को समझने के लिए काफी हैं. हालांकि ऐसे मामले अभी और भी हो सकते हैं, जो अब तक छुपे हो सकते हैं. लेकिन इसकी वजह से आम आदमी का हित ख़तरे में पड़ गया है और कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है. आम आदमी एक मुक्त और साफ-सुथरी न्यायपालिका की अपेक्षा तो रखता ही है, साथ ही यह भी चाहता है कि न्याय मिलने की प्रक्रिया और तेज हो.

आज तीन मिलियन से ज़्यादा मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं. साथ ही निचली अदालतों में क़रीब 26.3 मिलियन मामले लंबित हैं. जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, यहां भी 31 दिसंबर, 2010 तक के आंकड़ों के मुताबिक़, लगभग 54,562 मामले लंबित हैं, जिनमें से 35,283 मामले एक साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं. उक्त आंकड़े आम आदमी का न्यायपालिका में विश्वास कम करने का काम कर रहे हैं. दो नए मामलों ने आम आदमी की निराशा को और बढ़ा दिया है. एक मामले में जहां रॉ के एक पूर्व महिला अधिकारी ने ख़ुद को कोर्ट रूम में बंद करके ख़ूब शोरगुल मचाया. हालांकि उसकी इस हरकत को मनोवैज्ञानिक विकार से जोड़कर देखा गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन असल बात यह थी कि वह अपने मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी से निराश हो गई है. एक अन्य मामले में एक याचिकाकर्ता ने बांबे हाईकोर्ट को 20 हज़ार रुपये का चेक भेजकर बदले में 60 मिनट की सुनवाई का वक़्त मांगा. इस मामले में डिवीज़न बेंच ने उससे लिखित में क्षमा मांगने को कहा. पुणे के अनिल तिलोतेकर ने यह चेक भेजा था और सुनवाई के लिए जल्दी समय मांगते हुए उसने पत्र भी लिखे थे और ईमेल भी भेजा था.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल

आवरण कथा मनमोहन-सोनिया के मतभेद (31 जनवरी-06 फरवरी) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर कांग्रेस के अंदरखाने में चल रही उठापटक पर बख़ूबी रोशनी डाली गई. आम जनता को तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि मंत्री बनाने और मंत्री पद से हटाने के लिए कौन से मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं. यह और भी विचारणीय बात है कि जिनके ख़िलाफ़ संगीन आरोप हैं या जो अपने कर्तव्य निर्वहन में असफल हैं, उन्हें नहीं हटाया गया. प्रधानमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह जिन मंत्रियों के कामकाज से ख़ुश या संतुष्ट नहीं थे, उन्हें निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए था. इसमें पार्टी की दखलंदाज़ी का कोई औचित्य समझ में नहीं आता.

-शैलेंद्र कुमार शर्मा, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

अरविंद मायाराम की माया

पुरा प्रोजेक्ट आवंटन में धांधली: देशमुख के लिए चुनौती होंगे ऐसे अधिकारी शीर्षक से प्रकाशित आलेख के तहत आईएएस अधिकारी अरविंद मायाराम के बारे में पढ़ने को मिला. आश्चर्य हुआ और दु:ख भी कि उच्च पदों पर बैठे लोग किस तरह अपने परिवारीजनों के लाभ के लिए देश और जनता के हितों की बलि चढ़ा देते हैं. वास्तव में ऐसे अधिकारियों की वजह से ही व्यवस्था में घुन लग गया है और आम लोगों का शासन-प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है.

-किरण झा, *उत्तम नगर, नई दिल्ली.*

ज़िम्मेदार कौन?

गंगोत्री में ही गंगा मैली (31 जनवरी-06 फरवरी) आलेख के अंतर्गत लेखक ने एक गंभीर विषय उठाया है. एक समय था कि लोग गंगाजल को अमृत समान महत्व देकर उसके आचमन को आतुर रहते थे और आज स्थिति यह है कि वह नहाने लायक़ भी नहीं रह गया है. इसके लिए सरकार-प्रशासन से कहीं ज़्यादा हम लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि गंगा में कूड़ा-करकट तो हमारे द्वारा ही बहाया जाता है या किसी को बहाते हुए नज़रअंदाज किया जाता है. गंगा में कचरा और प्लास्टिक किसकी देन है, जनता की या सरकार की? सरकार या प्रशासन को कुछ कहने से पहले हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि हम आख़िर क्या कर रहे हैं.

-रीतेश सिंह, *फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

गौ हत्या पर प्रतिबंध ज़रूरी

31 जनवरी-06 फरवरी के अंक में प्रकाशित आलेख-कब लगेगा गौ हत्या पर प्रतिबंध काफी विचारणीय है. गाय को हमारे देश में मां के रूप में पूजा जाता है, बावजूद इसके गौ हत्या धड़ल्ले से जारी है और सरकार सब कुछ जानकर भी ख़ामोश है. वैसे भी जो लोग धर्म के नाम पर गौ हत्या कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि कोई भी धर्म जीव हत्या का पाठ नहीं पढ़ाता. हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है.

-मीना रानी, *दरभंगा, बिहार.*

दलितों की हालत जस की तस

आवरण कथा-कांग्रेस मीठा ज़हर है (24-30 जनवरी) पढ़ी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने बड़े-बड़े लुभावने नारे देकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया. देश का विभाजन, कश्मीर समस्या, 1962 का भारत-चीन युद्ध कांग्रेस की देन है. आज़ादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी दलितों की वही स्थिति है, जो आज़ादी के पहले थी. 80 प्रतिशत से अधिक दलित रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं.

-हरिहर आज़ाद, *सीवान, बिहार.*

तर्कसंगत प्रश्न उठाना देशद्रोह नहीं

करकरे भगवान थे क्या? कोई अपनी ड्यूटी करते हुए मारा जाता है और अगर वह अफसर है तो शुरू हो जाता है महिमा मंडन. पुलिस का कोई अधिकारी मुंबई में रहकर कहे कि वह ईमानदार है तो यह सबसे बड़ा मज़ाक होगा. जिन्हें वोटों की राजनीति करनी है, वे करें गुणगान. किसी का मारा जाना उसके महान होने का प्रमाण नहीं होता. आईआईटी के अध्यापक द्वारा इस तरह का लेख लिखना आश्चर्य है. भावनाओं की ज़मीन पर यथार्थ का महल नहीं खड़ा होता.

-मदन मोहन तिवारी, *ई-मेल से.*

आरटीआई और चौथी दुनिया

मैं चौथी दुनिया अख़बार का नियमित पाठक हूं. मुझे आरटीआई से जुड़ी ख़बरें पढ़ना अच्छा लगता है. आप जनता की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं. यह काबिले तारीफ़ है. मुझे मेरी दुनिया की कार्टून स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है.

-सुरेश शर्मा, *मधुबनी, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संसद को जनता के गुस्से से डरना चाहिए

राजा अभी कुछ महीनों पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे. अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं, पहले रिमांड फिर जेल, ज़ाहिर है, ज़मानत पर बाहर आ ही जाएंगे. पर उनकी गिरफ्तारी ने सीधा सवाल प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर खड़ा कर दिया है. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के दूसरे कार्यकाल में राजा ही संचार मंत्री रहे. उनसे पहले के संचार मंत्री दयानिधि मारन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को धमकाया, जुबानी नहीं, ख़त लिखकर, उसके बाद तो प्रधानमंत्री कार्यालय को जैसे सांप सूंघ गया. दयानिधि मारन ने पहले मनमानी की, बाद में ए राजा खुलकर खेले. इतना खुलकर खेले कि सभी को पता चल गया कि उनके पीछे देश के किस पैसे वाले का चेहरा है.

राजा की गिरफ्तारी किसने टाली या फिर राजा को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की मजबूरी क्या थी? क्या प्रधानमंत्री को यह डर था कि यदि वह राजा का विभाग बदल देंगे या उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देंगे तो द्रमुक उनकी सरकार गिरा देगी? क्या इस डर से प्रधानमंत्री ने राजा को भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी थी? या प्रधानमंत्री को सचमुच पता नहीं था कि संचार मंत्रालय में क्या हो रहा है, पर यह तर्क विश्वास करने के लायक नहीं है.

हर रात साढ़े नौ बजे के बाद डायरेक्टर आईबी नियमित रूप से प्रधानमंत्री से मिलने जाता है. उसकी यह ड्यूटी है कि वह देश के हालात के बारे में प्रधानमंत्री को बताए. आईबी मंत्रियों और सचिवों की लगातार निगरानी करती है. इसलिए अवश्य आईबी ने प्रधानमंत्री को संचार मंत्रालय में चल रहे घपलों और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे लूट के खुले महाखेल के बारे में अवश्य बताया होगा. सवाल है कि क्यों प्रधानमंत्री ने इसकी अनदेखी की.

राजा के कारनामों से लाभ उठाने वालों में कहीं कोई ऐसा शख़्स तो नहीं है, जिसका नाम आने से सरकार की स्थिरता पर ही ख़तरा खड़ा हो जाए? या फिर राजा ने सबको थोड़ा दिया और ज़्यादा ख़ुद हड़प लिया. चेन्नई के शहंशाह की राजा से खुन्नस कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है. पहले मधु कोड़ा और फिर राजा, लूट की इस महागाथा में कई अध्याय ऐसे हैं, जिनका पढ़ा जाना अभी बाकी है.

अगर प्रधानमंत्री राजा को बर्ख़ास्त कर देते तो किसी भी कीमत पर द्रमुक उनसे समर्थन वापस लेने की हिम्मत नहीं करती. प्रधानमंत्री अगर अपने मंत्रियों पर लगाम लगाते तो उन्हें भी बड़े व्यक्तियों में गिना जाता. उन पर यह आरोप नहीं लगता कि यह कई प्रधानमंत्रियों की अराजक कैबिनेट है, जिसकी एक दिशा नहीं है. इस मंत्रिमंडल में शरद पवार हैं, इसमें ममता बनर्जी हैं और इसमें जयराम रमेश हैं. वैसे इसमें कमलनाथ, कपिल सिब्बल और सीपी जोशी भी हैं. ये सब प्रधानमंत्री हैं, जिनका संयोजन मनमोहन सिंह करते हैं.

मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, पर उनका अर्थशास्त्र भारत के अस्सी प्रतिशत लोगों के काम में नहीं आ रहा है. सन् बयानवे की बनाई आर्थिक नीतियां आज देश में न औद्योगिक दर बढ़ा पा रही हैं और न रोज़गार दे पा रही हैं. भूख और बीमारी से लड़ना तो दूर, जो थोड़ा-बहुत आसान ज़िंदगी जी रहे थे, उन्हें भी महंगाई ने ख़ून के आंसू रुला दिए. महंगाई से सरकार चिंतित दिखाई ही नहीं दी. प्रधानमंत्री ने जब ख़ुद कहा कि वह ज्योतिषी नहीं हैं तो फिर शरद पवार पर टिप्पणी क्यों करें.

राजा के कारनामों से लाभ उठाने वालों में कहीं कोई ऐसा शख़्स तो नहीं है, जिसका नाम आने से सरकार की स्थिरता पर ही ख़तरा खड़ा हो जाए? या फिर राजा ने सबको थोड़ा दिया और ज़्यादा ख़ुद हड़प लिया. चेन्नई के शहंशाह की राजा से खुन्नस कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है. पहले मधु कोड़ा और फिर राजा, लूट की इस महागाथा में कई अध्याय ऐसे हैं, जिनका पढ़ा जाना अभी बाक़ी है. अगर प्रधानमंत्री राजा को बर्ख़ास्त कर देते तो किसी भी कीमत पर द्रमुक उनसे समर्थन वापस लेने की हिम्मत नहीं करती.

प्रधानमंत्री की आलोचना करना हमारा काम है भी और नहीं भी. पर मन रोने लगता है, जब सौ करोड़ से ज़्यादा लोगों की ताक़त वाले देश का प्रधानमंत्री किसी भी समस्या के सामने असहाय दिखाई पड़ता है. राजा का भ्रष्टाचार हो या कॉमनवेल्थ गेम्स का, घोटालों के किसी भी खेल को रोकने में प्रधानमंत्री बेबस नज़र आते हैं. महंगाई, बेकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सवाल तो उन्हें विचलित करते ही नहीं.

हां उनकी मुस्कराहट तभी दिखाई देती है, जब या तो ओबामा आते हैं या चीनी राष्ट्रपति, जो हमें मूर्ख बनाकर समझौते कर अपने देशवासियों के लिए हमसे तोहफ़े ले जाते हैं. अगर प्रधानमंत्री थोड़ा ध्यान देते तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार योजना में भ्रष्टाचार नहीं होता और यह देश की तक़दीर बदलने वाली योजना होती. इस योजना के कार्यान्वयन की शैली ऐसी रखी गई है कि गांव-गांव में भ्रष्टाचार फैल गया है और गांव के अधिकांश प्रधान और पंचायत के सदस्य भी इसके हिस्सेदार हो गए हैं.

हम ये बातें इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम सत्ता पर रहे लोगों का अपमान करना चाहते हैं. हमें डर है कि पश्चिम एशिया में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और लोकतंत्र के लिए जली आग कहीं हमारे यहां भी न जल जाए. हमें इतना ज़रूर पता है कि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाखों लोग इतिहास में पहली बार शामिल हुए थे. अगर जनता की तकलीफ़ों की चिंता सत्ता को नहीं हुई तो फिर जनता न तो सत्ता और न विपक्ष, किसी के बहकाने में नहीं आएगी. न्याय होता हुआ दिखना चाहिए और यही हमारे देश में नहीं हो रहा है. सरकार को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, बेकारी, महंगाई और भूख के ख़िलाफ़ लड़ते दिखना चाहिए. जब हम सरकार कहते हैं तो उसमें विपक्ष शामिल है. संसद का अगला सत्र लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय कर सकता है. लोगों के गुस्से से संसद में बैठे लोगों को डरना चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

अंधश्रद्धा को बढ़ावा देती सरकार

कहते हैं कि आस्था में पर्वतों को डिगाने की क्षमता होती है, परंतु अभी हाल में एक पर्वत आस्था का भार नहीं झेल सका. बीती 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला तीर्थस्थान में हज़ारों श्रद्धालु मकर ज्योति की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा थे. इसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा धसक गया और नतीजे में मची भगदड़ में 102 लोगों की जानें चली गईं. इसी स्थान पर 1998 में भी मकर संक्रांति के दिन 52 लोग भगदड़ में मारे गए थे. माना जाता है कि मकर ज्योति एक दैवीय प्रकाश है, जो भगवान अय्यप्पा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रगट होती है. इस घटना से कई प्रश्न उपजे हैं. पहली बात तो यह है कि जिस भी स्थान पर श्रद्धावश या किसी अन्य कारण से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, वहां भीड़ को नियंत्रण में रखने, साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को हरसंभव प्रयास करने चाहिए. चाहे वह कुंभ मेला हो या कोई अन्य अवसर, सरकार को व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी केवल आयोजकों पर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन एक समस्या यह भी है कि कुछ धार्मिक आयोजनों में कट्टरता का इतना बोलबाला रहता है कि सरकार के लिए भी उपयुक्त व्यवस्थाएं करना मुश्किल हो जाता है.

अभी कुछ ही वर्ष पहले, व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त एक महिला आईएएस अधिकारी को सबरीमाला मंदिर में इस आधार पर घुसने नहीं दिया गया था कि भगवान अय्यप्पा ब्रह्मचारी हैं और इसलिए 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं उनके सामने नहीं जा सकतीं. सबरीमाला में मकर संक्रांति के दिन होने वाला आयोजन श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज़ से देश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है. सबरीमाला के इतिहास के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, परंतु यह निर्विवाद है कि वहां आने वाले श्रद्धालु भगवान अय्यप्पा के साथ-साथ एक मुस्लिम संत, जिन्हें वावेर स्वामी कहा जाता है, को भी नमन करते हैं. हिंदू श्रद्धालु मंदिर में दर्शन से पहले वावेर मस्जिद में जाते हैं.

सबरीमाला कांड के कुछ पहलू अचंभित करने वाले हैं. ऐसा माना जाता है कि दैवीय प्रकाश ऋषियों द्वारा भगवान अय्यप्पा की आरती उतारने से प्रगट होता है. सच्चाई यह है कि मकर ज्योति राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा जलाई जाती है. इसके लिए बड़ी-बड़ी भट्ठियों में काफ़ी मात्रा में कपूर जलाया जाता है. कई दशक पहले तक स्थानीय आदिवासी भगवान अय्यप्पा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह ज्योति जलाते थे.

सबरीमाला कांड के कुछ पहलू अचंभित करने वाले हैं. ऐसा माना जाता है कि दैवीय प्रकाश ऋषियों द्वारा भगवान अय्यप्पा की आरती उतारने से प्रगट होता है. सच्चाई यह है कि मकर ज्योति राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा जलाई जाती है. इसके लिए बड़ी-बड़ी भट्ठियों में काफी मात्रा में कपूर जलाया जाता है. कई दशक पहले तक स्थानीय आदिवासी भगवान अय्यप्पा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह ज्योति जलाते थे. बाद में मंदिर ट्रस्ट अय्यप्पा देवासम यह काम करने लगा. इस काम में राज्य सरकार की भी भागीदारी है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा मंदिर से कुछ दूरी पर यह ज्योति जलाई जाती है. इस ज्योति को दैवीय बताया जाता है और इसके आसपास मिथकों का एक जाल बुन दिया गया है. धीरे-धीरे यह मान्यता प्रचलित हो गई कि ज्योति के दर्शन से पुण्य मिलता है. पहले हज़ारों और अब लाखों लोग इस पुण्य लाभ को पाने के लिए सबरीमाला में जुटने लगे हैं. ज्योति को ठीक प्रकार से देखने के लिए श्रद्धालु पहाड़ी के ऊंचे स्थानों पर भीड़ लगाने लगे. इससे ही शायद पहाड़ का एक हिस्सा धसक गया. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मान्यता के कारण मंदिर में आने वाले चढ़ावे में आशातीत वृद्धि हुई है.

इस मामले में सरकार व्यवस्था बनाए रखने में असफलता के लिए तो दोषी है ही, कपूर जलाकर दिव्य ज्योति पैदा करने के लिए मंदिर ट्रस्ट का सहयोग करने के लिए भी दोषी है. मंदिर प्रशासन भी अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता. वह न केवल दशकों से भोले-भाले भक्तों के साथ धोखाधड़ी करता रहा है, बल्कि महिला अधिकारियों का मंदिर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर व्यवस्था बनाने के काम में अड़ंगेबाज़ी भी करता रहा है. इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों के मारे जाने में अपनी ज़िम्मेदारी से न तो सरकार बच सकती है और न ही मंदिर प्रशासन. यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के धार्मिक मामलों के मंत्री ने मानव निर्मित ज्योति को दिव्य ज्योति बताए जाने के झूठे प्रचार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. देवासम मंत्री जी. सुधाकरन ने कुछ वर्षों पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि पिछली बार मैं मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला में मौजूद था. मैंने दैवीय तारा देखा. ठीक उसी वक़्त मकर ज्योति जलाई गई. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह ज्योति मानव निर्मित है. इस घटना से मंदिर ट्रस्टों समेत हमारे प्रशासकों के बारे में भी कई विचलित करने वाले प्रश्न उपजे हैं. हम सभी को आमजनों की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए, परंतु कोई तब क्या करे, जब उसे पक्का पता हो कि जिसे दैवीय बताया जा रहा है, वह दरअसल मानव निर्मित है. हमारा संविधान तार्किकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कहता है. केरल में कई संगठन मकर ज्योति की सच्चाई से जनता को परिचित कराने के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है. श्रद्धा का समाज में महत्वपूर्ण

स्थान है, परंतु जब यही श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाए, तब क्या किया जाए? अगर हमें किसी दैवीय परिघटना की सच्चाई मालूम हो तो उसे छुपाना चाहिए या सार्वजनिक करना चाहिए? कुछ साल पहले कैपिलरी एक्शन नामक वैज्ञानिक परिघटना के आसपास श्रद्धा का जाल बुनकर उसे गणेश का दूध पीना बताया गया था. इस अंधविश्वास के चलते लाखों लीटर दूध नालियों में बह गया. देश के कई शीर्ष राजनेताओं ने गणेश जी के दूध पीने को चमत्कार बताकर भारतीय संविधान के मूल्यों का मखौल बनाया. अंधश्रद्धा का विरोध किया जाना चाहिए. एक बड़ी समस्या यह है कि अंधश्रद्धा लगभग हमेशा धर्म से जुड़ी रहती है. यही कारण है कि बेनी हिम ने मनोविज्ञान के सम्मोहन एवं सम्मोहन चिकित्सा जैसे जाने-माने सिद्धांतों को धर्म का जामा पहनाया. इससे संदेह करना और प्रश्न पूछना मुश्किल हो जाता है. इतिहास गवाह है कि वंचितों को अधिकार दिलाने एवं सामाजिक परिवर्तन के ज़रिए एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्होंने हमेशा अंधश्रद्धा का विरोध किया. चार्वाक से लेकर गौतम बुद्ध और कबीर एवं तुकाराम से लेकर ज्योतिबा फुले एवं अंबेडकर तक ने अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का कड़ा विरोध किया तथा तार्किक सोच पर जोर दिया. गांधी जी ने भारतीय समाज की धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए जनता से संवाद स्थापित करने के लिए धर्म की भाषा अवश्य इस्तेमाल की, परंतु उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों को कभी प्रश्रय नहीं दिया. नेहरू जी ने तो अंधश्रद्धा का खुलकर विरोध किया और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने की बात कही. आज नेहरू जी की भाषा में कोई बड़ा नेता नहीं बोलता और आमजनों की श्रद्धा-भक्ति का जमकर दुरुपयोग हो रहा है. आधुनिक भारत का निर्माण अंधश्रद्धा विरोध और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने के रास्ते पर ही चलकर हो सकता है. ज़रूरत इस बात की है कि आमजनों के विश्वास एवं मान्यताओं का सम्मान करते हुए भी हमें ईमानदारी और निष्ठा से तार्किकता को प्रोत्साहित करना चाहिए.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

प्रिंस्टन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के नतीजे उस आम धारणा के विपरीत आए हैं कि आसान और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखे पाठ को पढ़कर उसे याद रख पाना सरल होता है.

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आपके पत्र, हमारे सुझाव

अपील कहां करूं

सूचना अधिकार क़ानून के तहत मैंने अपना आवेदन पीएनबी मुख्यालय दिल्ली भेजा था. द्वितीय अपील के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली. मैंने द्वितीय अपील लखनऊ स्थित राज्य सूचना आयोग में भेजी थी. मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में होगी या केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में? मैंने दोनों जगह अपील भेज दी है.

–सलीमुद्दीन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.

दरअसल, राज्य सरकार से संबंधित विभागों के लिए राज्य सूचना आयोग और केंद्र सरकार से संबंधित विभागों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में अपील किए जाने का प्रावधान है. पीएनबी से जुड़े मामलों के लिए आपको केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करनी है. आपने वहां अपील कर दी है, यह अच्छी बात है.

आवेदन शुल्क कैसे जमा करें

आपका अख़बार सही जानकारी और ज्ञान का समुद्र है, मुझे सूचना अधिकार क़ानून के तहत सभी विभागों के लिए आवेदन का प्रारूप चाहिए. क्या आप मुझे मेरे ई-मेल पते पर भेज सकते हैं? क्या आवेदन शुल्क नकद रूप में आवेदन के साथ रखकर भेज सकते हैं या कोर्ट फीस स्टांप के रूप में? आवेदन किस तरह भेजा जाए, ताकि सबूत रहे और संबंधित विभाग यह न कह सके कि आपका आवेदन मिला ही नहीं?

–चंद्र किशोर देशमुख.

आप चौथी दुनिया में हर सप्ताह प्रकाशित होने वाले आवेदन का इस्तेमाल कर सकते हैं. उक्त आवेदन विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित होते हैं. जहां तक आवेदन शुल्क जमा करने का सवाल है तो आप आवेदन के साथ नकद दस रुपये नहीं भेज सकते. आवेदन के साथ आप वहां दस रुपये नकद काउंटर पर जमा कर सकते हैं या फिर आईपीओ, सीएफएस आदि के रूप में भी आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं.

सूचना नहीं मिली

मैंने मंडल रेल प्रबंधक (पूरे) लखनऊ को एक शिक़ायती पत्र भेजा था, जिसमें लखनऊ रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या एक पर चल रहे पीसीओ द्वारा अधिक पैसे लिए जाने की शिक़ायत की गई थी. बाद में उसी शिक़ायत के आधार पर एक आरटीआई आवेदन दिया, लेकिन कहा गया कि आपका शिक़ायती पत्र मिला ही नहीं. मैंने प्रथम अपील की, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली.

–पं. एस बी शुक्ला, लखनऊ.

यदि आपको प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं मिली है तो आप इसकी शिक़ायत सीधे केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं और पीआईओ पर जुर्माना लगाने की मांग भी कर सकते हैं.

नियुक्ति में धांधली

मैं 1995 से सीजनल संग्रह अमीन के पद पर तहसील चांदपुरा, ज़िला बिजनौर में समय-समय पर कार्य करता रहा हूं. 1997 में मुझे इस पद से हटा दिया गया, जिसके ख़िलाफ़ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया, तब मुझे फिर इस पद पर रख लिया गया. अदालत ने संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली 1974 के नियम 5 के अंतर्गत नियमित किए जाने पर विचार करने के निर्देश दिए थे. 2008 में मैंने सूचना क़ानून के तहत पता लगाया कि ज़िले में नियमित अमीन के 10 पद अधिक भरे हुए हैं. मई 2009 में दो पद रिक्त दिखाकर दो लोगों की भर्ती कर दी गई, लेकिन मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया. जबकि आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक़ 7 अक्टूबर, 2008 से 15 जून, 2009 के बीच ज़िले में संग्रह अमीनों का कोई भी पद रिक्त नहीं हुआ था. मुझे क्या करना चाहिए, सवाल है कि जब ज़िले में दो पद रिक्त थे, तब मेरी नियुक्ति क्यों नहीं की गई?

–अवनीश कुमार, चांदपुर, बिजनौर.

आप आरटीआई का इस्तेमाल करके कुछ और सूचनाएं निकलवाएं. खासकर, पद रिक्त होने के संबंध में. तमाम सूचनाएं जुटाने के बाद आप इस मामले को एक बार फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(स्कूल में अध्यापक या अस्पताल में डॉक्टर का न आना या देर से आना)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैं अपने गांव/कस्बे/शहर में स्थित................ स्कूल/अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:

1. उपरोक्त संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं. इन सभी कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करें, जिसमें इनके बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध हो:
नाम...
पद...
कार्यभार/ज़िम्मेदारी का विवरण..................................
वर्तमान कार्यालय में कब से कार्यरत हैं............................
प्रतिदिन ड्यूटी पर आने एवं जाने का समय.......................

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की पिछले छह महीने की प्रति मुझे उपलब्ध कराएं.

3. अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है या बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने की क्या व्यवस्था है. कृपया इस संबंध में नियमों/दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं.

4. पिछले छह महीने में उपरोक्त में से कितने कर्मचारियों के ख़िलाफ़ देर से आने या अनुपस्थित रहने के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के तहत क्या कार्रवाई हुई है, उसका पूरा विवरण एवं उस संबंध में पारित किए गए आदेशों/निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

5. कृपया उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पिछले छह महीने में लिए गए कुल अवकाशों (साप्ताहिक एवं अन्य कार्यालय अवकाश दिवसों को छोड़कर) का विवरण उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम...
पता..
फोन नंबर...

संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
सप्ताह के आरंभ में धीरे-धीरे ही स्थिति को नियंत्रण में लाएं. कोई अच्छा संदेश आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर कर देगा. किसी अभिन्न मित्र या परिवारीजन से चल रहा मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
सप्ताह भर पैदा होने वाले तनाव अचानक समाप्त हो जाएंगे. कठोर परिश्रम करने के बावजूद आपको वांछित लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है. कभी-कभी समय साथ नहीं देता है. कुछ ऐसा ही अवरोध सप्ताह के मध्य में आपको भी झेलना पड़ सकता है.

मिथुन 21 मई से 20 जून
दूसरों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा है. अपने काम से काम रखना अभीष्ट होगा. आपको किसी कठिन काम के बन जाने की ख़ुशी होगी. संतान पक्ष या परिवारीजनों की ओर से कुछ अच्छी ख़बर मिल सकती है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन इस सप्ताह के दौरान हो जाएगा. फ़िलहाल आपके शत्रु और विरोधी शांत रहेंगे. यदि आप परहेज से रहें तो आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है. छिटपुट कार्य या अनुबंध हाथ में लेने से आगे चलकर संतोषजनक धनलाभ के योग हैं.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
यह सप्ताह फ़ायदेमंद है और आशाजनक भी. अध्ययन-अध्यापन में रुचि बढ़ेगी. काफी मेहनत के बाद भी वांछित लाभ की प्राप्ति में अवरोध झेलना पड़ेगा. शायद आपकी खिन्नता और चिड़चिड़ेपन का यही कारण हो सकता है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
इस सप्ताह के दौरान कामकाज में गतिरोध पैदा होंगे. कोई खास गुत्थी सुलझेगी. बहुत सोच-विचार, युक्ति और परिश्रम के बावजूद सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए व्यर्थ की दौड़-भाग लेकर आ रहा है. अगर आप इधर-उधर भटकना छोड़ दें.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
सप्ताह भर की व्यग्रता अचानक समाप्त हो जाएगी. काफी समय के बाद अच्छे सौभाग्य और समय की बलवानता का एहसास आपको होने वाला है. आपके स्वास्थ्य एवं सामाजिक दायरे में भी सुधार आ जाएगा.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
इस सप्ताह महत्वपूर्ण कार्यों की जांच-पड़ताल कर लें. वैसे तो आपका अधिकांश समय ठीकठाक व्यतीत हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको अपने प्रत्येक काम में सावधानी रखनी होगी.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
इस सप्ताह लाभ के अवसर प्रबल होंगे. अशुद्ध गोचर के कारण आपका मन कई प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहेगा. हो सकता है, आपको आगे चलकर किसी भारी नुक़सान का भी सामना करना पड़े.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
इस सप्ताह दूसरों के मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने से विवाद ही बढ़ेगा. आपको किसी विचारे हुए काम को पूरा करने में सफलता मिलेगी. जो काम आपने शुरू किए थे, उनमें अच्छी प्रगति देखकर आपको भी हर्ष होगा.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
इस सप्ताह सज्जनों का सहयोग प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहें. कार्य बनने में देर नहीं लगेगी. आपके मन में उत्साह और प्रसन्नता रहेगी. जो भी काम आप गंभीरता से करेंगे, उन सभी प्रयासों में सफलता मिल जाएगी.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
सप्ताह के आरंभ में जातिगत संस्थाओं में मान-सम्मान होगा, छिटपुट लाभ भी मिलेगा. आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी. यह एक सुखद बात है कि परिवारीजन और नज़दीकी दोस्त आपके लिए सहायता के द्वार खोल सकते हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

गैजेट हैं दुर्घटनाओं का सबब

हाल में हुई विमान दुर्घटनाओं में ज़्यादातर की वजह तकनीकी खामी या आतंकवादी वारदातें रही हैं, लेकिन कई और प्रश्न भी उठे हैं. इनमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि सैकड़ों की संख्या में हवा में उड़ रहे यात्री जहाजों में से अधिकतर काफी पुराने हो चुके हैं और नए और आधुनिक गैजेटों की वजह से उन्हें कोई ख़तरा हो सकता है? क्या विमान यात्रा के दौरान गैजेटों का इस्तेमाल करने से हवाई दुर्घटना हो सकती है? 2003 में न्यूज़ीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक विमान हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. जांच के दौरान पता चला कि दुर्घटना के समय पायलट मोबाइल फोन पर अपने घरवालों के साथ बात कर रहा था. 2007 में अमेरिका में बोइंग 737 उड़ा रहे एक पायलट ने पाया कि विमान का नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया है. परिचारिका ने यात्रियों की जांच की तो देखा कि एक यात्री अपने जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है. परिचारिका ने उससे निवेदन किया कि वह उसे बंद कर दे. यात्री ने अपना गैजेट बंद कर दिया और विमान का नेविगेशन सिस्टम सुचारू ढंग से चलने लगा.

ऐसे कई और उदाहरण सामने आए हैं, जब विमान यात्रा के दौरान गैजेटों का इस्तेमाल करने से विमान की मशीनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. एक अख़बार के मुताबिक़, अधिकतर डिवाइज़ सिग्नल प्रसारित करते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें भी प्रवाहित करते हैं. उक्त तरंगें विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. पुराने हो रहे विमानों में नए गैजेटों द्वारा प्रसारित हो रही तरंगों से बचाव की तकनीकें उपलब्ध नहीं हैं और न इस बारे में कोई व्यापक शोध किया गया है.

ब्रिटेन के सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. ह्यूज के अनुसार, आज के जमाने में गैजेटों की तकनीकें हर सप्ताह बदल जाती हैं, जबकि विमान की तकनीक 20 वर्ष तक नहीं बदलती. ऐसे में सामंजस्य स्थापित कर पाना मुश्किल होता है. हालांकि अभी तक इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया गया है कि किस प्रकार के गैजेट की वजह से विमान में किस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, परंतु दुनिया भर में हो रही दुर्घटनाओं से इतना तो सबक लिया जा सकता है कि गैजेट ही इन दुर्घटनाओं का सबब हैं.

सरल चीज ही कठिन होती है

कहते हैं कि सरल आंकड़ों और शब्दों को याद करना ज़्यादा आसान है, लेकिन एक शोध आपको चौंका सकता है. वैज्ञानिकों का मत है कि किताबों से अधिक ई-बुक की लोकप्रियता लोगों की स्मरणशक्ति पर विपरीत प्रभाव डाल रही है. वजह हैं ई-बुक रीडर में इस्तेमाल होने वाले अक्षर या फोंट, जो इस तरह के होते हैं, जिन्हें पढ़ना आसान हो और जो स्क्रीन पर सुस्पष्ट दिखें, परंतु इस तरह के फोंट से लिखे लेखों को याद रख पाना कठिन हो जाता

है. प्रिंस्टन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के नतीजे उस आम धारणा के विपरीत आए हैं कि आसान और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखे पाठ को पढ़कर उसे याद रख पाना सरल होता है. इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपनी जांच में पाया कि लोग यदि आसान अक्षरों में लिखे पाठ को पढ़ते हैं तो उनका दिमाग़ एक तरह से ऑटो मोड में चला जाता है और वे उस पाठ को कंठस्थ नहीं कर पाते. वही लेख यदि ऐसे फोंट में लिखा जाए, जिससे पढ़ने में थोड़ी दिक़्क़त आए तो वह लोगों को याद रह जाता है.

वजह यह है कि जब कठिन फोंट में लिखे लेख को पढ़ने का कार्य दिमाग़ को दिया जाता है तो वह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है. दिमाग़ को उस पाठ को पढ़ने में दिक़्क़त आती है तो हमारा ध्यान भी काफ़ी जाता है और इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है. शोधकर्ताओं का मानना है कि एरियल और टाइम्स रोमन फोंट में लिखे गए लेख पढ़ने में सरल हो सकते हैं, परंतु यदि कोई लेख कॉमिक सेंस जैसे फोंट में लिखा गया हो तो उसे याद रख पाना ज्यादा सरल होता है. इसलिए अब जब भी कंप्यूटर पर काम करें तो फोंट को ध्यान ज़रूर रखें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रूस-चेचेन के बीच दिलचस्प, किंतु ज़रूरी मुद्दा यह भी है कि रूस अक्सर यह दावा करता है कि चेचेन विद्रोहियों के प्रमुख नेता आरबी बरायोव को रूसी सेना ने मार दिया था.

लादेन अब मॉस्को की मुसीबत बना

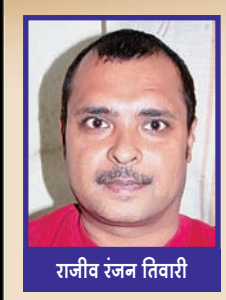

राजीव रंजन तिवारी

सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने चेचेन गणराज्य में विद्रोही आज़ाद होने के लिए न सिर्फ़ बेचैन हैं, बल्कि वे कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हैं. हालांकि चेचेन विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता आरबी बरायोव रूसी सैनिकों के हाथों मारा जा चुका है, फिर भी वहां शांति की स्थापना असंभव लगती है. कारण, आरबी बरायोव दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन का दोस्त था और आजकल उसका सारा काम उसका भतीजा मोवसार बरायोव देख रहा है. समझा जा रहा है कि मोवसार को भी लादेन का पूरा समर्थन है. यानी मॉस्को और आसपास के क्षेत्रों में अशांति के लिए चेचेन विद्रोही ही नहीं, बल्कि अलक़ायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी ज़िम्मेदार है. ताजा घटनाक्रम यह है कि बीती 24 जनवरी को रूस की राजधानी मॉस्को के निकट स्थित डोमोडेडोवो हवाई अड्डे पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें क़रीब 40 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए. इस घटना ने भी रूस को दहला कर रख दिया है. रूसी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आख़िर इस तरह की वारदातों के पीछे कारण क्या हैं? यहां बताना ज़रूरी है कि बीते वर्ष 19 अक्टूबर को चेचेन्या की राजधानी ग्रोज्ने में चेचेन संसद पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें दो लोग मारे गए थे. उस समय कार सवार आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था. बाद में पता चला कि इस घटना को चेचेन विद्रोहियों ने अंजाम दिया था. सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने चेचेन गणराज्य में विद्रोही आज़ादी की मांग को लेकर कई वर्षों से हिंसा पर उतारू हैं. इस हिंसा का असर रूस के भीतर और चेचेन्या में बहुत बुरी तरह पड़ा है.

जानकार बताते हैं कि लंबे समय से हिंसा की आग में जल रहा चेचेन गणराज्य बहुत बदहाल है. रूस के अन्य इलाक़ों की तुलना में दक्षिण-पश्चिम में मौजूद इस गणराज्य में लोगों का जीवन स्तर दोयम दर्जे का है. यहां बेरोज़गारी की समस्या गंभीर है और शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची है. बताते हैं कि चेचेन विद्रोहियों से मॉस्को का विवाद क़रीब दो दशक पुराना है. चेचेन विद्रोही कॉकेशस के पहाड़ी इलाक़े में मौजूद ज़मीन पर अपना दावा करते रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर हो रही हिंसा में अब तक हज़ारों लोगों की जानें गई हैं और क़रीब पांच लाख लोग पलायन कर चुके हैं. यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि मॉस्को में मार्च 2010 में दो मेट्रो स्टेशनों पर हुए विस्फोटों की ज़िम्मेदारी चेचेन विद्रोहियों ने ही ली थी. बीते वर्ष मॉस्को में थिएटर पर क़ब्ज़ा करने की घटना की ज़िम्मेदारी भी चेचेन विद्रोहियों ने ली थी. उसी वक़्त से मॉस्को वासी यह सोच रहे हैं कि आख़िर ऐसा क्या हुआ है कि चेचेन विद्रोही सिर्फ़ मॉस्को में ही कार्रवाई कर रहे हैं. इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि दिसंबर 1994 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने चेचेन्या गणराज्य में तीन साल से चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था. सैनिकों के आतंक से तंग होकर उसी वक़्त चेचेन बाग़ियों ने ऐसे दावे किए थे कि वे अपनी आज़ादी के संघर्ष को मॉस्को समेत रूस के अन्य नगरों तक ले जाएंगे. आख़िरकार जून 1996 में रूसी सैनिकों को चेचेन्या से वापस आना पड़ा. फिर सितंबर 1999 में मॉस्को में दो अपार्टमेंटों में विस्फोट हुए, जिसके लिए चेचेन विद्रोहियों को ही ज़िम्मेदार बताया गया. इसके बाद एक बार फिर रूसी सैनिक कार्रवाई के लिए चेचेन्या गए. हालांकि रूस दावा कर रहा है कि संघर्ष ख़त्म हो गया है, मगर लगता नहीं कि ऐसा हुआ है. फिर भी यदि रूस यह जताने में लगा हुआ है कि चेचेन समस्या सुलझ गई है तो मॉस्को के थिएटर पर क़ब्ज़े और बीती 24 जनवरी की आतंकी घटना ने साफ कर दिया है कि समस्या का अंत होना अभी बाक़ी है.

रूस-चेचेन के बीच दिलचस्प, किंतु ज़रूरी मुद्दा यह भी है कि रूस अक्सर यह दावा करता है कि चेचेन विद्रोहियों के प्रमुख नेता आरबी बरायोव को रूसी सेना ने मार दिया था. यदि इस दावे को सच्चा मान लिया जाए तो भी चेचेनियों के संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है. बताते हैं कि आरबी बरायोव बंधक बनाने की कला में माहिर था. 1998 में तीन ब्रितानियों और न्यूज़ीलैंड के दूरसंचार विभाग से जुड़े एक कर्मचारी की हत्या का शक भी आरबी बरायोव पर ही गया था. उसी वक़्त उसके अलक़ायदा से संबंध होने की पुष्टि हुई थी, क्योंकि बंधक बनाकर हत्या करने वालों में अलक़ायदा से जुड़े लोग भी थे. अब रूसी सेना ने मोवसार बरायोव को मारने के लिए अभियान छेड़ रखा है. हालांकि सेना ने कई बार दावा भी किया है कि उसने मोवसार बरायोव को मार दिया है. चूंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि रूसी सेना ने जिस शख़्स को मारने का दावा किया, वह बाद में जीवित निकला. इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मोवसार मारा जा चुका है, क्योंकि चेचेन विद्रोहियों का आंदोलन अब भी शबाब पर है.

ख़ैर, 24 जनवरी की घटना के पीछे उन्हीं चेचेन विद्रोहियों और उत्तरी कॉकेशस के इस्लामी चरमपंथियों का हाथ माना जा रहा है, जिन्हें ओसामा बिन लादेन का समर्थन हासिल है. इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इवान बारबालिक ने कहा कि हर तरह का आतंकवाद, चाहे वह कोई भी शक्ल या आकार लिए हो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर ख़तरों में से एक है. अब देखना यह है कि देश में शांति के लिए चेचेन विद्रोहियों को रूस किस तरह साधता है, ताकि उनका आक्रोश कम हो सके और वे रूस के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

कलयुग के इस दौर में जीवन को मजबूरी मानकर लोग कई तरह के समझौते करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी अंर्तात्मा की आवाज़ को यह कहकर समझा लेते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था.

साई बाबा मेरे पथ प्रदर्शक

ऑसिम खेत्रपाल

मेरा जीवन आप सबके सामने एक खुली किताब की तरह है. मैं एक स्पोर्ट्स प्रमोटर रहा, एक्टर रहा हूं, फिल्म मेकर हूं और एक बिजनेसमैन भी रहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख़ासियत या कहें कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद महसूस तब होता था, जब मैं किसी इवेंट या ख़ास व्यक्ति को प्रमोट करता था. मुझे युवा प्रतिभाओं पर काम करके उन्हें उनके मुक़ाम तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा ख़ुशी मिलती थी. हमारी स्पोर्ट्स अकादमी से कई विश्वस्तरीय खिलाड़ी निकले हैं, जो आज भी खेल जगत में अपना नाम कमा रहे हैं. बाबा के साथ जब रिश्ता जुड़ा और उनका आदेश मिला कि मेरा काम कर, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या काम करूं. अब किसी सद्‌गुरु या फिर कहें आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए मैं अदना सा बिज़नेसमैन क्या कर सकता हूं, समझ नहीं पाया. फिर जब बार-बार मेरे सामने बाबा के कहे वही शब्द आए कि तू मेरा बेटा है, तुझे मेरा काम करना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि बाबा का काम आख़िर है क्या? प्रचार-प्रसार के इस युग में एक ही बात मैंने सीखी थी कि जो बात बार-बार सुनी जाए या जिसका चित्र बार-बार सामने आए, वही हमारे मन-बुद्धि पर ज़्यादा देर तक असर करती है और हमारे विचारों पर उसका गहरा असर पड़ता है. मैंने बाबा के चरित्र को जब देखा और जाना तो मैंने समझा कि बाबा अपने जीवनकाल में दो महत्वपूर्ण कार्य करने आए थे. दर्द से तड़पती आत्माओं को सुख देने और श्रद्धा एवं सबूरी का पाठ पढ़ाने. दूसरी तरफ़ परमात्मा के नाम पर यह फकीर लगातार एक ही रट लगाता रहा, सबका मालिक एक.

बाबा के जीवन को देखो तो ऐसा नहीं था कि वह अपने भक्तों या शिष्यों को उनकी मुश्किल ठीक कर ऐसे ही छोड़ देते थे, बल्कि एक बार भी जिसने बाबा के साथ का अनुभव किया, वह जीवन भर के लिए बाबा का होकर रह गया. बाबा ने भी जीवन भर अपने हर भक्त का हर पल साथ निभाया. चाहे स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में. मज़े की बात तो यह है कि अगर कोई भक्त कहीं ग़लती करने जा रहा होता था तो बाबा हर बार उसे आगाह कर देते, क्योंकि बाबा जानते थे कि इस जीवन में किए हर बुरे कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा. जिसने बाबा का हाथ पकड़ा, उसे बाबा ने न सिर्फ़ हर मुश्किल से आगाह किया, बल्कि सच के रास्ते पर चलने की शक्ति भी दी. कलयुग के इस दौर में जीवन को मजबूरी मानकर लोग कई तरह के समझौते करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी अंर्तात्मा की आवाज़ को यह कहकर समझा लेते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था. बिज़नेस चलाने के लिए यह सब करना ही पड़ेगा, इसके बिना घर नहीं चल सकता, इतना झूठ तो चलता है, थोड़ी-बहुत बेईमानी, बेईमानी नहीं होती और इंसान हैं तो इतना समझौता करना ही पड़ेगा आदि जैसी बातों के आधार पर लोग समझौते कर लेते हैं.

मैं भी आम लोगों की तरह ऐसे ही जी रहा था. बाबा का मेरे जीवन में पर्दापण मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया. मुझे दिखने लगा. मैं झूठ बोल देता था, मुझे समझ आया कि छोटी-छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता था. अपने अहम के कारण दूसरों की बात बुरी लग जाती थी और मन करता था कि मैं भी बदला लूं. लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने बाबा के प्यार को महसूस किया और जाना, उनकी ताक़त मुझे भरने लगी, मैं कम दुखी होने लगा. मैं प्रशंसा और बुराई दोनों से परे होने लगा. हर नाकामी एक अवसर लगने लगी. सच को सच कहने की हिम्मत आने लगी. हालांकि स्व:परिवर्तन की यह यात्रा अभी लंबी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा के पथ प्रदर्शन में अपनी असली पहचान पा सकूंगा. कहते हैं कि उसके नूर से रोशन ज़र्रा भी आफ़ताब हो जाता है.

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

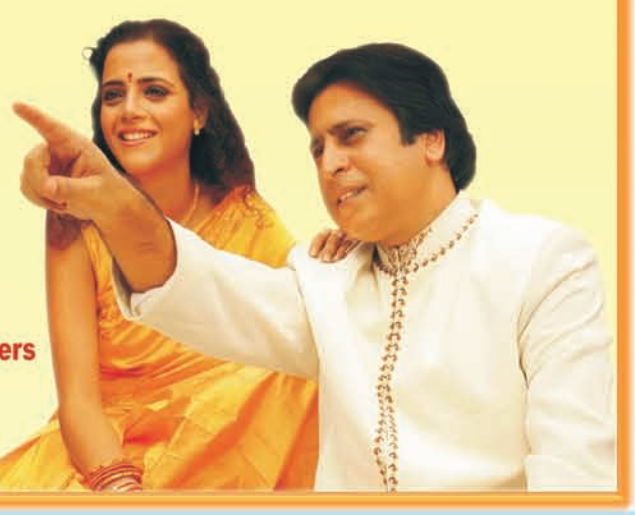

AUM Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

साई की महिमा के इस अंक में हम आपके लिए एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं. इसमें हम आपसे बाबा के जीवन से जुड़ी पहेली पूछेंगे.

इस बार की पहेली साई सच्चरित्र के 9वें अध्याय से जुड़ी है. आपको हमें उस भक्त का नाम बताना है, जिसने एक बार साई बाबा की आज्ञा की अवहेलना की थी.

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

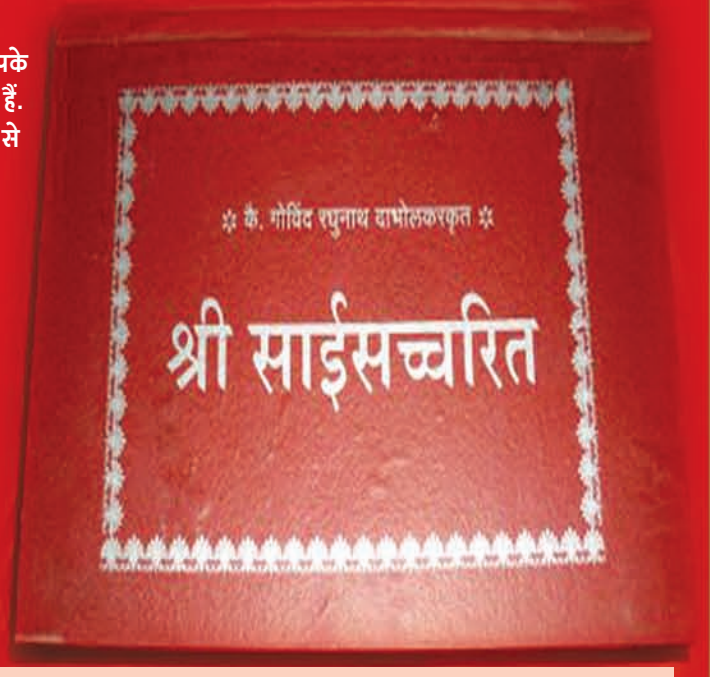

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब **info@ssbf.in** भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

श्री सद्‌गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

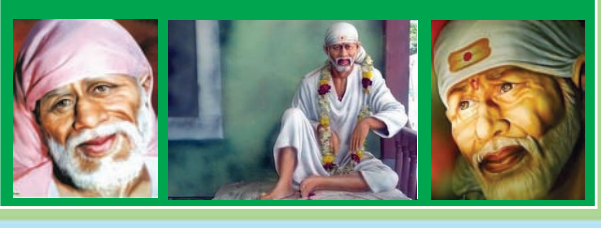

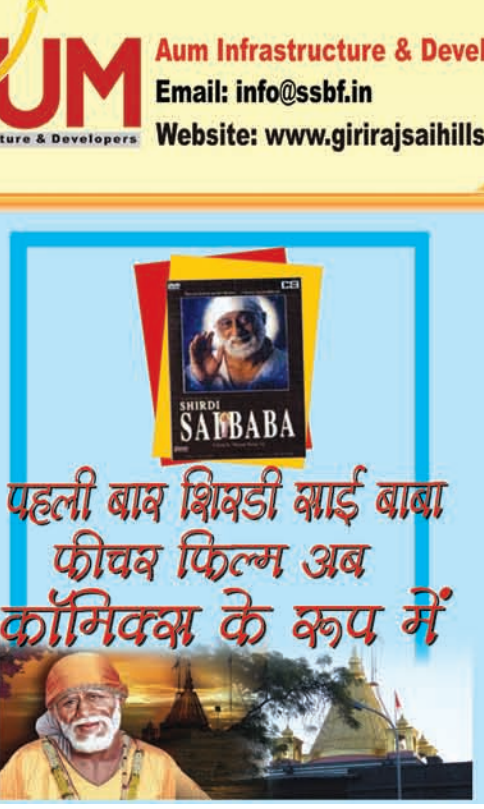

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

तट है, तटस्थ नहीं

अनंत विजय

रामचंद्र गुहा आज़ाद भारत के ऐसे इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास लेखन को मार्क्सवादी ढर्रे से मुक्त कराकर उसे लोकप्रिय बनाया. उनकी शैली शास्त्रीय इतिहास लेखन से बिल्कुल अलग हटकर है, जिसे इतिहास के विद्यार्थियों के अलावा आम पाठकों ने भी सराहा है. जब रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी प्रकाशित हुई तो स्तर पर उसकी सराहना हुई. उस वक़्त कई अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं ने उसे बुक ऑफ द ईयर कहा था, जिनमें प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट प्रमुख हैं. दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के अलावा गुहा ने बंगलुरू के मशहूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी पढ़ाया है. फ़िलहाल वह स्वतंत्र लेखन के अलावा अख़बारों में स्तंभ लेखन करते हैं. इंडिया आफ्टर गांधी के बाद रामचंद्र गुहा ने जब अपनी नई किताब का ऐलान किया था, तभी से इस किताब की प्रतीक्षा हो रही थी. अपनी इस नई किताब-मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में उन्होंने उन्नीस भारतीय नेताओं के बारे में लिखा है और उनके विचारों को संग्रहित भी किया है. गुहा के मुताबिक़, उन्होंने उन महिला और पुरुष नेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं या समाज सुधारकों को अपनी इस किताब में जगह दी, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्रोत्तर भारत को अपने लेखन और भाषण से गहरे तक प्रभावित किया. लेखक के मुताबिक़, ये उन्नीस भारतीय लोग सिर्फ़ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने लेखन से भी देश और समाज को एक नई दिशा दी. इस किताब में पांच खंड हैं. पहले खंड में राजा राम मोहन राय और विभिन्न विषयों पर उनकी राय को संकलित किया गया है. यह किताब राजा राममोहन राय से शुरू होती है, जो लेखक के मुताबिक़ पहले भारतीय विचारक थे, जिन्होंने पश्चिम की चुनौतियों को बेहद गंभीरतापूर्वक लिया. एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पहले ऐसे विचारक थे, जिन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष का बिगुल फूंका था.

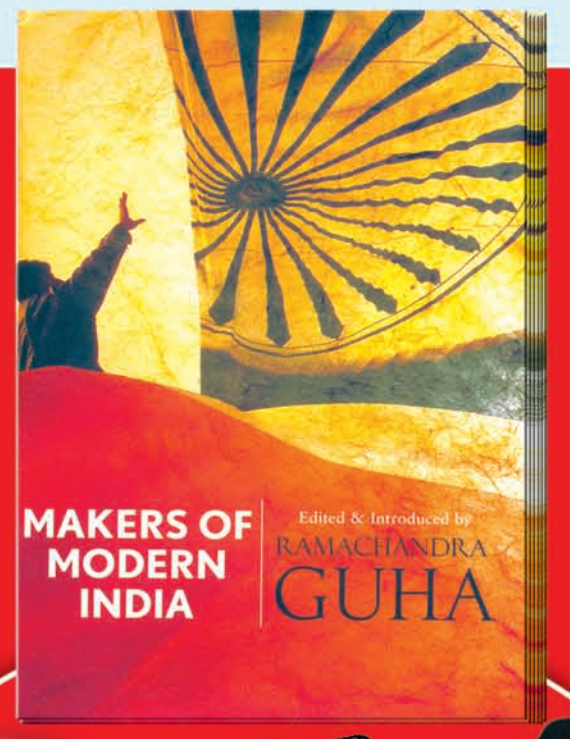

समीक्ष्य कृति-मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया
संपादक-रामचंद्र गुहा
प्रकाशक-पेंग्विन बुक्स, नई दिल्ली
मूल्य-799 रुपये

किताब के दूसरे खंड में जिन पांच लोगों, सैयद अहमद ख़ान, ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और ताराबाई शिंदे के बारे में लिखा गया है या जिनके अहम विचार संकलित किए गए हैं, उनमें से दो लोग लंबे समय से कांग्रेस के सदस्य रहे थे और उसी विचारधारा में जीते-मरते थे, जबकि दूसरे दो लोग उस कांग्रेसी विचारधारा के ख़िलाफ़ थे. तीसरा खंड मोटे तौर पर महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन के इर्द-गिर्द हुई बहसों पर केंद्रित है. गांधी के बारे में गुहा लिखते हैं कि अपने जीवनकाल में ही गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त हो गया था, लेकिन साथ ही वह उन सारे विवादों की जननी भी थे, जो देश के भविष्य को लेकर उस वक़्त चले थे. गांधी का जीवन जिस तरह आम जनता के लिए एक खुली किताब था और उनके आचरण को लेकर जो विवाद था, वैसा किसी दूसरे नेता को लेकर अब तक नहीं देखा गया. गांधी के बाद रामचंद्र गुहा भारतीय गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक समय का सबसे विचारवान राजनेता मानते हैं. उनके मुताबिक़, विंस्टन चर्चिल भी नेहरू जैसे विचारशील राजनेता नहीं थे. अपने देश के इतिहास में नेहरू की बेहद रुचि थी, साथ ही राजनीतिक विचारधारा, नए विचारों और आइडियाज में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उन्हें विश्व राजनीति के पटल पर चर्चिल से अलग खड़ा करती थी. इसके अलावा गुहा ने रवींद्र नाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एवं एम एस गोलवलकर आदि के बारे में भी अपनी राय रखी है. लेकिन इस किताब में आधुनिक भारत के तीन अहम किरदारों सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल और इंदिरा गांधी को न चुनना चौंकाने वाला है. इसके लिए लेखक के अपने तर्क हैं. उनका कहना है कि इस किताब में उन्हीं लोगों को जगह मिली, जिनके पास अपने विचार थे. ऐसे विचार, जो न सिर्फ़ मौलिक थे, बल्कि समाज को प्रभावित करने वाले भी थे.

गुहा के मुताबिक़, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान नेता थे, जिन्होंने तीस और चालीस के दशक में भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रेरित किया. ठीक उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकसूत्र में बांधने और उसे एक राष्ट्र का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. लेकिन लेखक के मुताबिक़, दोनों के पास मौलिक विचारों का अभाव था. हालांकि पटेल हमेशा यह कहा करते थे कि वह इतिहास लेखन से ज़्यादा इतिहास बनाने में यक़ीन करते हैं. इसी तरह तक़रीबन डेढ़ दशक तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी को भी मेकर्स ऑफ इंडिया में शुमार न किए जाने पर लेखक का तर्क है कि उन्होंने मौलिक कुछ नहीं लिखा. यहां तक कि उनके पिता जवाहर लाल नेहरू के विपरीत उनका भाषण भी कोई और ही लिखता था. इन तीन शख्सियतों को अपनी किताब में शामिल न किए जाने पर आलोचकों ने रामचंद्र गुहा को कठघरे में खड़ा किया, लेकिन मुझे लगता है कि लेखक को इतनी छूट तो होनी ही चाहिए कि वह जिसे चाहे, अपनी रचना में शामिल करे और उसके लिए उसके अपने तर्क हों. आलोचना इस बात पर की जा सकती है कि लेखक ने चुनाव के जो मानदंड रखे हैं, उन्हें वह ख़ुद पर सही तरीक़े से लागू कर पाते हैं या नहीं अथवा उसमें वस्तुनिष्ठ हो पाते हैं या नहीं. गुहा ने लिखा है कि भारत एक बेहद मजेदार देश है. मजेदार वह इसलिए नहीं है कि उसकी जनसंख्या विशाल है, मजेदार वह अपनी विविधताओं को लेकर भी नहीं है. मजेदार इसलिए है कि यहां एक साथ पांच सामाजिक बदलाव घटित हो रहे थे-शहरी विकास के क्षेत्र में क्रांति, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रीय क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति और सामाजिक क्रांति.

लेखक के मुताबिक़, इस किताब में उन्हीं महिलाओं और पुरुषों का चयन किया गया है, जिन्होंने इन पांच क्रांतियों में न केवल अपनी भूमिका का निर्वाह किया, बल्कि उसे अपने विचारों और लेखन से एक दिशा भी दी. लेकिन लेखक के इन्हीं तर्कों के आधार पर देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस किताब में विस्मरण विस्मित करने वाला है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न केवल विपुल मौलिक लेखन किया है, बल्कि अपने लेखन से तत्कालीन समाज पर अमिट छाप भी छोड़ी. उनके लेखन में, हम यह कह सकते हैं कि समाज सुधार के अलावा शिक्षा पर भी खासा जोर दिया गया है. लेकिन लगता है कि जिस तरह राजेंद्र प्रसाद को उनकी मौत के बाद साजिशन पूरे देश ने भुला दिया, रामचंद्र गुहा भी उसके शिकार हो गए हैं. राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान निर्माता का दर्जा भीमराव अंबेडकर को प्राप्त है, यह भी एक शोध का विषय हो सकता है. इसके अलावा गुहा ने कुछ ऐसे चिंतकों को शामिल कर उनसे हमारा परिचय कराया है, जो लगभग विस्मृत हो चुके थे, जैसे ताराबाई शिंदे और हामिद दलवई. इसके अलावा गुहा का दावा है कि उनकी इस किताब में जिस चिंतक राजनेता की एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, वह अब लगभग मृतप्राय: है.

गुहा के मुताबिक़, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान नेता थे, जिन्होंने तीस और चालीस के दशक में भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रेरित किया. ठीक उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकसूत्र में बांधने और उसे एक राष्ट्र का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. लेकिन लेखक के मुताबिक़, दोनों केपास मौलिक विचारों का अभाव था.

लेखक के मुताबिक़, अभी के परिदृश्य में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है, जो अपने चिंतन और मौलिक लेखन से भारतीय समाज को प्रभावित कर सके या फिर यह समझ सके कि समाज और राजनीति में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है.

किताब में गुहा ने सभी विचारधाराओं के लोगों को जगह दी है. एक तरफ़ सैयद अहमद ख़ान हैं, हामिद दलवई हैं तो दूसरी तरफ़ महादेव सदाशिव गोलवलकर हैं. 1960 में मुस्लिम समाज की समस्याओं को लेकर हामिद दलवई की जो चिंता दिखाई देती है, उनसे आज भी भारत का मुस्लिम समाज टकरा रहा है. दलवई के मुताबिक़, जो रूढ़िवादी हिंदू भारत में गाय के वध पर पाबंदी की बात करते हैं और जो सांप्रदायिक मुसलमान अपने समाज में आधुनिकता का विरोध करते हैं, दोनों के मक़सद समान हैं. इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक समुदाय में आधुनिकता का विरोध दूसरे समुदाय में भी आधुनिकता की प्रक्रिया पर वैसा ही प्रभाव डालता है. इस वजह से हमें भारत के नागरिकों के लिए एक समान क़ानून पर जोर देना चाहिए. दूसरी तरफ़ 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान संभालने वाले गोलवलकर के उग्र विचार हैं, जो हिंदू राष्ट्र की राह में मुस्लिमों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं. इसमेंगोलवलकर के जो भाषण संकलित हैं, वे कुछ दिनों पहले पीलीभीत में दिए गए वरुण गांधी के भाषण की याद दिलाते हैं. इन चिंतक राजनेताओं में गुहा ने संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को शिद्दत से याद किया है. जयप्रकाश नारायण को देश के लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक अहम किरदार के रूप में तो जानते ही थे, लेकिन 1974 से शुरू हुए इंदिरा गद्दी छोड़ो आंदोलन ने उन्हें देश की दूसरी आज़ादी का लोकनायक बना दिया. जयप्रकाश नारायण ने 1959 में ही एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था का खाका खींचा था. देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से चिंतित जेपी ने उस पर लगाम लगाने के लिए सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी की वकालत की थी. उनका मानना था कि सरकारी अफसरों पर जनता का सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सीधा नियंत्रण रहे और वे उसकी निगरानी में काम करें, ताकि काम बेहतर हो और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो.

किताब की एक अहम बात यह है कि रामचंद्र गुहा ने इतिहास को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है. इतिहास का विद्यार्थी होने की वजह से मुझे ए एल बैशम से लेकर रामशरण शर्मा, डी एन झा, बिपान चंद्रा और रोमिला थापर तक की किताबें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यह कह सकता हूं कि जितनी रोचकता और पठनीयता रामचंद्र गुहा की किताब में है, उतनी इन लेखकों की किताबों में नहीं है. हालांकि इस किताब में रामचंद्र गुहा का अपना लेखन बेहद कम है, लेकिन जिस तरह उन्होंने नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लेखन को संकलित किया है, वह बेहद श्रमसाध्य काम है. राममोहन राय से लेकर जयप्रकाश नारायण तक एक बहुत लंबा यानी तक़रीबन सौ साल का वक़्त है, जिसमें से उनके चुनिंदा भाषण और लेखन को संकलित कर गुहा ने भारत के इतिहास को उसके नेताओं और समाज सुधारकों के नज़रिए से पेश किया. गुहा की इस किताब में मेकर्स के चयन पर विवाद हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि साल 2010 में प्रकाशित यह किताब भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद अहम है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कंपनी ने इसे बजट क्वर्टी की-पैड फोन की कैटेगरी में लांच किया है. इस हैंडसेट की क़ीमत 4459 रुपये है.

लाजवाब कैमरा

जापानी कंपनी कैसियो ने एक्सिलिम की विशाल रेंज को और विस्तार देते हुए प्रीमियम ऑटो तकनीक वाला एक्सिलिम जेड-800 कैमरा लांच किया है. एक्सिलिम जेड-800 में इस्तेमाल प्रीमियम ऑटो तकनीक के कारण इसमें क़रीब एक लाख कलर कॉम्बिनेशन को परखने की क्षमता है, जिससे हमेशा बेहतरीन तस्वीर आती है. कैमरा अपने आप ब्राइटनेस चेक करके ज़रूरत के मुताबिक़ कलर कॉम्बिनेशन में फोटो लेता है. यह एक्सपोजर, आईएसओ, सेंसिटिविटी, फोकस लोकेशन, फोटो ब्लर करेक्शन, टोनल रेंज, कलर बैलेंस, न्वॉयज रिडक्शन लेवल अपने आप एडजस्ट कर लेता है. इस कैमरे में कैसियो का अपना डायनामिक फोटो फंक्शन भी मौजूद है. इसके ज़रिए मोशन में फोटो लेना आसान है. इस तरह न केवल खेल-खेल में तस्वीरें तैयार हो जाती हैं, बल्कि यू-ट्यूब पर अपलोडिंग के ज़रिए पिक्चर शेयर करना या ब्लॉग पर डालना भी एकदम आसान हो जाता है. सिंगल फ्रेम एसआर जूम ऑप्टिकल जूम की टेलीफोटो रेंज अधिकतम कर देता है. इस कैमरे में सुपर रिज़ॉल्यूशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तस्वीर बड़ी करते समय एजेज, फ्लैट एरिया और टेक्सचर ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं. सिंगल फ्रेम एसआर जूम ऑप्टिकल जूम की टेलीफोटो रेंज 1.5 गुना तक बढ़ा देता है. साथ ही तस्वीर की क्वालिटी ख़राब होने का ख़तरा भी ख़त्म कर देता है. एक्सिलिम इंजन 5.0 में आर्ट शॉट फंक्शन इमेज प्रॉसेसिंग तकनीक खींची हुई फोटो में ऑयल पेंटिंग, क्रेयॉन या वाटर कलर का एहसास कराती है. ऑर्ट इफेक्ट फंक्शन से सेव की हुई तस्वीरों में भी इसी तरह का लुक लाया जा सकता है. एक्सिलिम जेड-800 में हाई स्पीड फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए इनबिल्ट इंजन 5.0 है, जो कई सीपीयू को सपोर्ट करता है. ईएक्स-जेड 800 छह अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है यानी बेसिक काला, सिल्वर, गुलाबी, लाल, पीला और नीला. कैमरे में 4-एक्स ऑप्टिकल जूम लेंस लगा है, जो 27 एमएम वाइड एंगल व्यू 35 एमएम फिल्म कैमरे के बराबर शुरू होकर 14.1 मेगा पिक्सल रिज़ॉल्यूशन तक जा सकता है. कैसियो एक्सिलिम जेड-800 सिर्फ़ 9,495 रुपये में उपलब्ध है.

जेट सेट घड़ियों की नई रेंज

ख़ूबसूरत घड़ियां भला किसे नहीं भाती हैं. ख़ूबसूरत कुड़ियों की नाज़ुक कलाइयों की शोभा बढ़ाने के लिए बाज़ार में स्टाइलिश घड़ियों की कई वैरायटी मौजूद हैं. लक्जरी ब्रांड लिवटेक ने लेडीज घड़ियों की एक नई रेंज बाज़ार में उतारी है. इस खास रेंज में कंपनी ने नया और वाइब्रेंट कलेक्शन लांच किया है. दो साल की इंटरनेशनल वारंटी के साथ ये घड़ियां कुशल कारीगरों द्धारा तैयार की जाती हैं. नए फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस कलेक्शन की सभी घड़ियों में फ्रेंच फैशन स्टेटमेंट डाला गया है. इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट असेंबली यूनिट्स और लेजर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है. घड़ियों के निर्माण में यह तकनीक बिल्कुल नई है. कंपनी द्धारा उतारी गई इस खास रेंज में ग्लैम एंड द सिटी नामक कलेक्शन मेटल बेस है. इस कलेक्शन की घड़ियों की क़ीमत 18 हज़ार से लेकर 20 हज़ार रुपये तक है. ये वाटर रेसिसटेंट हैं और पर्ल, व्हाइट और ब्लैक स्ट्रैप्स के साथ आती हैं. इस रेंज के फ्लावर कलेक्शन में घड़ियों के स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप पर गढ़े हुए फूलों का डिज़ाइन है. इस कलेक्शन की घड़ियों की क़ीमत 21 हज़ार से लेकर 23 हज़ार रुपये तक है. पीयरे लैनिएर फैशन वॉचेज जहां कॉकटेल पार्टीज में पहनने के लिए उपयुक्त हैं, वहीं दफ्तर जाने के लिए भी. इसके साथ ही जेट सेट लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाली महिलाओं के लिए भी ये बेस्ट हैं. लिवटेक की पीयरे लैनिएर फैशन वॉचेज यूरोप, यूके, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, हालैंड, बेल्जियम, रूस, फ्रांस और जापान सहित विश्व के 40 देशों में तकरीबन 15 मिलियन घड़ियों का कारोबार प्रतिवर्ष करती है.

नोकिया का नया हैंडसेट

फिनलैंड की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया ने भारतीय बाज़ार में अपना एक और बेहतरीन हैंडसेट लांच कर दिया है, जिसका नाम है नोकिया एक्स 2-01. कंपनी ने इसे बजट क्वर्टी की-पैड फोन की कैटेगरी में लांच किया है. इस हैंडसेट की क़ीमत 4459 रुपये है. कंपनी का कहना है कि कम क़ीमत के बावजूद ग्राहकों को इसमें कई ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे, जो अक्सर महंगे स्मार्ट फोन में ही देखने को मिलते हैं. कम क़ीमत पर लोग बेहतरीन फीचर्स वाले फोन लेना चाहते हैं. इस फोन में सिंबायन एस-40 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही इसमें क्वर्टी की-पैड, 2.4 इंच डिस्प्ले, यूएसबी, 2.0 कनेक्टिविटी, ब्लुटूथ 2.1, 8 जीबी तक एक्सपेंडेबल मेमोरी, म्यूज़िक प्लेयर, स्टीरियो, एफएम रेडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इस पर आप ओवीआई मेल, याहू मेल, जी मेल, विंडोज लाइव और हॉटमेल जैसी सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे. कंपनी का दावा है कि कम क़ीमत में बेहतरीन फीचर्स के चलते भारतीय ग्राहकों को यह नया हैंडसेट काफी पसंद आएगा.

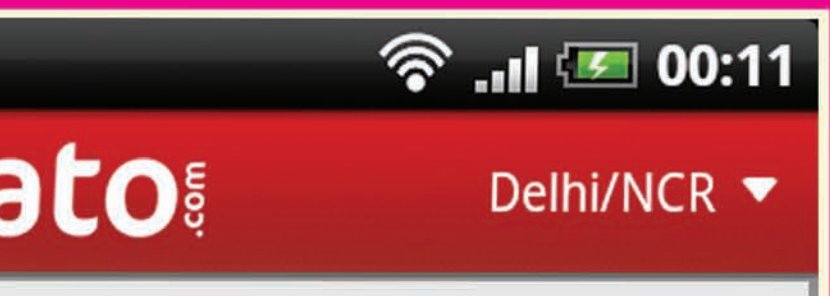

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फोन पर ख़ास एप्लीकेशन

पहले फूडीबे डॉट कॉम के नाम से जाना जाने वाला यह जोमैटो डॉट कॉम ऑनलाइन फूड गाइड और रेस्टोरेंट डायरेक्ट्री है. एंड्रॉयड फोन पर इस तरह का एप्लीकेशन देश का पहला लोकल सर्च एप्लीकेशन है.

पढ़ाई को सफ़ल तभी कहेंगे, जब उससे मिलने वाले ज्ञान का इस्तेमाल समाज में अच्छे कार्यों या जीवन को सुलभ बनाने के लिए किया जाए. देश के शीर्ष तकनीकी संस्थान आईआईटी में पढ़ने वाले दीपेंद्र गोयल एवं पंकज चड्ढा ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों का जीवन सुलभ बनाने के लिए किया है. दरअसल, मोबाइल आज के दौर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट है. मोबाइल पर ही कुछ ख़ास एप्लीकेशन डेवलप करके इन छात्रों ने एक अच्छा काम किया है. इन्होंने फूडीबे डॉट कॉम नामक बेवसाइट बनाई, जो ऑनलाइन फूड गाइड और रेस्टोरेंट डायरेक्ट्री है. अब मोबाइल फोन को लेकर लोगों की बढ़ती उम्मीदों की वजह से जोमैटो डॉट कॉम ने एंड्रॉयड फोन के लिए नया एप्लीकेशन लांच किया है.

पहले फूडीबे डॉट कॉम के नाम से जाना जाने वाला यह जोमैटो डॉट कॉम ऑनलाइन फूड गाइड और रेस्टोरेंट डायरेक्ट्री है. एंड्रॉयड फोन पर इस तरह का एप्लीकेशन देश का पहला लोकल सर्च एप्लीकेशन है. यह यूजर्स को उसके लोकेशन के पास के रेस्टोरेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देता है. एंड्रॉयड मार्केट में यह मुफ्त उपलब्ध है. इस एप्लीकेशन में वेबसाइट के सभी फीचर्स हैं, जिनके ज़रिए रेस्टोरेंट के मेन्यू, कांटेक्ट डिटेल्स, रीव्यू, फोटोग्राफ, लोकेशन और डिस्काउंट भी फोन पर ही आ जाते हैं. जोमैटो डॉट कॉम ऑनलाइन फूड गाइड और रेस्टोरेंट डायरेक्ट्री में 6 शहरों के 10,200 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है. ये शहर हैं दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता और पुणे.

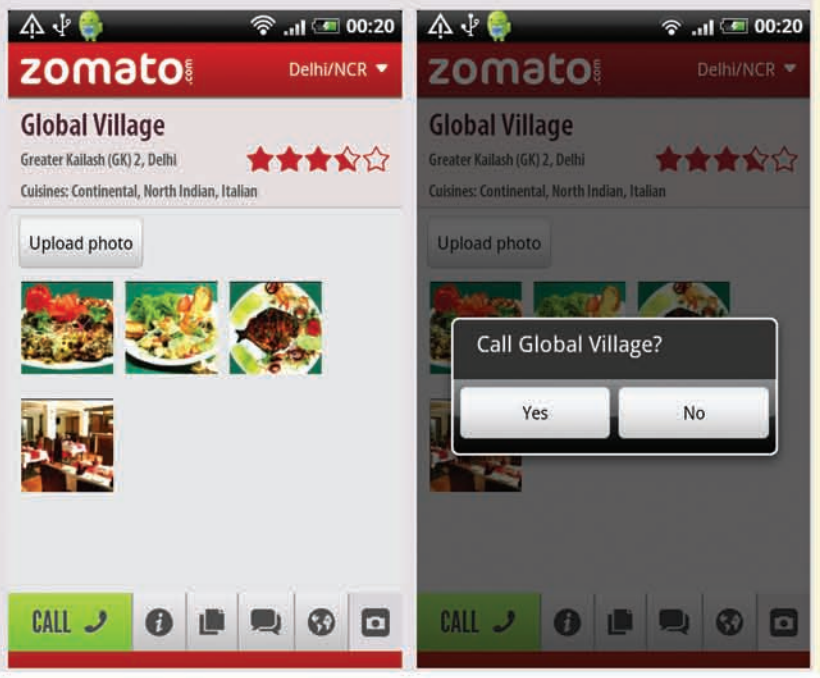

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ईडन गार्डन
अधूरी तैयारी ने तोड़ दिया सपना

राजेश एस. कुमार

एक बार श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान मरवन अटापट्टू ने नौकरशाही के ख़िलाफ़ कहा था कि ये सारे जोकर हैं. इन जोकरों का सरदार एक बड़ा जोकर है. यदि इस बात को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा. जिस तरीक़े से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और उसके अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने ईडन गार्डन, जो कि भारत में क्रिकेट का मक्का कहा जा सकता है, को शर्मसार किया है वो निश्चित ही जोकरों का सरदार होगा. कोलकाता के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरे विश्व में क्रिकेट को चाहने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से नाराज़ हैं. याद रखने वाली बात यह है कि इससे पहले ईडन गार्डन भारत का सबसे विश्वसनीय स्टेडियम था. पूर्व में भी ईडन गार्डन में विश्व कप के बड़े–बड़े मैच आयोजित हो चुके हैं.

यह पहली बार होगा कि भारतीय टीम अपने सबसे चहेते क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं खेलेगी. 1987 वर्ल्ड कप का फाइनल और 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी ईडन गार्डन में ही हुआ था. लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन का मैदान सूना ही रहेगा.आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हारून लोर्गट ने कहा कि ईडन की असफलता दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करता रहा है फिर भी वर्ल्ड कप के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच 27 फरवरी खेले जाने वाले मैच को स्थगित कर दिया गया था. लोर्गट ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को ईमेल भेज कर कहा कि मैं भी उतना ही निराश हूं कि ईडन गार्डन में मैच आयोजित नहीं हो पायेगा, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, यह मेरे हाथो में नहीं है. यह सब तकनीकी समिति का फ़ैसला है. मैं जल्दी ही आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि जो भी गलतफ़हमियां है, वो जल्द ही दूर हो जाएं.

इस फ़ैसले से न सिर्फ़ क्रिकेट खिलाड़ी बल्कि सभी क्रिकेट प्रेमी, अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ी भी आहत हैं. ईडन गार्डन सिडनी और लॉर्डस जैसा है. इंग्लैंड के लिए जो लॉर्डस के लिए स्थान है वही ईडन गार्डन का महत्व भारत के लिए है. खाली क्रिकेटर ही नहीं पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और फुटबॉल से जुड़े लोग भी भारत में हो रहे खेल आयोजनों के साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है. आख़िर भारत को लंदन से कुछ सीख लेनी चाहिए. लंदन में होने वाले ओलंपिक खेल 2012 में शुरु होंगे, उसके आज सभी स्टेडियम तैयार हो चुके हैं.

लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों? आख़िर मैच क्यों रद्द करना पड़ा? कारण बताया गया कि स्टेडियम की तैयारी तय समय पर पूरी नहीं हो सकी थी. आईसीसी के जांच दल के विशेष अधिकारी प्रो. यूजिन वान वूरेन ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को साफ़ शब्दों में कहा कि 27 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच को ईडन गार्डन की इस स्थिति को देखते हुए बिल्कुल नहीं कराया जा सकता. आईसीसी के इस फ़ैसले के बाद वही हुआ जो भारत में होता आया है. एक दूसरे पर छींटाकशी और अपनी नाक़ाबलियत को दूसरों के सर मढ़ने का खेल शुरु हो गया. आख़िर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या सोचा कि ईडन गार्डन की कीर्ति को वे भुना लेंगे. उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इतने गंदे रखरखाव के बाद भी आईसीसी वहां मैच की इजाज़त दे देगा. मामला यह है कि कहीं बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट में हमेशा चलने वाली राजनीति ने तो कहीं ईडन गार्डन पर धब्बा नहीं लगा दिया. क्या इस बार भी वही हुआ जो राष्ट्रमंडल खेल के दौरान हुआ था. क्या यहां भी घूसखोरी और भ्रष्टाचार का खेल खेला गया. जब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने तीन बार स्टेडियम को तैयार करने की अंतिम समय सीमा लांघ दी तो फिर जगमोहन डालमिया की सारी अपील और दलील खोखली साबित होती हैं. कुछ लोगों का मानना है कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पास ईडन गार्डन को तैयार करने की कोई रणनीति ही नहीं थी. जब उन्हें पुनर्निमाण चरणों में करना चाहिए था तो उन्होंने सारे काम एक साथ करने का मूर्खतापूर्ण फ़ैसला क्यों लिया?

लेकिन, इंटरनेशनल क्रिकेट कांउसिल यानी आईसीसी को भी पूरी तरह बरी नहीं किया जा सकता. आईसीसी को पता था कि बहुत सारे स्टेडियमों को ठीक करना था. ये आईसीसी की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन सारे निर्माण कार्यों को लगातार अपनी नज़र में रखता और अपना अंतिम निर्णय होने वाले प्रथम मैच के एक महीने पहले ही बता देता. आदर्श स्थिति तो यह होती कि आईसीसी सारे कार्यों और योजनाओं की समीक्षा और अध्ययन करता और एसोसिएशन को अपने हिसाब से सलाह देता. क्योंकि आईसीसी के पास हर मामले के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने बड़े–बड़े स्टेडियमों का निर्माण करवाया था. वो चाहते तो तैयारियों का मूल्यांकन भी कर सकते थे.

आईसीसी को अपनी तकनीकी टीम को स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन को मदद देने की सोचनी चाहिए थी. क्या आईसीसी ने ईडन गार्डन के निर्माण कार्य को इससे पहले समय रहते देखने का प्रयास किया था. हुआ यह कि थोड़ा–थोड़ा करके सारा काम इकट्ठा होता गया और अंत में काम इतना बढ़ गया कि सारी एजेंसियां और जो भी लोग ईडन गार्डन के रखरखाव से जुड़े थे, आपस में समन्वय नहीं बैठा पाए और एक बार फिर विश्व पटल पर भारत की किरकिरी हो गई. सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ईडन गार्डन ही खस्ता हाल में नहीं है बल्कि वानखेड़े स्टेडियम की भी कुछ यही कहानी है. यहां भी वही ग़लतियां की गई हैं जो ईडन गार्डन में हुई. सबसे चौकाने वाली बात यह है कि ईडन गार्डन के नए स्टेडियम में पहले से 20 हज़ार सीटें कम हो गई होंगी. वानखेड़े स्टेडियम में ये कमी 5 हज़ार की है. सवाल यह है कि जब आईसीसी का किसी भी बात पर कोई नियंत्रण नहीं है तो इतने बड़े आयोजन कराने की ज़रूरत क्या है? शर्मनाक बात यह भी है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष भारत के ही कृषि मंत्री शरद पवार हैं और बंगाल एसोसिएशन क्रिकेट के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया हैं, जो कि पूर्व आईसीसी अध्यक्ष हैं. याद रखने की बात यह है कि यह खेल भारत में क्रिकेट के साथ पहली बार नहीं हुआ है. पहले भी ख़राब पिचों और अधिकारियों का नकारापन सामने आता रहा है. लेकिन इस सबसे कभी भी कोई सबक नहीं लिया गया. दिसंबर 2009 में ऐसा ही कुछ फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान, दिल्ली के साथ हुआ था. भारत और श्रीलंका का मैच पिच के ख़तरनाक तरीक़े से उछाल लेने की वजह से रद्द करना पड़ा था. जो लोग इस पिच को बनाने के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने ग़ैर पेशेवर और ग़ैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से सारा काम किया था.

भारत को खेल जगत में अपनी किरकिरी कराने का ख़ासा अनुभव हो चुका है. अभी राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार से उठी बदबू दबी भी नहीं थी कि क्रिकेट जगत की सड़ांध लोगों के सामने आ गई. क्या वाकई क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ ही समय पहले जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी चल रही थी तब भी यही सब तमाशा हुआ था. अंतरराष्ट्रीय जांच दल ने कहा कि स्टेडियम का काम पूरा नहीं है और संभव है कि खेलों का आयोजन स्थगित हो जाए. हालांकि, जैसे–तैसे काम पूरा हुआ. खेल का आयोजन भी हुआ. खेल से पहले और खेल के बाद भी राष्ट्रमंडल आयोजन समिति का भ्रष्टाचार देश के सामने निकल कर आया. क्या क्रिकेट जगत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है?

rajeshy@chauthiduniya.com

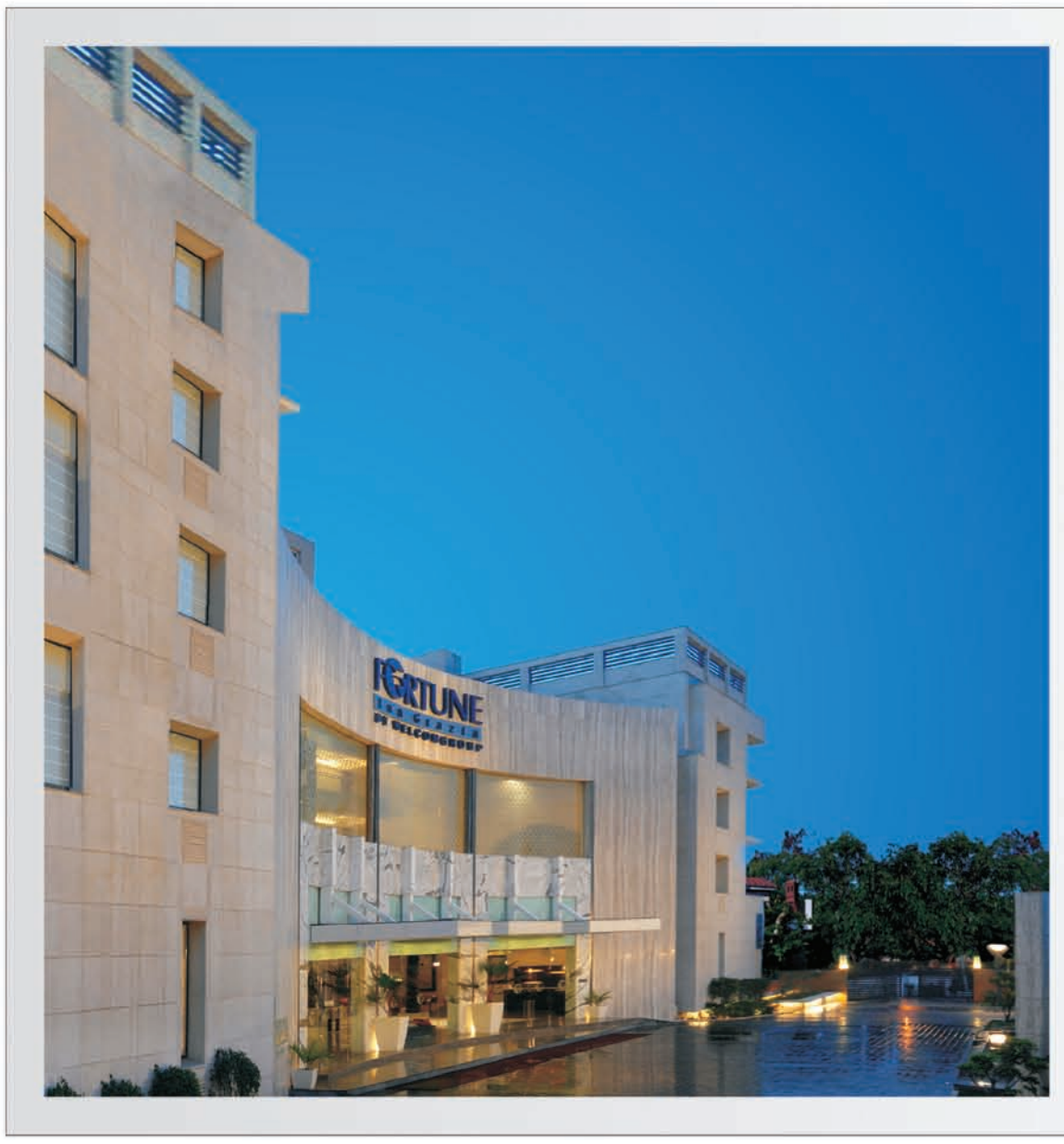

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida, an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

FORTUNE
Inn Grazia
BY WELCOMGROUP
Noida

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India
Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144
E-mail: grazia@fortunehotels.in Website: www.fortunehotels.in

CRAYONS

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 फरवरी–20 फरवरी 2011

याद करें, दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म ओम शांति ओम से लेकर अब तक उनके हेयर स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया.

चित्रांगदा की पसंद

स्मिता पाटिल की याद दिलाने वाली चित्रांगदा सिंह की बहुचर्चित फिल्म ये साली ज़िंदगी काफी विवादों में घिरने के बाद भी थिएटर तक पहुंच ही गई. अलग तरह के किरदारों में दिलचस्पी रखने वाली चित्रांगदा शबाना आज़मी को पसंद करती हैं, वह उन्हें अपना आदर्श मानती हैं और अपना फिल्मी करियर भी उन्हीं की तरह डेवलप करना चाहती हैं. लेकिन वह इन दिनों परेशान इसलिए हैं, क्योंकि उनका नाम उनकी फिल्म ये साली ज़िंदगी के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ जोड़ा जा रहा है. दरअसल फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी महिला का है, जो एक मर्द के साथ ज़िंदगी बिताना पसंद नहीं करती, लेकिन असल जीवन में वह वन मैन वुमेन हैं. वह अपने पति के सिवाय किसी और के साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हैं. उन्हें समाज की इस धारणा से शिक़ायत है, जिसमें किसी पुरुष और महिला के साथ काम करते हुए अच्छे रिश्ते बन जाने पर अफ़वाहें फैला दी जाती हैं. हालांकि चित्रांगदा कॉन्फिडेंट हैं और इन अफ़वाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती. फ़िलहाल उनके लिए ख़ुशी का वक़्त है, जिसे वह भरपूर एंजॉय करना चाहती हैं. दरअसल काफी मशक्कत के बाद उन्होंने मुंबई में अपना घर ले लिया है. इसके अलावा उनके पास अब फिल्मों की भी कमी नहीं है. जल्द ही चित्रांगदा डेविड धवन के बेटे रोहित धवन की कॉमेडी फिल्म में एक डांसर के रूप में नज़र आने वाली हैं.

सॉफ्ट हर्टेड अक्षय

कॉमेडी किंग अक्षय कुमार नए-नए फ्लेवर टेस्ट करने में उस्ताद हैं. जहां फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी, सीरियस और हर तरह के रोल निभाए, वहीं टेलीविज़न पर भी विविधता पर ख़ास ध्यान दिया. आने वाले दिनों में वह एक के बाद एक फिल्मों में नज़र आने वाले हैं. उनकी फिल्म हाउसफुल का रीमेक बनने वाला है, जिसमें उनके साथ दीपिका नहीं, असिन के होने की ख़बरें आई हैं. अभी हाल में उन्हें इंडस्ट्री की लेटेस्ट आई गर्ल अनुष्का शर्मा के साथ पटियाला हाउस में देखा गया. हालांकि फीमेल स्टार नई हो या पुरानी, अक्षय उसे कंफर्टेबल कर ही देते हैं. यही उनकी ख़ास बात है. जिस हीरोइन ने भी अक्षय के साथ काम किया, वह उनके गुण गाने लगी. अक्षय के डाउन टू अर्थ होने की वजह शायद उनका अपना जीवन है. जिस तरह वह संघर्ष करके इस मुक़ाम तक पहुंचे हैं, उन्हें स्ट्रगल करते कलाकारों को देखकर सहानुभूति होती है और अच्छा भी लगता है. दिल्ली के चांदनी चौक इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अक्षय इमोशनल हैं और सॉफ्ट हर्टेड भी. यही कहना है उनके साथ करने वालों का.

अनीता का नया शो

मॉडलिंग, टीवी धारावाहिक और क्षेत्रीय फिल्मों के अलावा अनीता ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री में ख़ुद की एक अलग पहचान बना ली है. लगभग दस टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी अनीता के अभिनय का लोहा तो सबने माना, पर उन्हें खास तौर पर तरजीह दी सोप ओपेरा क्वीन एकता कपूर ने. अनीता ने एकता के ही धारावाहिक कभी सौतन कभी सहेली से टेलीविज़न पर अपने करियर की शुरुआत की. उसके बाद उन्हें देश के हर घर में पहचान मिल गई और उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम किया. यही नहीं, उन्होंने तमिल, तेलुगु एवं कन्नड़ के साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उनके ग्लैम करियर की शुरुआत एवरयूथ, सनसिल्क और बोरोप्लस की एड फिल्मों से हुई. लगभग दस हिंदी फिल्मों में काम करके उन्होंने हीरोइन बनने की अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन उन्हें दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका. दक्षिण की फिल्मों में उन्हें काफी पसंद किया गया, लेकिन उन्होंने टीवी धारावाहिकों और हिंदी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा है. एक बार फिर वह टेलीविज़न पर वापस लौट रही हैं. वह जल्द ही विक्रम भट्ट के थ्रिलर शो लव स्टोरी में अजय सिंह चौधरी के अपोजिट नज़र आने वाली हैं.

एक्सपेरीमेंटल मुग्धा

इंडस्ट्री में बालों पर ज़्यादातर प्रयोग पुरुष कलाकार ही करते नज़र आते हैं. इनमें चारों ख़ान यानी नवाब सैफ अली ख़ान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर ख़ान, दबंग सलमान ख़ान, बादशाह शाहरुख ख़ान एवं रितिक रोशन, जो वक़्त-वक़्त पर अपना हेयर स्टाइल बदलते रहते हैं. लेकिन हीरोइनों में से शायद ही किसी ने अपना हेयर स्टाइल बदला हो. याद करें, दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म ओम शांति ओम से लेकर अब तक उनके हेयर स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया. इसी तरह दूसरी हीरोइनों के हेयर स्टाइल में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुग्धा गोडसे ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है. मुग्धा इन दिनों बदले हुए अंदाज़ में नज़र आ रही हैं. ज़ाहिर है, अपने इस नए लुक में वह बिल्कुल अलग दिख रही हैं. दरअसल, मुग्धा ने अपने वेवी हेयर को स्ट्रेट करा दिया है और फ्रंट से फ्रीन्ज हेयर कट कराया है. अपने इस नए हेयरकट के बारे में मुग्धा हंसते हुए कहती हैं, मैं जब अपने नए लुक में पार्टी में पहुंची तो वहां सभी मुझे देखकर हैरान हो गए. सभी ने सोचा कि मैंने विग लगा रखी है, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि यह मेरे रीयल बाल हैं तो सब सरप्राइज़्ड हो गए. वहीं मेरी मम्मी का कहना था कि जब मेरे फ्रंट के बाल बड़े होंगे तो वह मेरी आंखों में जाएंगे. इससे मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी. इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि मेरे बाल भेड़ के बाल जैसे दिख रहे हैं. तो क्या मुग्धा आप अपना यह नया लुक चेंज कर डालेंगी? वह कहती हैं, मैं इस लुक में ज़्यादा यंग लग रही हूं, इसलिए चेंज करने का तो सवाल ही नहीं है. यानी कोई कुछ भी कहे, अपने नए लुक से मुग्धा ख़ुश हैं.

उलझ गईं प्रियंका

मीडिया को ब्लेम करना सितारों के लिए फैशन हो गया है. कुछ भी हो, कहीं भी हो, वे अपनी बात मीडिया पर इल्ज़ाम लगाकर ख़त्म कर देते हैं. इल्ज़ाम लगाते वक़्त वे भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने मीडिया में आने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले थे. मीडिया के सामने अच्छी इमेज बने, इसके लिए प्रियंका चोपड़ा भी अक्सर तरह-तरह की कोशिशें करती रही हैं, लेकिन जबसे उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, तबसे मीडिया के प्रति उनके तेवर रूखे हो गए हैं. छापा पड़ने के बाद जब वह अपनी फिल्म का प्रोमोशन करने आईं, तब मीडिया पर ही भड़क गईं. उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया ने उनके घर पर मिलने वाले पैसों और प्रॉपर्टी के बारे में ग़लत जानकारियां दीं. लेकिन प्रियंका को शायद यह पता नहीं कि यह जानकारियां मीडिया को देश के एक बड़े और विश्वसनीय विभाग आयकर विभाग से मिली हैं. मीडिया उनके घर नहीं गया था कैश और प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ शाहिद को देखने. उनकी नई फिल्में बॉक्स ऑफिस के फ्लोर पर हैं, कहीं ऐसा न हो कि मीडिया को ब्लेम कर ख़ुद का पल्ला झाड़ने की कोशिश का असर प्रियंका की मच एक्सपेक्टेड फिल्मों पर पड़ जाए. फिर तो कोई न उनके बारे में जानने में रुचि रखेगा, न उनके पास ख़ुद के बारे में बताने का कोई ज़रिया होगा. प्रियंका मीडिया के सामने तो नहीं डरती, लेकिन फिल्म की शूटिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं. दरअसल प्रियंका अपनी मच अवेटेड, विशाल भारद्धाज कृत फिल्म सात ख़ून माफ है की शूटिंग के दौरान नसीरूद्दीन शाह को देखकर कई बार अपने डायलॉग भूल गईं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

सात ख़ून माफ़

फिल्म सात ख़ून माफ़ रस्किन बांड की कहानी सुसानाज सेवन हस्बेंड्स पर आधारित है. प्रियंका चोपड़ा ने इसमें एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है, जो उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर सात शादियां करती हैं, क्योंकि उसके पतियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है. प्रियंका को एक चैलेंजिंग किरदार निभाने को मिला है और कमीने के बाद विशाल के साथ यह उनकी दूसरी फिल्म है. सुसाना एना मेरी जोहानेस (प्रियंका चोपड़ा) एक ऐसी ख़ूबसूरत महिला है, जिसे पाने के लिए हर आदमी किसी भी हद तक जा सकता है. पिछले 35 वर्षों में उसने सात बार विवाह रचाया, क्योंकि उसके आधा दर्जन पतियों की असामयिक और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. शक की सुई प्रमुख रूप से सुसाना की ओर है.

ख़ूबसूरत और युवा सुसाना ने पहली शादी एडविन रॉड्रिक्स (नील नितिन मुकेश) से की थी, जो एक मेजर था. मेजर के प्यार में वह लट्टू हो गई थी, हालांकि मेजर और उसकी उम्र में ज़्यादा फासला था. यूनिफॉर्म में मेजर बेहद हैंडसम नज़र आता था और वह हमेशा हुक्म देना पसंद करता था, लेकिन सुसाना तो प्यार में अंधी थी. दूसरी बार सुसाना ने जिमी स्टेट्सन (जॉन अब्राहम) से शादी की. दिखने में जिमी बहुत आकर्षक था. संगीत का वह जादूगर था और इसी वजह से सुसाना उसकी ओर खिंची चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में क्या घटने वाला है. कविताएं सुसाना को बहुत पसंद हैं और इसी कारण उसने वसीउल्लाह ख़ान (इरफान ख़ान) से ब्याह रचाया. वसीउल्लाह उर्फ मुसाफिर रोमांटिक किस्म का इंसान था. दिन में दिल

को छू लेने वाली उम्दा कविताएं हुईं और रात में कुछ और ही घटित हो गया. सुसाना की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन समझदारी नहीं. मास्को के निकोलई व्रोंस्की (एलेक ड्याचेंको) के साथ उसने अगली शादी की. इन सारे पतियों की मौत के बाद पुलिस को इस केस में मज़ा आने लगा, ख़ासतौर पर ऑफिसर क़ीमत लाल (अन्नू कपूर) को. वह सुसाना की कुछ ज़्यादा ही मदद करने लगा और शादी के लिए दबाव डालने लगा. उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दीं कि सुसाना न नहीं कह सकती थी. क़ीमत लाल के बाद डॉ. मधुसूदन तरफदार (नसीरूद्दीन शाह) की बारी थी. मधुसूदन के जाने के बाद सुसाना ने सातवीं शादी की, अपनी बेहतरी के लिए. क्या ये सारे पति मर जाने के काबिल थे? क्या इनकी हत्या करना आवश्यक था या इनकी हत्याएं ख़ूनख़राबे का खेल खेलने के लिए की गई थीं? क्या सुसाना को कभी सच्चा प्यार मिल सका? इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे सात ख़ून माफ़ में.

संगीतकार से निर्देशक बने विशाल भारद्धाज की गिनती वर्तमान के प्रतिभाशाली निर्देशकों में होती है. वह कहानियों का चुनाव लीक से हटकर करते हैं और उन्हें अपने मुताबिक़ स्क्रीन पर पेश करते हैं. उनकी फिल्मों का ट्रीटमेंट, अभिनय और संगीत हमेशा उल्लेखनीय रहता है. विशाल भारद्धाज की फिल्म में न केवल खुले संवाद, बल्कि बोल्ड सीन भी होते हैं. उनके द्धारा निर्देशित यह फिल्म चर्चित फिल्मों में से एक है, जो आगामी 18 फरवरी को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 14 फरवरी–20 फरवरी 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

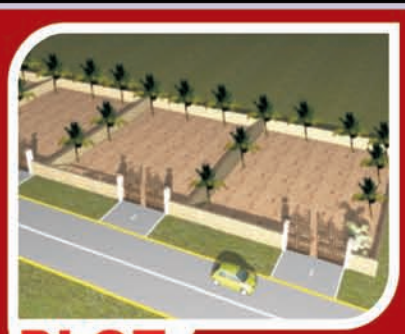

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सवर्ण आयोग

विवादों का पिटारा

नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फ़ैसला कर एक बड़ा दांव खेला है. यह ऐसा दांव है, जिससे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का दायरा बढ़ भी सकता है या फिर पूरा खेल बिगड़ सकता है. अगर तीर निशाने पर लगा तो नीतीश कुमार को पकड़ पाना विपक्षियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा.

प्रेम कुमार मणि

सरोज सिंह

पिछली विधानसभा में विधायक अवनीश कुमार सिंह ने अंतिम संस्कार में आरक्षण के अनुपालन की मांग करते हुए कह डाला कि बांसघाट के शवदाह गृह में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. इस बात ने सबको हैरत में डाल दिया था. पूरा सदन सकते में था. इसी बीच हंसी की फुहार फूट पड़ी और इसे राजनीतिक ठिठोली करार दे दिया गया, पर यह हास्य का नहीं, व्यंग्य का प्रसंग था. यह अगड़ी जाति से आने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दरकिनार किए जाने से उपजी कुंठा का व्यंग्यात्मक रूपांतरण था. सिर्फ़ जाति के नाम पर अवसरों से वंचित समुदाय की वेदना की दारुण अभिव्यक्ति. इसी बीच गत विधानसभा में लोजपा विधायक दल के नेता महेश्वर सिंह ने आज़ाद भारत में पहली बार सवर्णों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के आकलन के लिए आयोग बनाने की वकालत की. उनके उक्त ग़ैर सरकारी प्रस्ताव पर तकरीबन आधा घंटा बहस हुई, फिर उसे ख़ारिज़ कर दिया गया. आज़ादी के बाद भारत में यह पहला अवसर था, जब किसी संवैधानिक संगठन में सवर्णों के मौलिक सवाल को उठाया गया. आख़िरकार बिहार सरकार ने सवर्ण समुदाय में शोषित–पीड़ित तबके के लिए आयोग बनाने का फ़ैसला किया है. निश्चय ही यह आज़ाद भारत में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयास है. उपरोक्त प्रसंग इस प्रस्तावित आयोग की पूरी दास्तां को बयां करता है.

बिहार सरकार ने सवर्ण समुदाय में शोषित-पीड़ित तबके के लिए आयोग बनाने का फ़ैसला किया है. निश्चय ही यह आज़ाद भारत में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयास है. उपरोक्त प्रसंग इस प्रस्तावित आयोग की पूरी दास्तां को बयां करता है. इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सत्ताधारी जदयू से निलंबित नेताओं ने तैयार की थी.

इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सत्ताधारी जदयू से निलंबित नेताओं ने तैयार की थी. 24 जून, 2007 को संजय वर्मा, रामबिहारी सिंह, चंद्रभूषण राय और शंकर आज़ाद ने मिलकर एस–4 नामक एक संगठन बनाया. एस–4 अर्थात शोषित सवर्ण संघर्ष समिति. इसका उद्देश्य सवर्ण समुदाय के पिछड़े, पीड़ित और आर्थिक रूप से विपन्न तबके को उचित अधिकार दिलवाना था. हालांकि इन अति महत्वाकांक्षी नेताओं का मक़सद पूरा नहीं हुआ. ये शीघ्र ही बिखर गए. इनकी राहें जुदा हो गईं. इसी बीच इन लोगों ने सर्वजन समाज पार्टी भी बनाई. सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ जोड़ कर राजनीतिक हित साधने की मंशा थी, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली. इससे पूर्व लोजपा के युवा नेता रोहित कुमार सिंह ने भी रेन्शां नामक संगठन बनाया था. उधर गत विधानसभा चुनाव के समय मुख्य विपक्षी गठबंधन राजद–लोजपा ने ग़रीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का वादा किया था. वहीं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह द्वारा सवर्ण जातियों के सवाल एवं बटाईदारी के मुद्दे पर आयोजित किसान महापंचायत से जदयू के अगड़े वोटों में सेंधमारी का ख़तरा पैदा हो गया था. तब डैमेज कंट्रोल के तहत भाजपा–जदयू के घोषणापत्र में शोषित–पीड़ित सवर्णों के लिए आयोग बनाने का वादा किया गया था. उस वक़्त सियासी हलके में इसे ख़ास तवज्ज़ो नहीं मिली थी, लेकिन चुनाव बाद सरकार गठन के उपरांत पिछड़े सवर्णों के लिए आयोग बनाने का फ़ैसला किया गया तो बवाल मच गया.

जदयू के विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि ने इसे सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला क़दम क़रार दिया. उनके अनुसार, देश में मनुस्मृति के रूप में सवर्ण आयोग की एक रिपोर्ट पहले से पड़ी हुई है. मनुस्मृति में तथाकथित अगड़ों को अकूत नागरिक अधिकार प्रदान किए गए थे. यही समाज के अन्य तबकों के उत्पीड़न एवं पिछड़ेपन की मूल वजह थी. इसी कारण देश के संविधान ने मनुस्मृति को ख़ारिज़ कर दिया था. इसके बावजूद नीतीश कुमार चाहते हैं तो इसे लागू कर दें. मनुवादी विचारधारा के कारण सदियों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को भारतीय संविधान द्वारा विशेष सहूलियत प्रदान की गई है. नीतीश सरकार सवर्णों की पीड़ा दूर करना चाहती है तो क्या वह किशोर कुणाल द्वारा बनाए गए दलित महंत को हटाएगी, ज़मींदारी फिर लागू करेगी, अस्पृश्यता को पुन: स्थापित करेगी और कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फुले एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को दफ़न कर देगी? दूसरी तरफ जदयू के नेता चंद्रभूषण राय नीतीश सरकार के इस क़दम को ऐतिहासिक क़रार देते हैं. उनके अनुसार, नीतीश कुमार का यह क़दम सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला नहीं, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय बनने से बचाने का सार्थक प्रयास है. अगड़ों में आर्थिक–सामाजिक रूप से विपन्न तबके के हितों की रक्षा करने की कोशिश की गई है. यह वह वर्ग है, जो सदियों से दोहरी मार झेल रहा है. अगड़ी जाति से होने के कारण सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक सहूलियत से तो वंचित है ही, वहीं अपनी जाति एवं अन्य सामंतों से भी पीड़ित रहा है. इसके अलावा प्रेम कुमार मणि की तरह पिछड़े समुदाय का प्रतिक्रियावादी तबका इनसे सिर्फ़ इसलिए घृणा करता है, क्योंकि इनका जन्म उच्च जाति में हुआ है. पिछड़ी जाति में ही जन्म लेने वाले नीतीश कुमार जैसे संवेदनशील नेतृत्वकर्ता को इसका ख्याल आया और वह इस वर्ग के उद्धारकर्ता बन गए.

एस–4 के नेता संजय वर्मा काफ़ी कड़े शब्दों में विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि के बयान की मजम्मत करते हैं. वह कहते हैं, सामाजिक न्याय का मतलब हिंदू सवर्णों एवं मुसलमानों को बंगाल की खाड़ी में फेंकना तो नहीं है. मणि ख़ुद को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूले में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी तीन प्रतिशत कोटा प्रदान किया गया था. जदयू महासचिव छोटू सिंह भी मानते हैं कि सवर्ण आयोग का गठन समय और समाज की ज़रूरत थी और इसे पूरा कर नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया. बिहार राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामनरेश सिंह और विधान पार्षद उपेंद्र कुमार ने भी इस आयोग के गठन की आलोचना के लिए मणि को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जब जदयू के चुनाव घोषणापत्र में पिछड़े सवर्णों के लिए आयोग बनाने की मंशा व्यक्त की गई थी, तब विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि को सांप क्यों सूंघ गया था? क़ायदे से उसी समय उन्हें इसका प्रतिवाद करना चाहिए था. लेकिन प्रेम कुमार मणि अकेले दम पर विरोध की अलख जगा रहे हैं. वह कहते हैं, बिहार में वर्षों बाद विकास का वातावरण बना था, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की लालसा में इसे जातीय युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं. वह इस आयोग द्वारा देश के सवर्णों के समक्ष ख़ुद को उनका सबसे बड़ा हित चिंतक साबित करना चाहते हैं.

उच्च जाति के पिछड़ों के लिए आयोग बनाने की वकालत करने वाला वर्ग भी नीतीश कुमार के प्रति सशंकित है. उसे नीति पर नहीं, नीयत पर शक़ है. उसके अनुसार नीतीश कुमार इसमें किस तरह के लोगों के हाथों में कमान देते हैं, उससे ही तय होगा कि यह सियासी हथकंडा मात्र है या वास्तव में कुछ कर दिखाने की मंशा भी है. संजय वर्मा कहते हैं कि दिल्ली के सवर्ण को बिहार में सदस्य बनाया जाएगा तो वह छपरा के राजपूतों, मिथिलांचल के कायस्थों, कोशी के ब्राह्मणों एवं भूमिहारों की पीड़ा को क्या समझेगा. वैसे भी नीतीश सरकार में बने बहुतेरे आयोगों की रिपोर्ट धूल फांक रही हैं. भूमि सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, किसान आयोग और पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में गठित समान स्कूली शिक्षा से संबंधित आयोग हाथी के दांत ही साबित हुए. वहीं बिहार में मानवाधिकार आयोग, महादलित आयोग एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के लिए महादलित आयोग एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग नई–नई जातियों को महादलित एवं अति पिछड़े का दर्जा प्रदान करते रहे. महादलित आयोग के माध्यम से तो राजनीतिक हित साधने के लिए पटना के गांधी मैदान में रैली तक आयोजित की गई. लोजपा नेता रोहित कुमार सिंह भी आयोग बनाने के निर्णय का सशर्त स्वागत करते हैं. वह कहते हैं कि निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने को कहा जाना चाहिए, साथ ही उसे तत्परता से लागू किया जाएगा, तभी इस आयोग की उपादेयता सिद्ध होगी. देखा जाए तो नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फ़ैसला कर एक बड़ा दांव खेला है. यह ऐसा दांव है, जिससे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का दायरा बढ़ भी सकता है या फिर पूरा खेल बिगड़ भी सकता है. अगर तीर निशाने पर लगा तो बिहार में नीतीश कुमार को पकड़ पाना विपक्षियों के लिए मुश्किल हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

कुछ महीने इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में अबोध बच्चों के बीच खिचड़ी बनाकर उपलब्ध कराये गये मगर हाल के दिनों में मध्यान्ह भोजन का वितरण प्राय: विद्यालयों में पूर्णत: बंद है.

अर्जुन मुंडा ने सचिव के आदेश पर रोक लगा दी तो निबंधन का काम शुरू हुआ. सरकार के राजस्व में करोड़ों की क्षति के बावजूद हेमंत सोरेन ने सचिव के आदेश को कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत पर बल दिया.

एक नज़र इधर भी

तिरुपति होम्स कैंसर अस्पताल बनाएगा

तिरुपति होम्स ने अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए दरभंगा में एक कैंसर अस्पताल भवन के निर्माण की घोषणा की है. तिरुपति होम्स लिमिटेड के सीएमडी शशिभूषण सिन्हा ने बताया कि छह करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का पूरा ख़र्चा कंपनी उठाएगी. सिन्हा ने बताया कि तिरुपति होम्स आगे भी समाज कल्याण के कामों में अपनी ज़िम्मेदारी निभाता रहेगा. उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन में रोगियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा. *–अनुमेहा झा*

जागरूकता अभियान मज़ाक बना

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के दौरान आयोजित कार्यशाला के बावजूद कहीं पेड़ पौधों का नामोनिशान दिखाई नहीं देता. हर वर्ष रूरल यूथ को-ऑर्डिनेशन सेंटर, पटना के तत्वाधान में लाखों रुपये लगाकर समस्तीपुर ज़िले में कार्यशाला का आयोजन कर पेड़ों की हरियाली की बात की जाती है, लेकिन ज़मीन पर कोई हरियाली नहीं दिखती. जैसे-जैसे गरमी चढ़ेगी, लोग कार्यशाला का नतीजा ढूंढ़ेंगे और लूट की चर्चा होगी.

प्रेस क्लब का निर्माण अधर में

समस्तीपुर ज़िला गठन के 39 वर्षों के अंतराल में पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब निर्माण हेतु सरकार की मुश्तैदी के बाद भी ज़िला प्रशासन द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया जाना दु:खद ही नहीं बल्कि जनतंत्र विरोधी और तानाशाही रवैए का परिचायक है. नीतीश सरकार बनते ही मुख्यमंत्री द्वारा ज़िले के पत्रकारों की मांग पर सचिवालय, पटना से कार्रवाई की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के उक्त निर्देशों की अवहेलना अभी तक हो रही है.

इंडियन ओवरसीज बैंक की मदद

[illegible]

अंग लोक परिषद का गठन

[illegible]

पत्रकारों की मदद करेंगे मुंडा

[illegible] में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एवं झारखंड प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संयुक्त सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि पत्रकारों की पीड़ा को समझते हुए जल्द ही ज़मीन एवं आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है, इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि समाज के निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है. विकास को गति प्रदान करने में भी पत्रकारों का योगदान होता है. सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह ने कहा कि आंचलिक पत्रकारिता का कार्य काफ़ी ज़ोखिम भरा है. पत्रकारों की एकजुटता ज़रूरी है. वरिष्ठ पत्रकार बलवीर दत्त ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार का सम्मेलन आंचलिक स्तर पर भी किया जाना चाहिए. *–चौथ दुनिया ब्यूरो*

डॉ. इसरायल संकाय अध्यक्ष बने

मगध विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के निदेशक डॉ. इसरायल खां को मविवि के कुलपति डॉ. अरविन्द कुमार ने शिक्षा विभाग का संकाय अध्यक्ष बनाया है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डॉ. खां को कोचिंग फॉर सिडयूल कास्ट, सिडयूल ट्रायब एंड माइनोरिटीज का प्रभारी बनाया है. इसके द्वारा नेट, वेट, स्लेट, बैंक एवं विभिन्न सेवा से संबंधित परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी. *–सुनील सौरभ*

काला धन वापस आए : सुनील खवाड़े

भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योगपीठ के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने व विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित किया. धरने का नेतृत्व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मुख्य संयोजक सुनील खवाड़े ने किया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानून बनाकर कार्रवाई करने एवं विदेश के बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने चाहिए. समाहरणालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर मीडिया प्रभारी सोहन पाठक, संजीव झा, महेशमणी द्वारी, विश्वनाथ मंडल, गिरधारी मंडल, बबलू झा, वीरेंद्र अग्रवाल, बाबा खवाड़े सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे. *–रणजीत झा*

पुल न होने से परेशानी

गया ज़िले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सोभ बाज़ार से धनगई समेत करीब दो दर्जन से अधिक गांवों तक जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. क्योंकि जीटी रोड से लगी गुलसकरी नदी पर पुल नही बन पाया है. जबकि इस रास्ते से होकर चुनाव में तमाम जनप्रतिनिधियों का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन उनकी नज़र लाखों ग्रामीणों की इस आवागमन समस्या पर नही पड़ती है. वोट मिलने के बाद सारे जन प्रतिनिधि लोगों की समस्या को भूल जाते हैं. *–प्रमोद कुमार*

गोपालगंज में लंदन के डॉक्टर

बिना सरकार की मदद से गोपालगंज में एक ऐसा अस्पताल चल रहा है, जहां हज़ारों ग़रीबों का कम ख़र्च पर इलाज हो रहा है. गोपालगंज ज़िला मुख्यालय से लगभग 40 कि.मी. दूर कटैया प्रखंड के अमैया गांव में लंदन के ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड पा चुके डॉक्टर महिमा पाडेय ने इंडो ब्रिटिश मेडिकल सेंटर की स्थापना की है. यहां ग़रीबों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है. लंदन से समय-समय पर आने वाले डॉक्टर ब्रोनडेन ओकोल मैन और भारतीय मूल के डॉक्टर हरवंश सेठ ने अस्पताल को चलाने में स्थानीय लोगों की मदद की सराहना तो की, लेकिन उन्हें बिजली और सड़क के मुद्दे के अलावा राज्य सरकार से अपेक्षा अनुरूप सहायता न मिलने का मलाल रही है . *–संदीप कुमार*

सीमांचल

देह के दलदल में फंसी मासूम ज़िंदगियां

नीरज कुमार

एक ओर जहां पूरे देश में राष्ट्रीय बलिका दिवस मनाया जाता है, वहीं सीमांचल के चंद बेख़ौफ़ दलालों द्वारा मासूम नाबालिक लड़कियों से अनैतिक ज़िस्मफरोशी जैसे धंधे करवाकर मानवता को कलंकित और शर्मसार किया जा रहा है. आज सीमांचल के देह के व्यपार का नेटवर्क गुलाबबाग, किशनगंज, फारबिसगंज, सिलीगुड़ी, मुंबई, पटना और दिल्ली के सत्ता के गलियारे से लेकर तेल उत्पादक खाड़ी के देश तक फैल चुका है. दरअसल ग़रीब पड़ोसी मुल्क नेपाल व बंगालादेश की सीमा सीमांचल से सटती है, साथ ही देश के अन्य भागों की तुलना में सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार व पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर सिलीगुड़ी (दार्जलिंग) जैसे ज़िलों का आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है. यहां के लोगों की माली हालत ठीक नहीं है व शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है. इसीलिए नौकरी व धन के लालच में यहां की लड़कियां अच्छे जीवन की चाह में और माली हालत सुधारने के लिए देह के दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं और अपना जीवन नर्क बना लेती है. आज पूर्णिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी, मुंबई, पटना और दिल्ली के राजनितिक गलियारों से लेकर समंदर पर अरब के देशों तक बीते पांच सालों में 1000 से ज़्यादा लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी हैं. ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां हालात की शिकार हैं. इनमें से कुछ लड़कियों को अमीर बनने की ललक ने मुंबई से लेकर अरब के खाड़ी देशों तक पहुंचा दिया है. सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूर्णिया के गुलाबबाग, मौजरापट्टी की लगभग सौ से ज़्यादा लड़कियां देह के धंधे में फंसी हैं. वैसे यहां की लड़कियों का उपयोग स्थानीय सियासत के ठेकेदारों से लेकर अनेकों नौकरशाहों के लिए भी होता रहा है. वहीं स्थानीय होटलों मे भी इन लड़कियों को परोसा जाता रहा है. वर्तमान में सिलीगुड़ी प्रमुख अय्याशी का अड्डा बना हुआ है. यहां सीमाचंल के छुटभैये नेता से लेकर नामचीन नेता व नौकरशाह मनोरंजन के लिए प्राय: पहुंचते हैं. सीमांचल के देह व्यापार का नेटवर्क इतना गहरा और मज़बूत है कि इस व्यापार के विरुद्ध आम आदमी तो क्या पुलिस भी कड़ा कदम उठाने से कतराती है. विगत एक साल में पूर्णिया की हरदा देह मंडी, गुलाबबाग समेत रौटा में देह व्यापार के कई ऐसे मामले मिलें हैं जिनमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने से पुलिस कतराते रही है, वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक अनिल किशोर यादव जैसे लोग भी हैं, जिन्हें जनता के हित में कटिहार से देह मंडी को उजाड़ने में सफलता मिली. वर्तमान में गुलाबबाग ज़ीरो माइल स्थित देह मंडी में 12 साल से लेकर 14 साल तक की कई मासूम जिंदगियां सड़क किनारे गुज़रते राहगीरों को नज़र आ जाएगी. वहीं स्थानीय पुलिस इस अनैतिक धंधे में मासूमों को परोसे जाने के मामले को देखते हुए भी अनजान बनी हुई है. एक व्यक्ति ने इन मासूमों को देखते हुए अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कह दिया कि बापू तेरे देश में हो रहा यह कैसा अत्याचार. मासूम बच्चियों से भी कराया जा रहा है देह व्यापार.

feedback@chauthiduniya.com

मगध विश्वविद्यालय

बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर

सुनील सौरभ

जिस प्रकार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक व्यवस्था तथा पठन-पाठन के उच्च मापदंड के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, ठीक उसी तरह अब मगध विश्वविद्यालय भी देश-दुनिया में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरे उतरते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है. बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य ही यह था कि था इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, लेकिन बाद के वर्षों में मगध विश्वविद्यालय, बदनामी के एक नहीं, अनेक रिकॉर्ड कायम करता चला गया. परंतु, पिछले एक वर्ष में मगध विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी जो पहचान बनाई है, वह अद्भुत है. यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय की बढ़ती गरिमा को देखते हुए बौद्धों के महान धर्मगुरु 17 वें करमापा त्रिनेले थाये दोरजे, भूटान के प्रधानमंत्री, काबुल विश्वविद्यालय के चांसलर समेत अनेक राजनायिक एवं विद्वानों ने मगध विश्वविद्यालय में आकर बदलते शैक्षणिक परिवेश को न केवल सराहा, बल्कि हरसंभव मदद का आश्वासन भी दे डाला.

17 वें करमापा त्रिनेले थाये दोरजे ने तो मगध विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉ. अरविंद कुमार को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया, तो अफ़ग़ानिस्तान के मशाल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, काबुल के कुलपति और चांसलर ने अपनी सरज़मीं पर मगध विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा का केंद्र खोलने का प्रस्ताव दे डाला और इसके लिए हर तरह का सहयोग देने का वादा भी किया. मगध विवि में इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर को मूर्त रूप मिलते ही यह दुनिया के महत्वपूर्ण केंद्रों में एक होगा, जहां अंतराष्ट्रीय सम्मेलन या सार्क सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आसानी से किए जा सकते हैं. इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर का शिलान्यास जून माह में बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति देवानंद कुंवर के हाथों होने की संभावना है. यह सारा बदलाव मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार के अथक प्रयासों का परिणाम है. योगदान के समय ही उन्होंने मगध विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का संकल्प यहां के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष लिया था और अब पदस्थापन के एक साल की कम अवधि के बाद ही शैक्षणिक वातावरण कायम करने में मगध विश्वविद्यालय कई क़दम आगे बढ़ा चुका है. 25 सालों के बाद मगध विश्वविद्यालय में हुए दीक्षांत समारोह में काबुल विश्वविद्यालय के कुलपति का शामिल होना तथा मगध विश्वविद्यालय में विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए शोध कार्य हेतु सहयोग करने का प्रस्ताव देना, शायद देश के पहले विश्वविद्यालय में शामिल है. पिछले छह माह में दो विषयों, मगही एवं पर्यावरण में स्नातकोत्तर के साथ ही एमए इन एजूकेशन व एमए इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कराना एक बड़ी उपलब्धि है. पूरी दुनिया जहां पर्यावरण पर काम कर रही है, वहीं मगध विश्वविद्यालय इससे अछूता कैसे रह पाता. कुलपति के प्रयास से ही यहां इंडियन सोसाइटी ऑफ इंवायरमेंटल साइंस की स्थापना की गई. अगर प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने की ख़ातिर किए गए ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय कार्यों पर नज़र दौड़ाएं, तो मगध विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय हो गया, क्योंकि यहां संपादित सभी परीक्षाओं की कॉपियों को डिजिटल किया जाने लगा है. पहली बार कॉलेजों के निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि अंगीभूत कॉलेजों के पठन-पाठन सहित अन्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के कार्यों को देखा जा सके. मगध विश्वविद्यालय ही बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना, जहां चांसलर, लेक्चरर सीरीज प्रारंभ हुई है. इसमें देश-विदेश के अद्भुत विद्वान भाग ले रहे हैं. पिछले दिनों इसी सीरीज में भाग लेने के लिए कनाडा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान एमएच मुलर भी आए थे. स्नातकोत्तर की पढ़ाई अब साल भर की जगह सेमेस्टर से होने लगी है. विवि के हर विभाग में मोरल साइंस की पढाई भी प्रारंभ की जा चुकी है. जल्द ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी. कुलपति के बेहतर प्रयास और सोच का प्रतिफल है कि विवि का मान बढ़ाने वाले बैचलर डिग्रीधारकों को वीसी गोल्ड मेडल दिया जाने लगा है.

छात्र-छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए अंक पत्र व अन्य तरह के प्रमाण पत्रों के निर्गत करने सहित अन्य अभ्यावेदनों को प्राप्त करने के लिए शाम सात बजे तक मविवि मुख्यालय में काउंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है और वहां दो पालियों में कर्मचारियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई. इसके अलावा मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में स्थित सभी विभागों तथा अंगीभूत कॉलेजों में पठन-पाठन का समुचित माहौल के साथ चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने में कुलपति सफल रहे हैं.

मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरविन्द कुमार ने मगध विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का संकल्प यहां के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष लिया था और अब पदस्थापन के एक साल की कम अवधि के बाद ही शैक्षणिक वातावरण कायम करने में मगध विश्वविद्यालय कई क़दम आगे बढ़ा चुका है.

मगध विश्वविद्यालय बोधगया MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों का निवाला गटक जाते हैं गुरु जी

विजयेंद्र कुमार

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अबोध बच्चों को शिक्षा के प्रति ललक पैदा करने व उनके शारीरिक विकास के लिए चलाई जा रही मध्यान्ह भोजन योजना का निवाला कोई और ही गटक जाता है. इस मामले में सारण ज़िले का कोई सानी नहीं है. पिछले कई वर्षों से उक्त योजना मद का चावल व आवंटित राशि का बंदरबाट का मामला आम आवाम के साथ ही संबंधित स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी हैरत में डाले हुए है. बावजूद इसके, विभागीय अधिकारियों के मेल- जोल के चलते यह कार्य संस्कृति ज़िले के प्राय: सभी प्रखंडों के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बदस्तूर जारी है. विगत वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत आवंटित राशि व चावल में बड़े पैमाने पर हो रही बंदरबांट को देखते हुए इस कार्य की ज़िम्मेवारी कई स्वयं सेवी संगठनों को दी गई थी, मगर ज़िले के कई प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के तहत बटने वाली खिचड़ी में कीड़े मिलने की घटना ने इस योजना के प्रति कलयुगी गुरुओं की संकीर्ण मानसिकता की पोल खोलकर रख दी. पिछले साल सारण के तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने दिघवारा प्रखंड के एक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के तहत बच्चों को उपलब्ध कराई गई खिचड़ी में कीड़े मिलने की घटना की जांच कर इस मामले में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित भी किया था. इस मामले की तहक़ीक़ात करने पर जो रहस्योद्घाटन हुआ, उसके अनुसार इस मामले में कार्यरत एनजीओ संचालक को बदनाम कर उक्त योजना के कार्यों को अपने हाथ में पुन: हस्तगत करने की कुत्सित चाल बताई गई थी. उस वक़्त खिचड़ी में कीड़े मिलने की घटना अक्सर हो रही थी. उच्च अधिकारियों की दबिश के कारण कुछ महीने इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराया गया, लेकिन हाल के दिनों में मध्यान्ह भोजन का वितरण प्राय: विद्यालयों में पूर्णत: बंद है. जबकि योजना के तहत सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का कार्य सुचारू रूप से संचालित है. हैरत की बात यह है कि उक्त योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से अक्सर विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति दर्शायी जाती है, जबकि विद्यालयों में वास्तविक छात्रों का नामांकन अपेक्षाकृत कम होता है. बदले में अवैध रूप से दर्ज कराये गये नामांकन के आधार पर मध्यान्ह भोजन का आवंटन कर सीधे-सीधे शिक्षक डकार जाते हैं. ग़ौरतलब है कि उक्त मद में हर महीने करोड़ों रुपये का आवंटन ज़िले को प्राप्त होता है. ज़िला प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि इस मामले में सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं. फलस्वरूप, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की मिली-भगत से यह काम बदस्तूर जारी है. यही वजह है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान के पद पर बैठने के लिए शिक्षकों के बीच शह और मात का खेल चलता है. इस कारण विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल दूषित हो रहा है. मध्यान्ह भोजन के उद्देश्य से आवंटित चावल के साथ-साथ अन्य ख़र्चमद की राशि का आवंटन प्रधान शिक्षकों के लिए आम के आम और गुठली के दाम वाली कहावत चरितार्थ करता है. जिसके चलते प्राय: विद्यालयों के पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

सीएनटी एक्ट विवाद थमेगा नहीं

नवल किशोर सिंह

सीएनटी एक्ट को लेकर पिछले दिनों उठा विवाद फ़िलहाल थम गया है, लेकिन राख के नीचे चिंगारी दबी है. यह चिंगारी कभी भी भड़क सकती है. पिछले दिनों सीएनटी एक्ट के एक प्रावधान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया था. इसकी वजह से अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में दरार नज़र आने लगी थी. मंत्रिमंडल में शामिल नेता परस्पर विरोधी बयान दे रहे थे. झामुमो अपने पुराने रंग में लौट आया था. हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के सचिव संतोष कुमार ने विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बिना ही जो तुगलकी फरमान जारी किया था, वह अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की ज़मीन की ख़रीद बिक्री से संबंधित था, जिसका तत्काल असर यह पड़ा कि राज्य के सभी ज़िलों के निबंधन कार्यालयों में सन्नाटा छा गया. ज़मीन का निबंधन तक बंद हो गया था. बाद में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सचिव के आदेश पर रोक लगा दी तो निबंधन का काम शुरू हुआ. सरकार के राजस्व में करोड़ों की क्षति के बावजूद हेमंत सोरेन ने सचिव के आदेश को कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत पर बल दिया. इसके साथ ही कई संगठन इसे कड़ाई से लागू करने के पक्ष में बयानबाज़ी करने लगे. दूसरी तरफ रजिस्ट्री कार्यालय और व्यवसायी वर्ग के लोगों ने इस प्रावधान पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. मालूम हो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधीनियम की धारा 46 की उपधारा 1-बी में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की ज़मीन उसी इलाके के उसी जाति के लोग ख़रीद सकते हैं, वह भी उपायुक्त की अनुमति के बाद. हालांकि बिहार सरकार ने 40 वर्ष पूर्व ही कोर्ट के आदेश से इस प्रतिबंध को हटा दिया था और झारखंड में राज्य गठन के बाद भी व्यवहारत: यह लागू नहीं था. यदि झारखंड में यह लागू हो जाए तो विकास का पहिया पूरी तरह थम जाएगा, क्योंकि तब कुछ ही ज़मीन ही ख़रीद बिक्री के योग्य बच जाएगी. इसके समर्थकों का कहना है कि इससे औद्योगिक विकास पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपायुक्त के आदेश से इनकी ख़रीद बिक्री हो सकेगी. जब यह प्रावधान लागू नहीं है तब तो उद्योगों के लिए ज़मीन मिलने में कठिनाई हो रही है. लागू होने के बाद कम से कम निवेशक तो झारखंड की ओर रुख़ करने से कन्नी काटेंगे.

झाविमो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस मामले को समझते हैं, इसीलिए वह शुरू से ही सीएनटी एक्ट में संशोधन के पक्षधर रहे हैं. इस विवाद के खड़े होने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस एक्ट की समीक्षा करने और इसमें समयानुकूल संशोधन करने का अनुरोध किया है. यह एक्ट जिस समय बना था, उस वक़्त तक ज़मीन के मालिकाना हक़ के दस्तावेजीकरण की कोई पद्धति नहीं थी. ताक़तवर लोग आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरन क़ब्ज़ा कर लेते थे. उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिये ही ब्रिटिश सरकार ने सीएनटी और एसपीएनटी एक्ट बनाया. विस्थापन के मामले भी ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उलझे हैं. आज की तारीख़ में निजी क्षेत्र के उद्यमी या रियल स्टेट के व्यवसायी किसी भूखंड पर लाठी के बल पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकते. आदिवासियों की ज़मीन पर तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता है. इसके उलट आदिवासी ही किसी भी भूखंड पर सरना का झंडा गाड़कर उस पर क़ब्ज़ा कर सकते हैं. इनके क़ब्ज़े को हटाने की किसी में ताक़त नहीं. इस एक्ट के कारण आज इनकी ज़मीन की कोई कीमत नहीं. सामान्य ज़मीन यदि एक लाख रुपये डिसमिल बिकेगी तो इनकी इसी लोकेशन की ज़मीन की कीमत 10 हज़ार भी नहीं मिलेगी. इस एक्ट के कारण वे ज़मीन मालिक [illegible] को यह आदिवासियों और सदानों के बीच एकता कायम कर अपने जनाधार में विकास का एक ज़रिया नज़र आ रहा है. पेसा एक्ट को लेकर उनके बीच दूरी बढ़ गई थी. इसीलिये सदानों के पेसा विरोधी आंदोलन के प्रबल विरोधी आदिवासी नेता अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ग़ैर आदिवासी सदानों की ज़मीनों की सुरक्षा के लिए सीएनटी एक्ट में मौजूद प्रावधान पर रोक न लग जाए. उन्हें भी सीएनटी समर्थक बनाकर अपने क़रीब लाया जाए. इससे एक नया समीकरण बनेगा जो उन्हें सत्ता में बने रहने में सहायक सिद्ध होगा. उन्हें राज्य की नहीं अपनी कुर्सी की चिंता है. दूसरी तरफ झारखंड के विकास के लिए चिंतित नेता इस बात को लेकर परेशान हैं कि कम से कम झारखंड के शहरी इलाकों को इन प्रावधानों से मुक्त कैसे कराया जाए. किसी भी शहर का विकास रियल स्टेट सेक्टर के विकास पर निर्भर करता है और यह सेक्टर पूरी तरह निजी क्षेत्र से संचालित होता है. निवेश को आकर्षित करने में इस सेक्टर की प्रमुख भूमिका होती है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के विकास के दरवाजे बंद करने की जगह उसे यथासंभव खोल देना चाहते हैं. वे अपने वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि झारखंड के विकास के लिए चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं. हालांकि, एक नौकरशाह के हाथों बोतल से निकला हुआ यह जिन्न कितना उत्पात मचाएगा और झारखंड को किस दिशा की ओर ले जाएगा, कहना मुश्किल है. उल्लेखनीय है कि जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना की हज़ारों करोड़ की आवंटित राशि सीएनटी एक्ट और सीलिंग एक्ट के कारण नहीं उठायी जा पा रही थी. अब तीन प्रमुख शहरों से सीलिंग एक्ट हटाने के बाद कुछ उम्मीदें बंधी हैं लेकिन सीएनटी एक्ट का मामला अभी भी उलझा हुआ है. अर्जुन मुंडा का पूरा धन खरसावां उपचुनाव की ओर केंद्रित है. झामुमो भी अर्जुन मुंडा के विधायक बनने के बाद खाली होने वाले जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र पर नज़र टिकाए हुए है. लेकिन लगता नहीं है कि यह विवाद इतनी जल्दी थमेगा.

feedback@chauthiduniya.com

विजय हुंकार भरने को सेना तैयार

बेगूसराय ज़िले में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पूर्व के नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्य पार्षद पुष्पा शर्मा तथा उपमुख्य पार्षद जवाहर लाल भारद्वाज सहित कई दिग्गज वार्ड पार्षदों के द्वारा इस बार चुनाव न लड़ने तथा कई पंचायतों के नगर निगम में शामिल किए जाने के कारण मुखिया या मुखिया पति के चुनाव लड़ने से मुक़ाबला काफ़ी रोचक हो गया है. ज़िलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता के पालन की नसीहत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते पकड़े गए तो अंजाम बेहद बुरा होगा. बेगूसराय नगर निगम के सभी 45 वॉर्डों की स्थिति पर अगर नज़र डाली जाऐ तो यह स्पष्ट दिखेगा कि महिला प्रत्याशी पुरूष प्रत्याशियों पर बेहद भारी पड़ रही हैं. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वॉर्ड नंबर-1 में अवधेश कुमार देव, उपेंद्र चौधरी, किशोर कुमार पासवान, जितेंद्र मोची, प्रदीप राम, बंगाली पासवान, राम सकल पासवान, राजीव कुमार देव तथा रूशो सदा सहित कुल 17 उम्मीदवार भाग्य आज़मा रहे हैं. अनारक्षित वॉर्ड 2 से अनीता सिन्हा, कुंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पूनम सिन्हा, रामविलास सिंह सहित कुल 17 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में तलवार भांजने को तैयार हैं. पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित वॉर्ड नंबर 3 से गुलशन ख़ातून, फूल कुमारी देवी, रंजू देवी तथा रिंकी देवी एक दूसरे से गुत्थमगुत्था करने के लिए तैयार बैठी हैं. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वॉर्ड नंबर 6 से कृष्णदेव प्रसाद दास, गणेश पासवान, प्रतिभा देवी, मनोज पासवान सहित आठ प्रत्याशियों के बीच घमासान मचा हुआ है. अनारक्षित वॉर्ड 7 से अमरेंद्र कुमार सिंह, रामसागर चौधरी, पंकज कुमार सिंह, गुलशन ख़ातून सहित कुल 30 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है. महिला के लिए आरक्षित वॉर्ड नंबर 32 से सुनीता सोनी, शिवारानी अग्रवाल, सारिका भास्कर, किरण वर्मा सहित नौ उम्मीदवार तो भाग्य आज़मा रही हैं लेकिन मतदाताओं का कहना है कि स्वर्ण व्यवसायी विनोद कुमार सोनी की धर्मपत्नी सुनीता सोनी के जीतने की संभावना सबसे अधिक इसलिए है कि किसी भी पद पर न होने के बावजूद सोनी ने ग़रीबों के हक़ के लिए सदैव न केवल आवाज़ बुलंद की बल्कि ग़रीबों के सुख-दुख में कोई कमी नहीं छोड़ी. मतदाताओं के अनुरोध पर चुनावी अखाड़े में कूदी सुनीता का न केवल वॉर्ड पार्षद बनना तय है, बल्कि मेयर बनाने के लिए कई जीत के दावेदार प्रत्याशी कमर कस चुके हैं. इसी तरह वॉर्ड नंबर 33 से अनिता देवी, प्रकाश कुमार सिन्हा, राकेश कुमार चौधरी सहित चार, वॉर्ड नंबर 34 से ग्यारह, वॉर्ड नंबर 35 से आठ, वॉर्ड नंबर 36 से नौ, वॉर्ड नंबर 37 से बारह, वॉर्ड नंबर 38 से चौदह, वार्ड नंबर 39 से पांच, वॉर्ड नंबर 40 से छह, वॉर्ड नंबर 41 से 17, वार्ड नम्बर 42 से चौदह, वॉर्ड नंबर 43 से 17, वॉर्ड नबर 44 से ग्यारह तथा वॉर्ड नंबर 45 से नौ उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं. इस तरह लगभग सभी वॉर्डों के प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोंकने के लिए अपनी-अपनी सेना के साथ तैयार हैं.

बेगूसराय नगर निगम चुनाव

सारिका भास्कर, वीणा सिंह, अनीता राय, अर्चना कुमारी, बबन सिंह, एमडी मुख्तार, गौतम राम, आलोक कुमार अग्रवाल

राजेश सिन्हा/ नंदकिशोर दास
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

हर बच्चे की एक लिखावट

[illegible]

व्यवहार न्यायालय स्थापना की मांग

[illegible]

अधिकारियों पर गिरेगी गाज

[illegible]

सरकारी वाहनों से अधिकारियों की सैर

[illegible] महनार आना-जाना करते हैं. विधुत विभाग के अभियंता, आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर इत्यादि पटना से ही आना-जाना करते हैं, जबकि नियमानुसार मुख्यालय के आठ किलोमीटर के अंदर ही आवास रखना होता है और 24 घंटा मुख्यालय में रहना होता है. यहां के बीडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, सीओ, डीसीएलआर और पुलिस निरीक्षक महनार में ही आवास लेकर रहते हैं. *–अंजुम परवेज़*

धूमधाम से मनाते हैं नेता जी की जयंती

पूर्णिया में नेताजी की जयंती नेताजी विचार मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थानीय विवेकानन्द कॉलोनी स्थित नेताजी चौक पर प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है. हरेक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी की जयंती दिलीप कुमार दास की अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा प्रत्याशी अमित सरकार थे एवं सचिव सूमोल सिंह थे. झंडा तोलन हरि प्रसाद दास जी ने किया. वक्ताओं ने नेताजी की 114 वीं जयन्ती के अवसर पर 64 वर्ष की आज़ादी के बाद आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, वंशवाद का देश से ख़ात्मा करने के लिए वर्तमान प्रासंगिक दौड़ में सुभाषवाद लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया. विशेष चर्चा में कामरेड अमित सरकार ने मूर्ति लगाने की इच्छा व्यक्त की तथा उन्होंने एक राष्ट्र नेता जी के नाम से बनाने की राय दी. इस अवसर पर इंदेश्वरी प्रसाद सिंह, फणी भूषण चौधरी, रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, दीपनारायण यादव अधिवक्ता समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे.

प्राक्कलन बोर्ड से मनरेगा की हक़ीक़त

सरकार ग़रीब ग्रामीण जनता के दु:ख दर्द दूर करने के लिए चाहे कितनी भी योजनाएं चला लें, लेकिन पूर्णिया पूर्व प्रखंड की हंसदा पंचायत में मनरेगा के तहत किए जा रहे सड़क के जीर्णोद्धार की हक़ीक़त प्राक्कलन बोर्ड से ही लग जाएगी. प्राक्कलन बोर्ड में योजना संख्या 4/10-11 उल्लेखित है, लेकिन प्राक्कलित राशि का उल्लेख नहीं है. कार्य प्रारंभ की तिथि 05/09/2010 दर्शाई गई है, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि का उल्लेख नहीं है. मुखिया जितेंद्र उरांव द्वारा अनुशंसित हंसदा पीच सड़क से मध्य विद्यालय होते हुए लगनझड़ी तक जीर्णोद्धार होने वाली इस सड़क का अभिकर्ता रोज़गार सेवक मृत्युंजय सिन्हा है.

सरकारी राजस्व वसूली में पूर्णिया डी.टी. ओ. अव्वल

बिहार सुशासन की सरकार में जहां आम लोगों की धारणा बेलगाम अफसरशाही की तरफ़ है, वहीं पूर्णिया के ज़िला परिवहन पदाधिकारी दरोगा यादव बीते साल से लेकर वर्तमान तक सरकारी राजस्व की वसूली व अपने काम-काज को लेकर पूरे सीमांचल में अव्वल नज़र आ रहे हैं. लोगों मे उनके कार्य की काफ़ी चर्चा है. पूर्णिया की जनता में उनकी छवि एक कर्मठ, लगनशील व ईमानदार पदाधिकारी की बन गई है. मालूम हो कि जब से वह ज़िले में पदास्थापित हुए हैं, उन्होंने सिर्फ स्थानीय जनता के कार्य को प्रथम वरीयता दी है.

बगलवाड़ी पुल डायवर्सन निर्माण ध्वस्त

किशनगंज जिला मुख्यालय से मस्तान चौक होते हुए कोचाधमन जाने वाली सड़क का पुल विगत साल ध्वस्त हो गया. राज्य सरकार ने निविदा निकालकर नए पुल का निर्माण चालू कराया साथ ही डायवर्सन निर्माण के लिए राशि अवांटित कराई. लेकिन गुणवत्ता विहीन डायवर्सन जल्द ही ध्वस्त हो गया, जिससे ज़िला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय व संबंधित पंचायत जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

धर्मेन्द्र जागरण ग्रुप
सनराईज मोबाईल स्टेशन रोड समस्तीपुर
जागरण सम्राट सरदार धर्मेन्द्र सिंह गिन्नी, एवं रॉकी सिंह की ओर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनायें
सम्पर्क
9334377567
9931455866

प्रभात तारा आवासीय विद्यालय
प्रभु ठाकुर मुहल्ला, वार्ड नं. - 4, रोसड़ा समस्तीपुर

समस्त छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों और चौथी दुनिया के पाठकों को विद्यालय परिवार की ओर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनायें
व्यवस्थापक
नये सत्र में नामांकन हेतु सम्पर्क करें
9934880781 9431898742 उमेश नारायण चौधरी

महेश मोदी का जवाब था कि जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मेरा भाई उप मुख्यमंत्री है.मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है.

राष्ट्रकवि दिनकर के मकान पर ज़बरन क़ब्ज़ा

फोटो-सुनील मल्होत्रा

राजेश एस. कुमार

मेरा भाई उप मुख्यमंत्री है और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. यह धमकी है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के भाई महेश मोदी की. इस धमकी से एक बार फिर साबित हो गया है कि हमारे देश में महापुरुषों की क्या हैसियत रह गई है. हालत यह है कि अब उनके मकानों पर भी क़ब्ज़ा किया जा रहा है. ताज़ा मामला, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का है. पटना स्थित उनके घर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के भाई महेश मोदी ने क़ब्ज़ा कर रखा है. न सिर्फ़ क़ब्ज़ा कर रखा है, बल्कि अपने भाई के मंत्री पद के ज़ोर पर उनको घर से निकालने की धमकी भी दी है.

दरअसल, पटना के राष्ट्रकवि दिनकर गोलंबर से सटे आर्य कुमार रोड पर स्थित दिनकर भवन है. यह भवन सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का है. कुछ साल पहले दिनकर जी की विधवा पुत्रवधू हेमंत देवी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री के भाई महेश मोदी को भवन परिसर में स्थित एकमात्र दुकान किराए पर दी थी. इस दुकान को तीन साल के इक़रार नामे पर किराए पर दिया गया था. जब 30 अप्रैल 2010 को यह इक़रारनामा ख़त्म हो गया तो महेश मोदी को दुकान खाली करने के लिए कहा गया. महेश मोदी ने दुकान खाली करना तो दूर उलटा घरवालों को धमकाना शुरू कर दिया. जब मामले की शिकायत करने की बात कही गई तो ऐसे में महेश मोदी का जवाब था कि जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मेरा भाई उप मुख्यमंत्री है. मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. बार-बार दुकान खाली करने का आग्रह करने पर उप मुख्यमंत्री के लाडले महेश ने यह तक कह डाला कि दुकान के साथ-साथ एक महीने के अंदर पूरे मकान पर क़ब्ज़ा कर लेंगे. चौथी दुनिया से जब इस संबंध में दिनकर जी के पविार से बात की तो कई बातें सामने आईं. दिनकर जी के पौत्र अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग जाकर नीतीश कुमार से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. इसके अलावा उन्होंने इस धमकी की लिखित जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार के सभी राजनीतिक दलों के पास भेजी है. लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है. इसलिए उन्होंने राजघाट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठने का फ़ैसला लिया. जब हमने उनसे पूछा कि अगर धरने के बाद भी काई बात नहीं बनी तो क्या करेंगे? इस पर अरविंद कुमार का कहना था हमसे जो बन पड़ा, हमने किया. अगर फिर भी हमें मदद नहीं मिली तो हम सीधे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौपेंगे.

हालांकि, यहां पर बात सिर्फ़ अवैध क़ब्ज़े की नहीं है, बात है देश की उस महान कवि के अपमान की, जिसने न सिर्फ़ अपनी लेखनी से देश को कई कालजयी रचनाएं दी हैं, बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है. इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जिस आदमी ने देश को आज़ाद कराया, आज उसी का मकान उसके अपने लोगों ने ही क़ब्ज़ा लिया है. यह सिर्फ़ दुर्भाग्य ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान है और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. अपनी पीड़ा का अंत न होते देख आख़िर दिनकर जी के परिवार ने पिछले दिनों नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के सामने शांतिपूर्ण धरना दिया. इस धरने में दिनकर जी की के परिवार के अलावा राम विलास पासवान भी विरोध करते दिखे. सभी ने इस घटना की निंदा करते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई की मांग की. अब इस पर कितनी कार्रवाई होती है यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा पर इतना तो तय है कि दिनकर जी का जो अपमान होना था वह हो ही गया. यह शांतिपूर्ण धरना अपनी ख़ामोशी के पीछे कई सवाल छोड़ गया. वो सवाल जिनके जवाब न तो नीतीश के पास हैं और न ही सुशील मोदी के पास. सवाल उस पीढ़ी से भी है जो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हुए बड़ी हुई है. क्या इन सबका दिनकर जी के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है. क्या आज मंत्रियों के रिश्तेदार महान कवि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? अगर हमारे दिल में देश के महापुरुषों के लिए इतनी भी इज़्ज़त नहीं बची है तो आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला कल कैसा होगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त
हम निम्नलिखित में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं:
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी
मास्टर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक*
मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी*
एम. एड. (स्पेशल एजुकेशन)*
स्नातक स्तरीय पाठ्क्रम
बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन)
बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ रेडियोइमेजिंग टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी
डिप्लोमा पाठ्यक्रम
डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी
डिपलोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट
डिप्लोमा इन ओ.टी.असिस्टेन्ट
डिप्लोमा इन इ. सी. जी.
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसींग
डी.पी.टी./डी.ओ.टी. के लिये १ वर्षीय अव्रीग्ड डिग्री इन
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, www.iiher.ac.in

Anil Sulabh
Director-in-Chief

Grand opening with new theme
" EMPOWERMENT THROUGH EDUCATION"
TECHNO MISSION SCHOOL
South-West Corner of Patel Maidan, (Near Law College)
Kashipur, Samastipur- 848101, e-mail : technomission.principal@gmail.com
Run & Managed by : Apurva Welfare Society, Samastipur

Registration Form & Prospectus available at School Counter between 8.00 AM to 4.00 PM
Registration for admission from Kg to Class IX under Session April 2011 to March 2012 is going on
Unique Features
- Located in the heart of town.
- Built up with well-ventilated & spacious rooms.
- Spread over Free & Open Areas with Gorgeous playground.
- Easily accessible & Congestion - free
- English Medium, Co-educational, C.B.S.E. Curriculum (KG to IX)
- Special Emphasis on Co-Curricular activities.
- Well-skilled & devoted teachers.
- Learning through activities.
- Conveyance facilities on the major routes.

Applications are invited for the following posts
Vacancy
Principal : P.G.+B.Ed having ten years teaching experience and five years administrative experience in a recognised institution, **Salary**- 8500-12500 + DA and other allowances/.
P.G.T. : P.G. in concerned subject + B.Ed having five years teaching experience in a recognised institution. **Pay Scale** - 6500-10500 + DA and other allowances .
T.G.T. : Graduate in concerned Subject+ B.Ed having three years teaching experience in a recognised institution. **Pay scale** : 5500-8500+DA and other allowances.
P.R.T. : Graduate in concerned subject +B.T. having three years teaching experience in a recognised institution. **Pay Scale** - 4500-6500+DA and other allowances.
Receptionist Cum Counter Assistnat : Graduate in any discipline with good communication skill in english, Female candidate will be preferred.
Applications are also invited for yoga teacher, music teacher, physical training instructor, librarian, Security guard (ex-Armyman) (Salary as per CBSE norms)
Interested candidates should apply to The Manager before 20th February 2011 at the school address

Mr A.K. Lal
Chairman
Good Wishes to Guardians, Students, All Indian nationals and well wishers on the occasion of Basant Panchami

Mr M.K. Karna
Manager
CONTACT : 9431245057, 9204068555, 9934304741, 9304051574

चौथी दुनिया

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

दिल्ली, 14 फरवरी–20 फरवरी 2011

www.chauthiduniya.com

एक और किसान आंदोलन

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

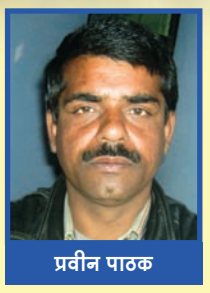

प्रवीन पाठक

आंदोलन में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वे मौक़ा पड़ने पर स्वयं मोर्चा भी संभाल रही हैं. गांव-गांव चल रही बैठकों से यही आवाज़ निकल कर आ रही है कि लोग किसी भी हालत में अपनी ज़मीन अधिग्रहीत नहीं होने देंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है.

फ़िरोज़ाबाद रोड स्थित वायुसेना कैंप के निकट वायुसेना की यूनिट खोलने के लिए टूंडला ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों पचोखरा, देवखेड़ा, छिकाऊ, हिम्मतपुर और गढ़ी हरराय की 1785 एकड़ यानी 10 हज़ार बीघा ज़मीन अधिग्रहीत की जाएगी. इन पंचायतों के अंतर्गत 29 गांव आते हैं, जिनकी कुल आबादी 85 हज़ार है. सबसे अधिक पचोखरा पंचायत प्रभावित होगी, जिसकी 1475 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहीत होगी. बाक़ी चार पंचायतों से 60-60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है. इस ख़बर से क्षेत्र के किसानों में खलबली मच गई है, लेकिन वे संगठित हैं, उनका कहना है कि वे अपनी जान दे देंगे, पर भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे.

क्षेत्र की पूरी भूमि तीन फ़सली है और यहां मुख्य रूप से आलू की खेती होती है. यहां की भूमि को चकबंदी विभाग ने ए ग्रेड दे रखा है. यही कारण है कि किसान अपनी उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण की आशंका के मद्देनज़र संगठित हैं. किसानों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, रक्षा सचिव, वायुसेना अध्यक्ष, विंग कमांडर एयरफोर्स स्टेशन आगरा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और ज़िलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद को ज्ञापन भेजकर भूमि अधिग्रहण न करने की गुहार लगाई है. अधिग्रहण की ख़बर से गांव इमलिया के 66 वर्षीय पन्नालाल कश्यप की हृदयगति रुक जाने से मौत हो गई. वह बेचैन थे कि पुरखों की जायदाद क्या यूं ही छिन्न-भिन्न हो जाएगी. परिवार के पालन-पोषण का जरिया क्या जड़ से समाप्त हो जाएगा. इसी प्रकार 8 अगस्त, 2010 को गांव बुर्ज भजन में किसानों की सभा हो रही थी, तभी 70 वर्षीय किसान गीतम सिंह फांसी का फंदा डालकर एक पेड़ पर झूल गए. किसानों ने तुरंत उन्हें उतार कर अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचा ली. बाद में मालूम हुआ कि गीतम सिंह ने भूमि अधिग्रहण की आशंका से पिछले चार-पांच दिनों से खाना-पीना तक छोड़ रखा था.

आंदोलन में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वे मौक़ा पड़ने पर स्वयं मोर्चा भी संभाल रही हैं. गांव बुर्ज भजन में भूमि अधिग्रहण के विरोध में आयोजित सभा में एक महिला किसान किरन देवी ने कहा कि यदि ज़मीन चली गई तो बच्चे भूखे मर जाएंगे. वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगी और यदि सरकार ने जबरदस्ती की तो वह परिवार सहित आत्मदाह कर लेगी. आत्मदाह करने की धमकी कई किसानों ने दे रखी है. गांव-गांव चल रही बैठकों से यही आवाज़ निकल कर आ रही है कि लोग किसी भी हालत में अपनी ज़मीन अधिग्रहीत नहीं होने देंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है. वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा. प्रशासन की चुप्पी किसानों को अंदरखाने बहुत डरा रही है. लोगों को लगता है कि शासन राष्ट्रहित का तर्क देकर चिन्हित भूमि को अधिग्रहीत करने का आदेश न दे दे और प्रशासन लोगों को उनकी ज़मीन से बेदख़ल करने की कार्रवाई न शुरू कर दे. पचोखरा बेल्ट के गांवों में गली से लेकर चौपाल तक हर आदमी आशंकित है. किसी को अपनी ज़मीन चले जाने की आशंका है तो किसी को मकान, दुकान और रोजगार का साधन.

कुछ लोग किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए यह भी कह रहे हैं कि सरकार ज़मीन मुफ्त तो लेगी नहीं, वह अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का उचित मुआवज़ा देगी. फिर क्षेत्र के लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतनी हाय-तोबा क्यों कर रहे हैं? किसान वह पैसा ख़र्च करके कहीं और बस सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई लोकतांत्रिक सरकार बसे-बसाए मकान-दुकान ध्वस्त करके लोगों को निर्दयता से निर्वासित कर सकती है, जबकि उसके पास अन्य सस्ते और अच्छे विकल्प मौजूद हों? सरकार भूमि का मुआवज़ा तो दे देगी एक निर्धारित दर से, लेकिन क्या उस मुआवज़े से भूमि-भवनों की क्षतिपूर्ति हो जाएगी? क्या भूमि-भवन बनाने में मात्र धन ही लगता है? सही बात तो यह है कि किसी भी भूमि-भवन में व्यक्ति-परिवार पीढ़ियों का वर्षों का त्याग, तपस्या, बुद्धि, कौशल, भावनाओं एवं संवेदनाओं का समावेश होता है, जिसे धन से नहीं मापा जा सकता. पुनर्वासित होने में बहुत कुछ टूटता-बिखरता है, जिसे मुआवज़े से पूरित नहीं किया जा सकता. मुख्य बात यह कि मुआवज़े की रक़म हाथ में आने पर किसान उसे ख़र्च करने की योजनाएं बनाने लगता है. नकद रक़म का अधिकांश हिस्सा वह सुख-सुविधाओं और अन्य कामों पर ख़र्च कर बैठता है. रीति-रिवाज निभाने में, जहां वह पहले किफ़ायत से काम लेता था, उदारता से ख़र्च करने लगता है. धीरे-धीरे रक़म ख़त्म या अल्प हो जाती है और वह खाली हाथ रह जाता है.

मान लीजिए, एक किसान के पास 25 बीघे ज़मीन है. वह तो मुआवज़े से किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपने को जैसे-तैसे पुनर्वासित कर लेगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने मात्र पचास-सौ गज में अपना मकान बना रखा है और उसमें ही एक दुकान करके वह अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, तो क्या वह मिलने वाले थोड़े मुआवज़े में अपने परिवार को पुनर्वासित करके बारोज़गार हो सकेगा? क्षेत्र में ऐसे हज़ारों किसान- मजदूर भी हैं, जिनके पास भूमि के नाम पर कुछ भी नहीं है. वे सिर्फ़ मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं. उन्हें मुआवज़े में क्या मिलेगा? निर्वासित तो वे भी होंगे! हम मानते हैं कि राष्ट्रहित का तर्क सर्वोपरि है, लेकिन किसी भी भूमि को चिन्हित करने से पूर्व यह तो सोचना ही चाहिए कि अन्य विकल्प क्या-क्या मौजूद हैं. कौन सा विकल्प पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम है और कौन सा विकल्प योजना को कार्यान्वित करने के लिए किफ़ायती रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

अधिग्रहण की चपेट में क्या-क्या आएगा

ग्राम पंचायत पचोखरा

एक इंटर कालेज, पांच उच्च प्राथमिक स्कूल, एक प्राचीन जैन मंदिर, पुलिस थाना, दूरसंचार केंद्र, पशु चिकित्सालय, बीज गोदाम, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, व्यवसायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पशु हाट, पेट्रोल पंप, दो अंबेडकर पार्क, तीन कोल्ड स्टोरेज, दो प्राचीन शिव मंदिर, पांच बारातघर, दस बाग-बगीचे, पानी की टंकी जो 36 गांवों को पेयजल मुहैय्या कराती है और एक मस्जिद.

ग्राम पंचायत देवखेड़ा

एक इंटर कालेज, चार उच्च प्राथमिक विद्यालय, पांच प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, दो अंबेडकर भवन, एक मिलन केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, साधन सहकारी समिति का गोदाम, तीन प्राचीन मंदिर, पांच बाग-बगीचे आम, कटहल एवं नींबू के और एक मस्जिद.

ग्राम पंचायत छिकाऊ

कुसुमा देवी दीक्षित महाविद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीन प्राथमिक विद्यालय, बीज गोदाम, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत घर.

ग्राम पंचायत हिम्मतपुर

आंशिक भूमि और भवन.

ग्राम पंचायत गढ़ी हरराय

एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और एक मंदिर. यह एक मोटा हिसाब है प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का. इसके अलावा लगभग दस-बारह हजार रिहायशी भवन, जो एक मंजिल से लेकर तीन मंजिल तक हैं.

क्षेत्रीय लोगों ने सुझाए विकल्प

- चिन्हित भूमि से 7 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पहले बड़ी मात्रा में बीहड़ी जमीन है. यह भूमि वायुसेना अपनी यूनिट बनाने के लिए विकसित करे तो इससे पर्यावरण को लाभ होगा.
- जनपद फिरोजाबाद की सीमा पर स्थित जलेसर, जनपद एटा के ग्राम जरानीकलां के पास से जनपद मैनपुरी तक ऊसर-बंजर भूमि को अधिग्रहीत करना उचित रहेगा और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी भी.
- इसी क्षेत्र के पश्चिम में लगभग पांच किलामीटर की दूरी पर एत्मादपुर तहसील जनपद आगरा के पास हजारों एकड़ ऊसर-बंजर भूमि पड़ी है.

मेरे संज्ञान में ऐसी कोई समस्या नहीं: राकेश

टूंडला के विधायक राकेश बाबू को जब बताया गया कि वायुसेना की यूनिट खोले जाने के लिए पचोखरा की 1785 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किए जाने की आशंका से क्षेत्र के किसान आंदोलित हैं. आपको इस क्षेत्र की जनता ने अपना विधायक चुना है, इसलिए आप चिन्हित भूमि बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर उनका जवाब चकित कर देने वाला था. उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई. अगर आएगी तो मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करूंगा और समुचित कदम उठाऊंगा.

मैं बेटों को धरती मां से अलग नहीं होने दूंगा: राज बब्बर

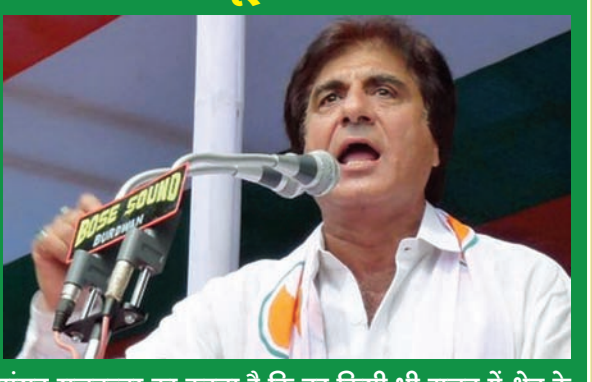

सांसद राजबब्बर का कहना है कि वह किसी भी हालत में क्षेत्र के बेटों को उनकी धरती मां से अलग नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह रक्षामंत्री ए के एंटोनी से मिल भी चुके हैं. रक्षामंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वायुसेना की यूनिट के लिए किसी अन्य जगह पर सर्वे कराया जाएगा.

बरेली के किले में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें रुहेलों के समय की कई दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है. इस किले का निर्माण रुहेलखंड में प्रथम जंग-ए-आज़ादी का आगाज़ करने वाले रुहेलों ने कराया था.

पथराव-फायरिंग में पुलिसकर्मियों समेत पचास से ज़्यादा लोग घायल हो गए. यहां इकट्ठी भीड़ के आक्रामक तेवर को देखकर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा.

सार संक्षिप्त

हौसले और हुनर का कमाल

अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. इस बात का जीता जागता उदाहरण है हामिद हुसैन. ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी साख का झंडा गाड़ने वाली कंपनी टाटा मोटर्स के लिए बागपत के बसौद गांव के हामिद हुसैन मानो नई प्रेरणा और राह लेकर आए हैं. हवा से इंजन स्टार्ट करने का कारनामा दिखाने वाले हामिद को टाटा ने जांच का ऑफर दिया है. बहुत दिनों की बात नहीं है, जब टाटा ने पेट्रोलियम की बढ़ती क़ीमतों के मद्देनज़र पानी से कार चलाने की एक नई सोच सामने रखी. ऐसा लगता है हामिद ने भविष्य में पानी की किल्लत को भांपते हुए एक क़दम आगे जाकर हवा से इंजन चलाने का कारनामा कर दिखाया. पिछले दिनों हामिद ने जब यह कारनामा सार्वजनिक रूप से दिखाने का एलान किया तो कई लोगों को यक़ीन नहीं आया. लेकिन गत 2 जनवरी को बसौद में जब हामिद ने अपने दावे को हक़ीक़त की सरज़मीं पर अमलीजामा पहनाया तो लोग भौंचक्के रह गए. आम लोगों की छोड़िए अब टाटा ने हामिद के इस शानदार आविष्कार को हाथोंहाथ लिया और इस साधारण से अनपढ़ मोटर मैकेनिक को अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दे डाला. टाटा मोटर्स के चार इंजीनियर गत दिवस हामिद के बसौद स्थित उनके घर आए और उनके आविष्कार के बारे में बातचीत की. मेरठ की एनआईएफ स्वयंसेवी संस्था के साथ आए टाटा मोटर्स के इंजीनियरों की टीम ने इंजन चलने के बारे में गहनता से जानकारी ली. हामिद ने बताया कि उसने बीस साल की अथक मेहनत के बाद यह इंजन तैयार किया है. यह हवा से स्टार्ट होकर चल सकता है. टाटा की टीम केइंजीनियर राहुल मिश्रा ने बताया कि दुनिया में पानी से इंजन चलाने का पहला आविष्कार कोरिया केएक व्यक्ति ने किया था. जापान केएक व्यक्ति ने हवा से इंजन चलाया था, लेकिन हवा में कोई केमिकल मिला होने केकारण उसका प्रयास सफल नहीं हो सका था. हामिद दुनिया का तीसरा ऐसा व्यक्ति है, जिसने इस तरह का आविष्कार किया है. टीम के साथ आई मेरठ की एनआईएफ संस्था केसदस्य अक्षय सिंह ने बताया कि हामिद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा.

बढ़ता जा रहा है बीज घोटाले का मामला

लगता है बीज घोटाले का मामला अभी और तूल पकड़ेगा. मुरादाबाद मंडल में बीज उत्पादन कार्यक्रम केतहत हुए करोड़ों के बीज घोटाले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है. मामले की तहक़ीक़ात के लिए उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम केएमडी जल्द ही रामपुर आएंगे. फिलहाल उन्होंने रामपुर में बीज उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान पर रोक लगा दी है. सोमवार को कार्यालय खुलने के साथ ही मुरादाबाद केदलपतपुर और जेपीनगर केगजरौला बीज वितरण केंद्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय संचालकों ने घोटाले से संबंधित फाइलों को तलाशना शुरू किया. सूत्रों केअनुसार किसानों ने अपना हक़ मारे जाने की शिकायत लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम केएमडी से की और पूरे मामले की जांच की आग्रह किया. इसकेबाद एमडी ने मार्केटिंग हेड केमाध्यम से दैनिक जागरण केविभिन्न अंकों में छपी कतरनें फैक्स से लखनऊ मंगाईं. साथ ही, उन्होंने कई किसानों को कहा कि अगर ऐसा है तो यह गंभीर है और इस पूरे मामले को आकर वह ख़ुद देखेंगे. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा पंचवर्षिय योजना वर्ष 2008-09 केतहत संभल और बहजोई के46 ऐसे किसानों का चयन किया जो वास्तव में हैं ही नहीं. मंडलायुक्त द्वारा कराई गई जांच में यह ख़ुलासा हो चुका है. इसकी सुचना मुख्य कार्यालय तक पहुंचा दी गई. रामपुर से प्राप्त ख़बर केअनुसार निगम केप्रबंधक निदेशक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीज उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान पर रोक लगा दी है. साथ ही फाइल तलब की है और बीज उत्पादकों केनाम भी मांगे हैं. निगम केपरियोजना अधिकारी पवन सिंह ने बताया कि बीज उत्पादकों को किए जाने वाले प्रोत्साहन राशि केभुगतान पर रोक लगा दी गई है. यहां भी जांच करा ली जाएगी. यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो संबंधित केख़िलाफ़ कार्रवाई होगी. बताया कि शिकायतकर्ता पहले निगम में संविदा कर्मी था और संविदा समाप्त होने केबाद निगम का बीज उत्पादक बन गया, इसीलिए निगम केकर्मचारियों पर दबाव बनाना चाहता है.

गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी

महानगर केरसोई गैस एजेंसी संचालक फिर मनमानी पर उतर आए हैं. 15 दिन पहले बुक कराए गए सिलेंडर भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे हैं. ऐसी शिकायतें डीएस-ओ दफ्तर में खुले कंट्रोल रूम में दर्ज कराई गई हैं. बता दें कि महानगर में रसोई गैस वितरण का बुरा हाल है. न फोन पर बुकिंग होती है ना ही होम डिलीवरी की जाती है. आम उपभोक्ता दौड़ लगाकर एजेंसी केदफ्तर में गैस बुक कराने जाते हैं, फिर सिलेंडर केगैस गोदाम पर लाइन लगाते हैं, जहां से अक्सर बैरंग लौटना पड़ता है. उधर कालाबाजारी केजरिए सिलेंडर की मोटी कीमत देने वालों केपास घर बैठे गैस पहुंचाई जाती है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का दावा है कि वे हफ्ते की बुकिंग में रसोई गैस मुहैया करा रहे हैं. उधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन केउपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं, उन्हें बुकिंग केमहीने बाद भी गैस नहीं मिल रही है. डीएसओ ऑफिस में खुले कंट्रोल रूम में उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज़ कराई है कि 11 जनवरी को बुक कराने केबाद सिलेंडर नहीं मिल रहा है. इस मामले में ज़िलाआपूर्ति अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि गैस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की गई है. उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी. रसोई गैस उपभोक्ता इस मुद्दे को कुछ सियासी नेताओं की मदद से मुख्यमंत्री केसामने उठाने की तैयारी में जुट गए हैं. इसकेलिए फोन कॉल का रिकार्ड, अख़बारों की कतरन आदि जुटाई जा रही है. उपभोक्ताओं का कहना है कि बेलगाम रसोई गैस एजेंसियों पर स्थानीय प्रशासन का कोई काबू नहीं रह गया है. यह बात किसी भी विधि से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी.

सेना ने संवारा किला

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम केप्रतीक बरेली किले को सेना ने संवारा है. ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और संजोने केलिए सेना की यूबी एरिया सिग्नल रेजीमेंट ने इस किले का पुन: निर्माण कराया है. सही मायने में पुराने स्वरूप में ही किले का पुन: उद्धार किया गया है. इतना ही नहीं, किले में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें रुहेलों केसमय की कई दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है. बता दें कि इस बरेली किले का निर्माण रुहेलखंड में प्रथम जंग-ए-आजादी का आगाज़ करने वाले रुहेलों ने कराया था. 1857 की जंग-ए-आजादी केमहानायक खान बहादुर ख़ान को गिरफ्तार करने केबाद अंग्रेजों ने इसी किले में कैद किया था. यहीं से उन्हें 24 मार्च 1860 को पुरानी कोतवाली ले जाकर फांसी दी गई थी. जीर्णशीर्ण हो चुके इस किले को सेना ने संवारने का बीड़ा उठाया. उत्तर भारत एरिया केजीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एसपी तनवर केदिशा-निर्देशन में यूबी एरिया सिग्नल रेजीमेंट केकर्नल राजीव कृष्ण ने लंबे प्रवास और कड़ी मेहनत से इसका पुन: उद्धार किया. वह बताते हैं कि इस किले में म्यूजियम का निर्माण कराकर उसमें रुहेलों केसमय की वस्तुओं का संग्रह किया गया है. इसके लिए काफी मशक्क़त करनी पड़ी. लेकिन यह काम कर्नल (रिटायर्ड) राजीव रावत ने आसान कर दिया. वस्तुओं केसंग्रह में उन्होंने काफी योगदान दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कांशीराम नगर ड्रग्स की चपेट में

एटा ज़िले के युवा नशे की गिरफ्त में हैं. एटा और कांशीराम नगर के शहरी और कस्बाई इलाक़ों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाक़ों में भी ड्रग्स का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि चहुंओर नशेड़ी झूमते नज़र आते हैं. सोरों स्थित गंगा तट से लेकर अलीगंज के नया गांव तक ड्रग तस्करों का जाल बिछा है. बड़े तस्करों को सफ़ेदपोशों का संरक्षण मिला है. लिहाज़ा इनके आगे पुलिस भी बौनी है. पुलिस एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ़ इन्हीं छोटी इकाई के लोगों को जेल भेज पाती है, जो अपने नशे की लत पूरी करने के लिए इन मादक पदार्थों को अपने जैसे नशेड़ियों को बेच रहे हैं.

मादक पदार्थों की तस्करी के तार यूं तो मध्य प्रदेश से जुड़े है लेकिन फिलहाल कांशीराम नगर के समीपवर्ती बदायूं ज़िले से तस्करी कर मादक पदार्थ इन दोनों ज़िलों में लाए जा रहे हैं. मध्यप्रदेश के उज्जैन, इंदौर और उत्तर-प्रदेश के बदायूं-बरेली के ग्रामीण इलाक़ों में बड़ी संख्या में अफ़ीम की खेती होती है. अफ़ीम से ही स्मैक हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं. इन्हीं इलाक़ों से तस्करी के जरिए नशीले पदार्थों की आपूर्ति एटा और कांशीराम नगर के शहर और कस्बाई इलाकों में होती है. इन दिनों मादक पदार्थों की सबसे बड़ी मंडी कासगंज बनी हुई है.

एटा शहर मुख्यालय स्थित करबला वाली गली भी मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख अड्डा है. अलीगंज, जैथरा, जलेसर, अवागढ़, सिढ़पुरा, सोरों, सहावर इत्यादि समेत विभिन्न इलाक़ों में घूमते नशेड़ी इस बात की गवाही देते हैं कि नशे का मैराथन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसा नहीं है कि नशेड़ियों पर पुलिस का अंकुश नहीं हैं. समय-समय पर इनके विरुद्ध अभियान तो चलाया जाता है पर पुलिस के इस अभियान में सिर्फ़ छुटभइए विक्रेताओं पर ही गाज गिरती है. आंकड़े गवाह हैं, बीते एक दशक में अपवाद स्वरूप आधा दर्जन ज़िले स्तर के सप्लायरों को छोड़ दिया जाए तो किसी बड़े तस्कर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है. दरअसल वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाती. बड़े माफ़िया बीच में ही अपने किसी गुर्गे को फंसवा कर साफ़ बच जाते हैं.

स्मैक का प्रचलन अपराध बाहुल्य ज़िलों में पिछले एक दशक से ज्यादा बढ़ा है. नौजवान पीढ़ी सेक्स क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करती है और फिर इस नशे की गिरफ्त में वह इस कदर जकड़ जाती है कि यह नशा इसकी मजबूरी बन जाता है. स्मैक का सबसे ज़्यादा प्रचलन एटा शहर मुख्यालय के अलावा सोरों और कांशीराम नगर में है. सोरों और कासगंज में तो पांच दर्जन से ज़्यादा नशे के आदी युवक मौत के आगोश में भी समा चुके हैं. बावजूद इसके नशेड़ियों की संख्या में कमी नहीं बल्कि इज़ाफ़ा हो रहा है.

स्मैक की छोटी-सी पुड़िया की क़ीमत पचास रुपए है. आर्थिक रूप से कमजोर तबके के नशेड़ी सिर्फ़ इसके धुएं से ही अपनी लत पूरी कर रहे हैं. यही वजह है कि ड्रग्स की चपेट में आई युवा पीढ़ी अपनी लत को पूरी करने के लिए अपराधों की ओर उन्मुख हो रही है. जिस समय इस नशे के लती को तलब लगती है तो उसका शरीर ऐंठने लगता है इस समय वह अपनी लत पूरी करने के लिए कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है. अतीत इस बात का गवाह है कि लूट और चोरी की ही नहीं बल्कि नशेड़ियों ने हत्या जैसी संगीन घटनाओं को भी अंजाम दिया है.

ऐसा नहीं है कि इस सच से पुलिस वाकिफ़ नहीं है. हक़ीक़त वह भी जानती है पर नशेड़ियों को गिरफ्तार करना भी पुलिस के लिए बवाल ए जान है. थाने की हवालात में अगर स्मैक नहीं पिलाई गई तो नशेड़ी पूरे थाने को ही सिर पर उठा लेते हैं. पुलिस की सभी पाबंदियां नशे की लत छुड़ाने में बेअसर साबित हो रही हैं. चिंतनीय पहलू तो यह है कि 12 से 17 वर्ष के किशोरों का झुकाव भी अब ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है. सच्चाई तो यह है कि नशे के मैराथन को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा. ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए तभी निजात मिल सकती है.

संजय सब्बरवाल
feedback@chauthiduniya.com

स्मैक की छोटी-सी पुड़िया की क़ीमत पचास रुपए है. आर्थिक रूप से कमजोर तबके के नशेड़ी सिर्फ़ इसके धुएं से ही अपनी लत पूरी कर रहे हैं. यही वजह है कि ड्रग्स की चपेट में आई युवा पीढ़ी अपनी लत को पूरी करने के लिए अपराधों की ओर उन्मुख हो रही है.

पचास के दशक से शुरू हुआ दौर

एटा में नशे की लत का दौर तीर्थ नगरी सोरों में वर्ष 1950 से शुरू हुआ. थाने का रिकार्ड भी इस बात की गवाही देता है. 21 अगस्त 1951 को सोरों पुलिस ने कस्बे के सियाराम, शंकर, चंदा और मुरारी नामक तस्करों को गिरतार किया था. 1950 से 1975 तक मादक पदार्थों की बिक्री के जुर्म में 184 लोगों को गिरतार किया गया था. जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं; जिन्हें 1962 में तस्करी करते रंगेहाथ गिरतार किया गया है. इसके अलावा 1975 से 2000 तक 225 लोगों को गिरतार किया गया है. जबकि 2001 से अब तक पुलिस ने 275 से ज्यादा लोगों को गिरतार तो किया किन्तु वे तस्कर नहीं बल्कि मादक पदार्थ बेचने वाले थे.

अब बदलाव ज़रूरी है

हमारे देश में कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बाबा आदम के जमाने से चल रही हैं. वर्तमान में स्थितियां बदल चुकी हैं, इसके हिसाब से व्यवस्था में बदलाव होना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अब पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट को ही ले लीजिए.

भारतीय गणतंत्र को स्थापित हुए 61 साल हो रहे हैं, लेकिन अब भी अंग्रेजों के जमाने का पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट ही चल रहा है. समय के साथ इसमें ज़रूरी बदलाव न होने से तमाम दुश्वारियां सामने आती हैं. और तो और अधिकांश पुलिस उच्चाधिकारियों का अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार हर जगह अच्छा नहीं रहता. सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक भारत सिंह मानते हैं कि पुलिस पुराने जमाने में जी रही है. दूसरे देशों की पुलिस हमारी पुलिस से बहुत आगे है. मोहम्मदाबाद के रोहिला में रह रहे भारत सिंह से 1861 में बने पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट के संबंध में चर्चा हुई तो उन्होंने बदलते वक्त के साथ इसमें आ रही ख़ामियों को बख़ूबी रेखांकित किया. पूर्व आईजी कहते हैं कि पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार बहुत सख्त रहता है. आम आदमी ख़ाकी से डरता है. थानों में भले आदमियों ख़ास तौर से महिलाओं के बैठने की जगह नहीं है. क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि फरियाद लेकर गए पांच-दस लोगों के बैठने की व्यवस्था हो.

रिटायर्ड आईजी कहते हैं कि मामलों की विवेचना जल्द निपटनी चाहिए. पुलिस जांच अधिकारियों के पास प्राय: तमाम विवेचनाएं लंबित रहती हैं. दूसरे पुलिस में भर्ती का तरीक़ा प्रॉपर नहीं है. इसमें भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आती हैं. इस समय पुलिस परीक्षण में लेफ्ट-राइट (परेड) पर बहुत अधिक समय लगता है. इस समय में कटौती कर क़ानून की जानकारी देने के लिए किया जा सकता है. कई बार कांस्टेबिल को क़ानून की धाराओं की जानकारी नहीं रहती. वह कहते हैं कि कई बार आदमी को यह महसूस होता है कि पुलिस में भर्ती होकर उसने कोई बड़ी ग़लती की है. सिपाही छुट्टी मांगता है तो उसमें तमाम अड़चने आती हैं. ऐसे में उसके दिमाग़ में तमाम बातें आती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से ऐसे बात करनी चाहिए कि उन्हें मानसिक सांत्वना मिले. विदेशों में कांस्टेबिल जनरल तक से बात कर सकता है. अपने यहां सिपाही को डीआईजी से बात करने के लिए सोचना पड़ता है.

भारत सिंह सितंबर 1947 में कांस्टेबिल से पुलिस में भर्ती हुए. इसके बाद सीओ और एसपी बने. 1969 में वह महानिरीक्षक पद पर पहुंचे. शिमला समझौता के समय उन्हें विशेष ड्यूटी पर भेजा गया था. 1974 में वह सेवानिवृत्त हो गए. 8 फरवरी को 100 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे भारत सिंह सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हैं.

पुलिस के आंतरिक सिस्टम में सुधार होना ज़रूरी है. लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है. अगर सही समय पर बदलाव किए गए होते तो आज इनकी छवि कुछ और होती.

feedback@chauthiduniya.com

बरेली: शहर की हालत देख लोग हुए हैरान

बरेली शहर में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ. चार थानों में कर्फ्यू लगा. बरेली शहर के कोतवाली प्रेमनगर, किला और बारादरी क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था. यहां एक धार्मिक जुलूस निकालने से ठीक पहले दो समुदायों में जमकर पथराव और फायरिंग शुरू हो गया.

बिंदास शहर बरेली में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो वाकई बरेली शहर को शर्मशार करने वाला था. ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस शहर को राजा बॉस देव और बरल देव ने बसाया था. इस शहर को रुहिला सरदारों ने अपनी राजधानी बनाया था. पूरे देश को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, पर बरेली शहर को नबाब खानबहादुर खान और उनके मंत्री मुंशी शोभा राम ने 31 मई 1857 को ही आजाद घोषित कर दिया था. फिर बरेली के बाजार में झुमका गिरने से बरेली की मस्ती और भी बढ गई. बरेली के लोगों को अब तक मस्त स्वभाव और राष्ट्र भक्ति के लिए जाना जाता था. पर उसी बरेली शहर में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ. चार थानों में कर्फ्यू लगा. बरेली शहर के कोतवाली प्रेमनगर, किला और बारादरी क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था. यहां एक धार्मिक जुलूस निकालने से ठीक पहले दो समुदायों में जमकर पथराव और फायरिंग शुरू हो गया. कई दुकानें लूटी गई तो कई मकानें और दुकान आग के हवाले कर दी गईं. इसके अलावा पुलिस चौकी के पास धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई. भीड़ ने सरकारी-गैरसरकारी कई वाहनों को तोड़ फोड़ दिया. पथराव-फायरिंग में पुलिसकर्मियों समेत पचास से ज्यादा लोग घायल हो गए. यहां इकट्ठी भीड़के आक्रामक तेवर को देखकर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पडा. पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे. पर तब भी आक्रामक भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा. इस स्थिति को कंट्रोल करना जब पुलिस के लिए मुश्किल हो गया तो प्रशासन ने प्रेमनगर, किला और बारादरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया. इन तमाम घटनाओं से बरेली के आस पास के शहरों में रहकर जॉब कर रहे और पढाई कर रहें युवाओं के मन में अपने शहर के समाचार को टीवी या अखबारों में देखकर डर सा बैठ गया था कि न जाने आगे क्या होगा. जहां उनके माता पिता परेशान थे वहीं बच्चे भी अपने घरवालों को लेकर परेशान दिखें. खबरों को देखकर वो अचंभित थे कि यह उनका ही शहर है. आश्चर्य मिश्रित शब्दों में वो उनका कहना था कि बरेली के लोग कभी हिंसा और दंगा नहीं कर सकते. यहां तो विविध धर्मो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और भी कई धर्म के लोग आपस में प्यार के साथ रहते हैं.

प्रियंका प्रियम तिवारी
priyanka@chauthiduniya.com

सार संक्षिप्त

जापानी विशेषज्ञ सुझाएंगे पर्यावरण संवर्धन के उपाय

पर्यावरण संरक्षण के तकनीकी हस्तांतरण विषय पर जापान की संस्था आइसेट के सहयोग से विनरॉक इंटरनेशनल इंडिया द्वारा फ़िरोज़ाबाद में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में कांच की टैंक भट्ठियों में ऊर्जा संरक्षण और कार्बन तकनीकी के हस्तांतरण पर चर्चा की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्योगपति बालकृष्ण गुप्त ने विशेषज्ञों से आह्वान करते हुए कहा कि वह तकनीकी ज्ञान से फ़ीरोज़ाबाद की टैंक इकाइयों के लिए उपयुक्त तकनीक का प्रदर्शन करें. विनरॉक केमनीष सोनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग केअंतर्गत भारत की लघु और मध्यम इकाइयों के लिए इस तरह के कार्यक्रम फ़ीरोज़ाबाद सहित और शहरों में भी आयोजित किए गए है. विनरॉक के सलाहकार पीयूष शर्मा ने कहा कि प्रोजेक्ट टीम द्वारा औद्योगिक इकाइयों दौरा किया गया था, जिसमें चयनित इकाइयों को कार्यक्रम केअगले भाग में जापानी विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन कर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के उपाय सुझाए जाएंगे.

WINROCK INTERNATIONAL
Putting Ideas to Work

विकलांग बच्चों का शिक्षण की प्रशिक्षण लेंगे शिक्षक

विकलांग बच्चों को अलग से शिक्षा देने की जगह मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा नया प्रयास किया जा रहा है. इस प्रयास के तहत अब सभी प्राथमिक व उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को विकलांग छात्रों की देखभाल की ट्रेनिंग दी जाएगी. राज्य में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच प्रशिक्षण कार्य चलाया जाएगा. राज्य परियोजना निदेशक केआदेशानुसार 1,35,603 शिक्षिकाओं को इस प्रशिक्षण कार्य से जोड़ा जाएगा. इसके लिए राज्य में छह करोड़ 78 लाख 1500 रुपए का बजट रखा गया है. अभी तक विकलांग बच्चों की पढ़ाई व देखभाल आदि के लिए समेकित शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे थे. मेरठ में इस प्रशिक्षण कार्य के तहत 540 शिक्षकों को रखा गया है. इन शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दो लाख सत्तर हज़ार रुपए का बजट पास किया गया है. प्रत्येक बीआरसी में शिक्षकों को पांच दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस प्रशिक्षण कार्य के लिए एक बैच में 50 शिक्षकों को रखने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य महिला आयोग करेगा महिलाओं को सम्मानित

उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य महिला आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराने वाली महिलाओं को सम्मानित करने की योजना बनाई है. इसके तहत सभी ज़िलाधिकारियों को उनके ज़िले से कला, साहित्य, विरता, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और लड़कियों के नाम मांगे हैं. इन महिलाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

कंप्यूटर है पर शिक्षक नहीं

माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ के डीडीआर संतराम सोनी को माध्यमिक विद्यालयों केनिरीक्षण में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित मिली. माध्यमिक शिक्षा अभियान में उच्चीकृत हिसामपुर हाईस्कूल में दो शिक्षक ही मिले. संस्थानों में कंप्यूटर लैब स्थापित होने केबावजूद कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा का लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा. शासन ने डीडीआर उर्दू संतराम सोनी को फर्रुखाबाद व औरैया जिले केदस-दस माध्यमिक विद्यालयों केनिरीक्षण की जिम्मेदारी दी है. जीआईसी फतेहगढ़ में 50 कंप्यूटर लैब है, पर बीते वर्ष संबंधित फर्म से संविदा खत्म होने केकारण कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को देने की समस्या आ गई. सह जिला विद्यालय निरीक्षक व विद्यालय प्रधानाचार्य देवेंद्र स्वरूप सचान ने डीडीआर को बताया कि संविदा खत्म होने पर अब विद्यालय स्तर से कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है. जनता राष्ट्रीय फतेहगढ़, रस्तोगी इंटर कालेज, रामानंद बालक का निरीक्षण करने केबाद डीडीआर ने बताया कि कुछ विद्यालयों में सभी कंप्यूटर छात्रों को शिक्षा केलिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं. विद्यालय परिसर का रखरखाव व संसाधनों के समुचित उपयोग न होने केमामले पाए गए. सभी कालेजों में शिक्षकों की कमी मिली.

उत्तर प्रदेश का खतौली ब्लॉक सर्वाधिक साक्षर

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में खतौली ब्लाक ज़िले में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय व प्रदेश की साक्षरता दर से भी ज़्यादा है. ब्लाक में साक्षरों का प्रतिशत 66.30 है. साक्षर महिलाओं की संख्या भी अन्य ब्लॉक के मुक़ाबले ज़्यादा है. पढ़ाई के मामले में जहां उत्तर प्रदेश अन्य कई प्रदेशों से पिछड़ा है, वहीं खतौली ब्लॉक प्रदेश के आंकड़ों में सुधार की ओर बढ़ रहा है. बेसिक शिक्षा विभाग केआंकड़ों केअनुसार हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38 है और प्रदेश के सौ में से 57.36 लोग पढ़ लिखे हैं. मुजफ्फर नगर ज़िले के सौ में से 61.68 लोग पढ़े लिखे हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि ज़िले के सभी 14 ब्लॉक के मुक़ाबले खतौली में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है. ब्लॉक की साक्षरता दर 66.30 प्रतिशत है. सौ में से 80.50 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 50.50. ब्लॉक में 132 प्राथमिक विद्यालय व 59 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. इनमें क़रीब 16 हज़ार से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहें हैं.

मक्का के साथ उगेंगी और भी सब्जियां

किसान अब मक्के के खेत में धनिया, मेथी और मूली भी उगाएंगे. इस नई तकनीक में मक्के को फरवरी महिने तक बोया जाएगा. यह साढ़े तीन महीने में तैयार होने वाली यह फ़सल एक एकड़ में तीस से पैतीस क्विंटल के बीच उपज देती है. मक्का की सबसे ज़्यादा खेती कमालगंज, राजेपुर तथा नवाबगंज क्षेत्र में हौती है. कमालगंज क्षेत्र में फ़सल अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहले तैयार हो जाती है. मक्के के प्रति ज़िले के किसानों के बढ़ते रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने दोहरी फ़सल की तकनीक विकसित की है. वैज्ञानिकों का कहना है मक्के के साथ किसान मेड़ विधि से मूली, चुकंदर, धनिया और मेथी भी उगा सकते हैं. इसके बारे में किसानों कौ जागरूक किया जा रहा है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गांव गढ़िया, दहेलिया और जैतपुर के किसान मुनाफ़ा देख दोहरी फ़सल की खेती करने के लिए तैयार हैं. यहां के किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों को भरोसा दिलाया है कि वह दोहरी फ़सल से लाभ कमाएंगे. कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान खेतीबाड़ी से पहले कृषि वैज्ञानिकों से अवश्य सलाह लें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Romsons
Romsons Group of Industries
AGRA

एस.आर.हॉस्पीटल
लॉरीज कॉम्पलैक्स नामनेर रोड, आगरा
Ph.: 4025200, 4025201
Dr. Sudha Bansal
M.B.B.S. (Hons.) D.G.O., M.S. (Obs. & Gyn.)
SENIOR CONSULTANT
OBSTETRICIAN & GYNAECOLOGIST
DIRECTOR
100 Bedded Multi Speciality Hospital
Dr. Rajendra Bansal
M.B.B.S. (Hons.) M.D. (Med.) F.I.A.C.M., F.I.C.M.U.
SENIOR CONSULTANT PHYSICIAN
CARDIOLOGIST & ULTRASONOLOGIST
MANAGING DIRECTOR
लेप्रोस्कोपिक (दुरबीन विधि) सर्जरी, (पित्त की थैली एवं बच्चेदानी के आपरेशन) मेडिसन एवं स्त्रीरोग विभाग, दिमाग की चोट, हड्डी की चोट, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोसर्जरी, जनरल सर्जरी